



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23072020-220660  
CG-MH-E-23072020-220660

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/ आषाढ़ 31, 1942

No. 270]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASHADHA 31, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 26 जून 2020

**सं. टीएएमपी/11/2020-वीएसपीएल.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने 1 जून 2020 को हुई इस प्राधिकरण की बैठक में, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में ईक्यू-8 और ईक्यू-9 बर्थों में इसके द्वारा प्रहस्तिट पोतों के लिए अपने दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान किया था। तथापि, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए दरमान के साथ अधिसूचित करने वाले (स्पष्ट) आदेश में लगने वाले समय पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केवल संशोधित दरमानों को तत्काल अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, 1 जून 2020 को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान को 18 जून 2020 को राजपत्र सं. 212 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया था कि यह प्राधिकरण आने वाले समय में स्पष्ट आदेश अधिसूचित करेगा। तदनुसार, यह प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार वीएसपीएल से उसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान किए जाने से संबंधित स्पष्ट आदेश अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2020-वीएसपीएल

विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

**कोरम:**

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

## आदेश

(1 जून 2020 को पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में ईक्यू-8 और ईक्यू-9 में विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) द्वारा प्रहस्तित पोतों के लिए इसके एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए इसके ईमेल दिनांक 31 जनवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 द्वारा वीएसपीएल द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30 जनवरी 2020 से संबंधित है।

2.1. वीएसपीएल का मौजूदा एसओआर पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/19/2017-वीएसपीएल दिनांक 19 जनवरी 2018 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे 26 फरवरी 2018 को राजपत्र सं. 78 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 में, लागत विवरण में दर्शाये गए घाटे के आधार पर, तट प्रहस्तन प्रभार रु. 45 प्रति टन से बढ़ाकर रु. 65 प्रति टन (44 प्रतिशत वृद्धि), बीएमएचएस प्रभारों को रु. 150 प्रति टन से घटाकर रु. 140 प्रति टन (7 प्रतिशत वृद्धि) किया गया था, रेलवे साइडिंग प्रभारों को हटाया गया था, धूल निवारण प्रणाली प्रभार को रु. 1.50 प्रति टन से बढ़ाकर रु. 2.00 प्रति टन (33 प्रतिशत वृद्धि) किया गया था, घाटशुल्क प्रभारों में वीएसपीएल द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार 5 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच वृद्धि की गई थी और बर्थ किराया प्रभार में वृद्धि कर 0.0072 अ.डा. से 0.0083 अ.डा. (15 प्रतिशत वृद्धि) किया गया था।

2.2. तत्पश्चात्, इस प्राधिकरण ने वीएसपीएल द्वारा दाखिल किए गए समीक्षा आवेदन का निपटान करते हुए आदेश सं. टीएमपी/24/2018-वीएसपीएल दिनांक 03 अक्टूबर 2018 पारित किया था जिसे राजपत्र सं. 413 दिनांक 06 नवंबर 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश ने एसओआर की वैधता 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की थी। उक्त समीक्षा आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2018 में, बर्थ किराया प्रभार को संशोधित कर 0.0089 अ.डा. प्रति जीआरटी प्रति घंटा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद से लागू किया गया था।

3.1. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी (पीटी. IV) दिनांक 05 मार्च 2019 द्वारा सभी महापत्तन न्यासों में परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश जारी किए थे और पहले महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाता था, और इस प्राधिकरण को तदनुसार तत्काल प्रभाव से कार्य करने का निर्देश दिया था। महापत्तन न्यास में परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश और पहले 2005 प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित 07 मार्च 2019 को राजपत्र सं. 92 द्वारा भारत का राजपत्र असाधारण (भाग 3 खंड 4) में अधिसूचित किए गए थे। उसके बाद, प्रशुल्क नीति, 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों को 2005 प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन शासित बीओटी परिचालकों और महापत्तन न्यासों से परामर्श के बाद राजपत्र सं. 244 दिनांक 11 जुलाई 2019 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे।

3.2. प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 4.2 के अनुसार, प्रत्येक बीओटी परिचालक इसके एसओआर के कार्यान्वयन की संभावित तारीख अर्थात् 31 जनवरी 2020 से 60 दिन पहले प्रस्तावित एसओआर जमा करेगा। इस संबंध में, वीएसपीएल ने हमारे पत्र दिनांक 31 जनवरी 2020 द्वारा अनुरोध किया गया था कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को कार्यान्वित करने के लिए जारी किए गए वर्किंग दिशानिर्देशों के साथ पठित प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का अनुसरण करते हुए अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करें।

4.1. इस परिप्रेक्ष्य में, वीएसपीएल ने 01 अप्रैल 2020 से तीन वर्षों की अवधि के लिए वीपीटी में ईक्यू-8 और ईक्यू-9 के मामले में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए प्रशुल्क नीति, 2019 का अनुसरण करते हुए अपना प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी 2020 दाखिल किया था।

- (i). एसओआर हमारे वाणिज्यिक निर्णय और वीपीटी और विजाग में अन्य टर्मिनलों के दरमानों के आधार पर अधिकतम एआरआर से कम राजस्व के साथ तैयार किया गया है।
- (ii). ईक्यू 8 बर्थ के लिए अभियंत्रित कार्गो परिचालन के अधीन और ईक्यू 9 बर्थ के लिए गैर-अभियांत्रिक परिचालनों के अधीन अलग-अलग बर्थ किराया दरें प्रस्तावित की गई हैं।
- (iii). वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के अनुसार और वीपीटी तथा अन्य बर्थों के एसओआर पर विचार करते हुए, प्रशुल्क में वृद्धि प्रपत्र 5 में दिए गए ब्लोरे के अनुसार विभिन्न कार्गो संबंधित प्रभारों पर प्रस्तावित की गई है।

4.2. वीएसपीएल ने प्रपत्र-1 के अधीन एआरआर का विस्तृत परिकलन और प्रपत्र-4 में प्रस्तावित दर पर राजस्व अनुमानन भेजे हैं।

- (i). वीएसपीएल द्वारा प्रेषित एआरआर परिकलन की सार स्थिति नीचे तालिकाबद्ध की गई है:

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वाई1 (2016-17)	वाई2 (2017-18)	वाई3 (2018-19)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	11,438.25	13,641.12	14,794.00
(ii).	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)	3,124.96	2,511.19	2,187.39
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	14,563.21	16,152.31	16,981.39

क्र.सं.	विवरण	वाई1 (2016-17)	वाई2 (2017-18)	वाई3 (2018-19)
(2).	ऐसी मदों के मामले में समायोजन जहां आईएनडीएस (लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार) और आईजीएपी के अनुसार प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता हो			
(i).	मूल्यहास	152.03	150.85	143.33
(ii).	सूचीबद्ध की जाने वाली अन्य व्यय मदें, यदि कोई हों	(703.37)	(490.69)	(341.20)
	समायोजनों का जोड़ <b>2=(i)+(ii)</b>	<b>(551.34)</b>	<b>(339.84)</b>	<b>(197.87)</b>
(3).	समायोजन घटायें:			
(i).	पत्तन को भुगतान की गई वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	693.96	791.82	876.35
(ii).	ऋणों पर ब्याज	3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	अशोध और आशंकित ऋणों के लिए प्रावधान	8.22	80.62	31.03
(iv).	धीमे चलने वाली वस्तुसूची के लिए प्रावधान	-	-	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हों	-	-	-
	3 का जोड़ = <b>[3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]</b>	<b>3,777.37</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के अनुसार स्वीकार्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	520.00	593.00	656.00
(5).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय <b>(5=1+2-3)</b>	<b>10,754.50</b>	<b>13,046.88</b>	<b>14,366.92</b>
(6).	क्र.सं. 5 के औसत व्यय = $[वाई1+वाई2+वाई3]/3$	<b>12,722.77</b>		
(7).	नियोजित पूंजी			
	(i). बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथा वाई3 के 31 दिसंबर को सकल अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) (आईजीएपी के अनुसार)			34,749.18
	(ii). जोड़ें: बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथा वाई3 के 31 दिसंबर को प्रगतिधीन केपिटल वर्क (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			6.73
	(iii). जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्किंग केपिटल			2,398.28
	(क). वस्तुसूची			-
	(ख). विविध देनदार			-
	(ग). रोकड़			-
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़			-
	<b>(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)+(iii)]</b>			<b>37,154.20</b>
(8).	क्र.सं.7(iv) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ			5,944.67
(9).	31 मार्च वाई3 अथवा यथा लागू वाई3 के 31 दिसंबर को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) <b>[(6)+(8)]</b>			18,667.44

क्र.सं.	विवरण	वाई1 (2016-17)	वाई2 (2017-18)	वाई3 (2018-19)
(10).	उदाहरण के लिए वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन, यदि वाई वाई4 2019-20 हो, तो लागू डब्ल्यूपीआई 3.45 प्रतिशत है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर (9) x 1.0345) होगा।			19,311.47
(11).	ऊपर क्र.सं. 10 में यथा दिया गया अधिकतम सूचकांकित एआरआर			19,311.47
(12).	ऊपर क्र.सं. 11 पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित एसओआर पर राजस्व अनुमानन			17,263.00

(ii). वीएसपीएल ने वर्ष वाई1, वाई2 और वाई3 के दौरान बीओटी परिचालक द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात की औसत के लिए प्रपत्र 4 में प्रस्तावित प्रशुल्क एवं मौजूदा प्रशुल्क के लिए राजस्व अनुमानन की गणना भेजी है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर अनुमानित कुल राजस्व रु. 17,163/- लाख है।

4.3. वीएसपीएल ने प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रपत्र सं. 1, 2, 3, 4, 6ए, 6बी और 7 भी भेजा है।

4.4. वीएसपीएल ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रत्येक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ प्रस्तावित एसओआर ईमेल दिनांक 11 फरवरी 2020 द्वारा भेजी है।

4.5. वीएसपीएल ने नीचे दिए गए अनुसार अनुमानित एआरआर की पूर्ति के लिए वृद्धि/(कमी) का प्रस्ताव किया है:

विवरण	% वृद्धि/कमी	
	विदेशी	तटीय
बर्थ किराया प्रभार	11.24% तक	62.88% से 80%
घाटशुल्क प्रभार	0.33% से 90%	-53.95% से 166.67%
विलंबशुल्क प्रभार		यथास्थिति
स्टीवडोरिंग प्रभार	0% से 132.56%	-13.60% से 125%
तट प्रहस्तन प्रभार		24.62%
100 टन एचएमसी		यथास्थिति
गैन्ट्री अनलोडर किराये पर लेने के लिए प्रभार		हटाया गया है
रेलवे अनुरक्षण के लिए प्रभार और साइडिंग प्रभार		पुनः-शामिल
भंडारण प्रभार		33% से 50%
धूल निवारण प्रणाली प्रभार		50% से 100%
भारतोलन प्रभार		20% से 66.67%
बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए सामग्री प्रहस्तन प्रणाली		7.21%
तारपाउलिन कवरेज प्रभार		20%
विविध प्रभार		
आगंतुक/वाहन प्रवेश अनुज्ञापत्र		यथास्थिति
फोटोग्राफी		400%

5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सभी संलग्नकों (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों) के साथ दिनांक 31 जनवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 के प्रस्ताव की प्रति वीपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। हमें केवल मै. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से ही टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं जिसकी एक प्रति वीएसपीएल को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। वीएसपीएल ने अपना प्रतिसाद भेजा है।
6. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 26 फरवरी 2020 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। वीएसपीएल ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, वीएसपीएल, वीपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने अपने निवेदन रखे थे।
7. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, वीएसपीएल से हमारे पत्र दिनांक 3 मार्च 2020 द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ बिंदुओं पर मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण 10 मार्च 2020 तक भेजे जाएं। वीएसपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 12 मार्च 2020, अनुवर्ती ईमेल दिनांक 16 मार्च 2020 और 6 अप्रैल 2020 द्वारा अपना जवाब भेजा था। हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और वीएसपीएल द्वारा प्रेषित तदनुसंगी जवाब नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं—

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	वीएसपीएल द्वारा प्रेषित उत्तर			
1.	वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) (प्रपत्र-1):				
(i).	प्रपत्र-1, क्र.सं. 1, कुल व्यय: कुल व्यय आंकड़े वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों से मेल खाते हैं। तथापि, वैयक्तिक आंकड़े जैसे परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित) और वित्त एवं विविध व्यय लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों से मेल नहीं खाते हैं। वीएसपीएल लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार इन आंकड़ों पर विचार करे। यह उक्त वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों से वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए कुल व्यय में थोड़ा अंतर है जिसे ठीक किया जाए।	निम्नलिखित लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों और प्रशुल्क प्रपत्र सं. 1 के बीच मिलान है:			
		लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार	2016-17	2017-18	2018-19
		परिचालन व्यय	8,640.43	10,539.09	11,511.79
		इसमें शामिल है।			
		1. व्यापार किए गए माल की खरीद			
		2. व्यापार किए गए माल की वस्तुसूची में परिवर्तन			
		3. परिचालन व्यय			
		कर्मचारी लाभ व्यय	612.74	729.93	908.58
		वित्त लागतें	3,124.96	2,511.19	2,568.52
		मूल्यहास और प्रभाजन	1,411.41	1,466.20	1,458.61
		अन्य व्यय	773.69	905.90	533.85
		कुल व्यय	14,563.23	16,152.31	16,981.35
		प्रपत्रों के अनुसार:			
		परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	11,438.25	13,641.12	14,794.00
		वित्त और विविध व्यय (एफएमई)	3,124.96	2,511.19	2,187.39

		<table><tr><td>कुल व्यय</td><td>14,563.21</td><td>16,152.31</td><td>16,981.39</td></tr><tr><td>अंतर</td><td>0.02</td><td>0.00</td><td>(0.04)</td></tr></table> <p>लाखों में तैयार तुलनपत्र की कास्टिंग के कारण मामूली अंतर है। वर्ष 2016-17 और 2018-19 में क्रमशः रु. 2 हजार और रु. 4 हजार का अंतर संशोधित प्रपत्रों में समायोजित किया गया है।</p>	कुल व्यय	14,563.21	16,152.31	16,981.39	अंतर	0.02	0.00	(0.04)
कुल व्यय	14,563.21	16,152.31	16,981.39							
अंतर	0.02	0.00	(0.04)							
(ii).	<p>प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.3.2 के अनुसार, यदि आईएनडी एस और आईजीएपी के अधीन प्रतिवेदित व्यय में कोई अंतर पाया जाता है तो आईजीएपी के अनुसार आंकड़ों पर विचार करते हुए और आईएनडी एस आंकड़े को शामिल नहीं करते हुए एआरआर परिकलन में जरूरी समायोजन किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में, वीएसपीएल द्वारा क्र.सं. 2 पर प्रेषित, परिवर्तन लागत, विकास की लागत, अन्य वित्त प्रभार, उपदान, पट्टा किराया और एआरआर परिकलन से यथा अलग दर्शाते हुए वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आईएनडी एस से आईजीएपी तक परिसंपत्तियों की बिक्री पर पट्टा किराया तथा नुकसान के लिए “अन्य व्यय” शीर्षक के अधीन समायोजन दर्शाता है। इस संबंध में, वीएसपीएल निम्नलिखित स्पष्ट करे:-</p>									
	<p>(क). वीएसपीएल आईजीएपी के अधीन विवरण तैयार करते समय शामिल नहीं किए जाने के लिए सुविचारित मदों के लिए आईएनडी एस के अधीन दिए गए संव्यवहार को संक्षेप में स्पष्ट करे।</p>	<p>वीएसपीएल वित्तीय विवरण में दिए गए आईएनडी एस प्रभार का सार:</p> <p>1. परिवर्तन लागत:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>कंपनी ने ट्रांजिशन की तारीख को आईएनडी एस 11 (परिशिष्ट क-सेवा रियायत करार) लागू किया था जिसे अनुवर्ती वर्षों में ले जाया जा रहा है।</li><li>सेवा रियायत करार की समाप्ति पर प्रोद्भूत की जाने वाली लागत को बन्द किए जाने का निवल वर्तमान मूल्य इनटेनजिबल परिसंपत्तियों में जोड़ा गया है।</li><li>उपयुक्त एनपीवी पर ब्याज वर्ष 2018-19 में वित्तीय लागत के रूप में दर्शाया गया है (हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों में टिप्पणी सं. 21 देखें) और वर्ष 2016-17 और 2017-18 में इसे अन्य व्ययों (हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों में 2017-18 में टिप्पणी सं. 23 और 2016-17 में टिप्पणी सं. 4. 23 देखें) में परिवर्तन लागत के लिए प्रावधान के रूप में दर्शाया गया है।</li></ul> <p>2. विकास की लागत:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>परिशिष्ट क के अनुसार – सेवा रियायत करार निर्माण अथवा अपग्रेडेशन राजस्व को निष्पादित कार्य के पूरा होने की अवस्था के आधार पर सेवा रियायत अवधि के दौरान स्वीकार किया गया है।</li><li>इस प्रकार, मार्जिन सहित निर्माण की लागत को सेवा रियायत करार के अनुसार उपयोग करने के लिए अधिकार रूप में इनटेनजिबल्स में पूंजीकृत किया गया है और इसे लाभ तथा हानि लेखा से घुमाया गया है।</li><li>इस प्रकार, लाभ तथा हानि लेखा में लेखांकित निर्माण लागत तथा तदनुरूपी निर्माण राजस्व है। अतः, निर्माण लागत को आईएनडी एस समायोजन के रूप में कुल व्ययों से घटाया गया है।</li><li>एफवाई 2017 के लिए स्पष्टीकरण टिप्पणी सं. 4.18 और 4.20 और एफवाई 2018 के लिए टिप्पणी सं. 15 (ड) और 19 देखें।</li></ul> <p>3. अन्य वित्त प्रभार:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>आईएनडी एस 109 के अनुसार, उधारियों के लिए भुगतान किए गए प्रक्रिया प्रभारों को ऋण की अवधि में प्रभाजित किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार, पिछली अवधियों में लाभ तथा हानि में नामे किए गए ट्रांसिशन उधारी लागत की तारीख को वापिस किया गया था और वित्तीय विवरणों</li></ul>								

	<p>में उधारियों के साथ निवल किया गया था। ट्रांसिशन तारीख के बाद, गणना के आधार पर, कार्यवाही प्रभार के भाग को पीएल खाते से घटाया गया है जिसे प्रपत्र में आईएनडी एस समायोजन के रूप में वापिस किया गया है।</p> <p><b>4. उपदान</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>बीमांकक लाभ और हानियों को अन्य बृहत् आय में स्वीकार किया गया है और आईएनडी एस 19 के अनुसार अनुवर्ती अवधि में लाभ तथा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया है।</li><li>अतः, किसी भी लाभ/हानि को कर्मचारी लागत से घटाया नहीं गया है, इसे इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में अन्य बृहत् आय में सीधे लिया गया है।</li></ul> <p><b>5. पट्टा किराया व्यय:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमाराशियों के सही मूल्यांकन को ट्रांसिशन तारीख को लेखांकित किया गया है और दुलाई मूल्य और एनपीवी के बीच अंतर को प्रीपेड डिपॉजिट में लिया गया है जिसे पट्टा करार की अवधि में प्रभाजित किया गया है।</li></ul> <p><b>6. आईएनडी एस के अनुसार मूल्यहास:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>आईएनडी एस 11 के परिशिष्ट क के लागू होने पर, कंपनी ने सेवा रियायत करार (एससीए) से आने वाली मान्यता प्राप्त इनटेन्जीबल परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया है, जहां तक कंपनी के पास एससीए की अवधि के बाद रियायत अवसंरचना के उपयोग के लिए वसूली का अधिकार होगा। अतः, प्रभाजन/मूल्यहास को पूर्वव्यापी प्रभाव से परिकलित किया गया था और संव्यवहार तारीख को और अनुवर्ती अवधियों में लागू किया गया था।</li></ul> <p><b>7. परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि;</b></p> <p>इनटेन्जीबल परिसंपत्ति के परिसंपत्ति हिस्से की बिक्री को ब्लॉक में जमा किया गया है और आईएनडी एस में कोई लाभ/हानि को लेखांकित नहीं किया गया है।</p>																								
<p>(ख). वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित पट्टा किराया क्रमशः रु. 478.88 लाख, रु. 251.55 लाख और रु. 544.00 लाख है। उसके विपरीत, वीएसपीएल ने प्रपत्र 6 क में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए पट्टा किराये के आईएनडी एस आंकड़े क्रमशः रु. 3.27 लाख, रु. 3.27 लाख और रु. 5.46 लाख दर्शाया है जोकि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। यह आंकड़ा समायोजन आंकड़े दिखाई देते हैं। वीएसपीएल प्रारूप के अनुसार आईजीएपी के अनुसार आंकड़े भेजे, आईएनडी एस आंकड़े विधिवत् रूप से लेखापरीक्षित लेखों से मेल खाते हैं और भिन्नताओं को प्रपत्र 1 में समायोजन के रूप में लिए जाने की जरूरत है।</p>	<p>पट्टा किराया व्ययों में डब्ल्यूएबी और वीपीटी के लिए प्रतिभूति जमाराशि का सही मूल्यांकन है। उक्त समायोजन वर्ष 2016-17, 2017-18 के लिए रु. 3.27 लाख का आईएनडी एस आंकड़ा है और 2018-19 के लिए 5.46 लाख प्रपत्र 6क में लिया गया है और पट्टा किराये का संपूर्ण व्यय प्रपत्र 1 में परिचालन व्यों के हिस्से के रूप में सुविचारित किया गया है। एआरआर गणना के लिए प्रभाव नीचे सही दिया गया है:-</p> <table><tr><th>वित्तीय आंकड़ों के अनुसार</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th></tr><tr><td>पट्टा किराया व्यय – आईएनडी एस</td><td>3.26</td><td>3.26</td><td>5.46</td></tr><tr><td>पट्टा किराये – वीपीटी अन्य</td><td>5.85</td><td>11.74</td><td>8.65</td></tr><tr><td>पट्टा किराये से एक्विजम पार्क</td><td>258.40</td><td>64.90</td><td>68.79</td></tr><tr><td>पट्टा किराये से वीपीटी</td><td>195.23</td><td>166.12</td><td>437.83</td></tr><tr><td>पट्टा किराये से</td><td>16.14</td><td>5.52</td><td>23.28</td></tr></table>	वित्तीय आंकड़ों के अनुसार	2016-17	2017-18	2018-19	पट्टा किराया व्यय – आईएनडी एस	3.26	3.26	5.46	पट्टा किराये – वीपीटी अन्य	5.85	11.74	8.65	पट्टा किराये से एक्विजम पार्क	258.40	64.90	68.79	पट्टा किराये से वीपीटी	195.23	166.12	437.83	पट्टा किराये से	16.14	5.52	23.28
वित्तीय आंकड़ों के अनुसार	2016-17	2017-18	2018-19																						
पट्टा किराया व्यय – आईएनडी एस	3.26	3.26	5.46																						
पट्टा किराये – वीपीटी अन्य	5.85	11.74	8.65																						
पट्टा किराये से एक्विजम पार्क	258.40	64.90	68.79																						
पट्टा किराये से वीपीटी	195.23	166.12	437.83																						
पट्टा किराये से	16.14	5.52	23.28																						

		डब्ल्यूएबी प्लॉट				
		(क)	478.88	251.55	544.00	
		घटायें: आईएनडी एस अनुज्ञापत्र	(ख)	3.26	3.26	5.46
		पट्टा किराा व्यय (आईजीएएपी)		475.62	248.29	538.55
	(ग). इसी तरह, प्रपत्र 6क में अन्य वित्त व्यय, उपदान और परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान के आंकड़े भी लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं/अंतर्संबंधित नहीं हैं। अतः वीएसपीएल निर्धारित प्रारूप के अनुसार लेखापरीक्षित लेखों से विधिवत् मेल खा रहे और भिन्न आईजीएएपी, आईएनडी एस आंकड़ों के अनुसार आंकड़े भेजें। भिन्नता को प्रपत्र 1 में समायोजन के रूप में लिए जाने की जरूरत है।	● अन्य वित्तीय व्ययों (वित्त लागतों के अधीन) में आईएनडी एस के अनुसार उधारी लागत का प्रभाजन शामिल है। निम्नलिखित पिछले 3 वर्षों के लिए दर्शाये गए उधारी लागत के ब्योरे हैं, जोकि प्रपत्र 1 के मामले में आईएनडी एस के मामले में समायोजन के रूप में दर्शाये गए हैं।				
			2016-17	2017-18	2018-19	
		वित्तीय आंकड़ों के अनुसार				
		वित्तीय लागत (*)	3,124.96	2,511.19	2,187.39	
		घटायें: उधारी लागत – आईएनडी एस	2.47	7.99	7.61	
		आईजीएएपी के अनुसार वित्त लागत	3,122.49	2,503.20	2,179.78	
		(*) एफवाई 2018-19 के लिए टिप्पणी सं. 21 में दर्शाये गए सेवा रियायत करार के अधीन बाध्यता से संबंधित वित्त लागत अतिरिक्त।				
		● प्रपत्र 6क में उपदान समायोजन बीमांकक लाभ/हानि दर्शाता है जिसे आईएनडी एस-19 “कर्मचारी लाभ” के अनुसार अन्य बृहत् आय के अधीन दर्शाये जाने की आवश्यकता है और लाभ एवं हानि नुकसान में कर्मचारी लागत से घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसे पिछले 3 वर्षों के प्रत्येक लेखापरीक्षित लेखों में इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में “अन्य इक्विटी” टिप्पणी से मिलान नहीं किया जा सकता। इसकी सभी वर्षों में उपबंध टिप्पणियों के नीचे आईएनडी एस 19 के अनुसार दिए गए प्रकटन से भी जांच की जा सकती है। (हस्ताक्षरित वित्तीय विवरणों में एफवाई 2017 के लिए टिप्पणी सं. 4.13, एफवाई 2018 के लिए 13(ख) और एफवाई 2019 के लिए 13(ख) देखें)। उक्त लाभ/हानि प्रपत्र-1 में समायोजन रूप में दर्शाया गया है।				
			2016-17	2017-18	2018-19	
		वित्तीय आंकड़ों के अनुसार उपदान	7.64	11.17	13.34	
घटायें: पुनःमाप लाभ (आईएनडी एस) (*)	4.22	1.37	(7.32)			
आईजीएएपी के अनुसार उपदान	3.42	9.80	20.66			
	● आईएनडी एस के अनुसार परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि शून्य है क्योंकि बिक्री प्रोसीड्स को इनटेन्जीबल के ब्लॉक में जमा किया गया है और लाभ तथा हानि तभी लेखांकित की जाएगी जब ब्लॉक शून्य हो। तथापि, आईजीएएपी हानि को बुक किया जाएगा और इसलिए आईजीएएपी के अधीन रु. 45.67 लाख परिकलित किया गया है और प्रपत्र 6क और					



		परिणामस्वरूप प्रपत्र 1 में भी एआरआर गणना के लिए व्यय में जोड़ा गया है।
(iii).	वर्ष 2018-19 के लिए प्रपत्र-1 में ऋण पर ब्याज शीर्ष के अधीन शामिल नहीं किए जाने के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित आंकड़ा रु. 2,165.22 लाख है। यह वर्ष 2018-19 के लिए रु. 2,151.41 लाख लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। इस मद को शामिल नहीं किए जाने को सही किया जाए और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यथा प्रतिवेदित विचार किया जाए।	रु. 2165.22 लाख की राशि में रु. 13.82 लाख के अत्यावधि ऋणों पर ब्याज शामिल है जिसे वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में अन्य वित्तीय लागत के अधीन समूहित किया गया है। इसलिए, रु. 2151.41 लाख जमा रु. 13.82 लाख का ब्याज रु. 2165.22 लाख है जिसे हमने प्रपत्र 1 में दर्शाया है। एफवाई 2016-17 और 2017-18 में कोई ऐसा अत्यावधि ऋण ब्याज नहीं था।
(iv).	वीएसपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.3 (ii) के अनुसार कुल व्ययों से वर्ष 2016-17 से 2018-19 में क्रमशः रु. 8.22 लाख, रु. 80.62 लाख और रु. 31.03 लाख के अशोध्य और संदेहपूर्ण ऋणों के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया है। ये आंकड़े लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों से क्रॉस चैक नहीं किए जा सकते। वीएसपीएल यह स्पष्ट करे कि किसी शीर्षक के अधीन ये मदें लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित की गई हैं।	आंकड़े प्रत्येक लेखापरीक्षित लेख में अन्य व्यय शीर्षक के अधीन प्राप्ति-योग्य ट्रेड के इम्पेयरमेंट पर भत्ता का उल्लेख करते हुए क्रॉस चैक किए जा सकते हैं। टीएमपी प्रत्येक लेखापरीक्षित लेख में ट्रेड प्राप्ति योग्य अनुसूची के अधीन दर्शाये गए संभावित क्रेडिट नुकसान भत्ते में मूवमेंट को भी देखें। एफवाई 17-18 के लिए रिपोर्टों में टिप्पणी सं. 4.8 (ii) और एफवाई 2017-18 और 2018-19 के लिए 6.1 (क) देखें।
(v).	प्रपत्र 1 में सुविचारित कुल व्यय के सापेक्ष वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार कुल व्यय का मिलान करते हुए प्रपत्र 6ख में दिए गए मिलान विवरण में, यह देखा गया है कि प्रपत्र 6ख में मिलान विवरण में क्र.सं. 4 में कुल व्यय प्रपत्र-1 में क्र.सं. 5 में कुल व्यय से मेल नहीं खाता है। मिलान विवरण को उपर्युक्त टिप्पणी के आलोक में सही किया जाए।	वीएसपीएल ने इस मिलान के अधीन केवल आईएनडी एस प्रविष्टियों पर विचार किया है (एआरआर परिकलन में शामिल नहीं किए गए व्यय के लिए)। तथापि, टीएमपी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, वीएसपीएल ने अन्य व्ययों पर विचार किया है और संशोधित मिलान विवरण भी भेजा है।
(vi).	निम्नलिखित भेजें:	
	(क). वर्ष 2018-19 में रु. 144.20 लाख तक ट्रेड किए गए माल सहित के लिए औचित्य।	यह प्रासंगिक व्यय के साथ प्रत्येक राजस्व मद से मिलान के मैचिंग सिद्धांत के अनुसार है।
	(ख). वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः रु. 429.25 लाख, रु. 652.62 लाख और रु. 708.52 लाख तक टर्मिनल के बाहर कार्गो प्रहस्तन प्रभारों के लिए औचित्य।	वीएसपीएल से यह अपेक्षा की गई थी कि सेल के कोकिंग कोल के कम से कम 6 ग्रेडों का प्रहस्तन किया जाएगा और ज्यादातर समय टर्मिनल स्टॉकपाइल क्षेत्र ईक्यू-9 में प्रहस्तित कार्गो की स्टॉकिंग के लिए थोड़ा स्थान छोड़ते हुए सेल के कार्गो से घिरा रहता है। स्थान की ऐसी कमी के कारण, ईक्यू-9 के सकल कम उपयोग की चुनौती थी। रैकों की कमी के कारण कार्गो विराम समय में वृद्धि हमारे टर्मिनल के भीतर भंडारण स्थान पर और अवरोध था। इसपर पार पाने के लिए, हुक प्वाइंट पर केवल डिलीवरी देते हुए प्रहस्तित की जाती थी और प्रहस्तन एजेंटों (स्टीवडोर) ने कार्गो को हमारे टर्मिनल के बाहर वीपीटी से पट्टे पर लिए गए उनके प्लॉटों में स्थानांतरित किया था। तथापि, ज्यादातर ग्राहक करार वीएसपीएल से अपेक्षा करते हैं कि पूर्ण तट प्रहस्तन सेवाएं ऑफर की जाएं। इसलिए, इस तरह, वीएसपीएल को ईक्यू-9 में प्रहस्तित कार्गो को वीपीटी के स्टीवडोर द्वारा पट्टे पर लिए गए हमारे टर्मिनल के समीप वीपीटी के प्लॉटों में स्थानांतरित करना पड़ा था और ऐसे स्टीवडोरों के प्लॉटों पर तारपाउलिन कवरिंग, सिक्वोरिटी, प्लॉट किराये, धूल निवारण आदि जैसी संबंधित स्टॉक प्रबंधन सेवाओं के लिए व्यय प्रोदभूत किया था। इसके अलावा, वीपीटी सड़कों पर कार्गो के ऐसे संचलन के लिए धूल निवारण प्रभार संग्रहीत करता है। ऐसी सभी व्यय इस मद के अधीन लेखांकित किए जाते हैं जोकि ईक्यू-9 के सकल कम उपयोग से बचने और लक्ष्य थ्रुपुट को अर्जित करने के लिए अनिवार्य हैं।
	(ग). वीएसपीएल ने निर्माण लागत के रूप में वर्ष 2017-18 के लिए रु. 152.04 लाख पर विचार किया था। यदि निर्माण लागत आईएफआरआईसी 12 के अनुसार सेवा रियायत करार से संबंधित है तो उक्त व्यय को अलग रखा जाए।	उक्त व्यय को वर्ष 2017-18 में आईएनडी एस समायोजन (आईएनडी एस के अनुसार विकास की लागत) रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, इसे पहले ही प्रपत्र 6 ख में अलग रखा गया है।

	(घ). वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सुविचारित रु. 22.21 लाख, रु. 25.05 लाख और रु. 35.99 लाख की अन्य वित्त लागत की प्रकृति स्पष्ट करें।	बैंक गारंटी प्रभार, कार ऋण पर वित्त प्रभार और प्रक्रिया लागत का प्रभाजन आदि शामिल है।
	(ङ). यह स्पष्ट करें कि वर्ष 2016-17 के लिए रु. 27.56 लाख की सीमा तक अन्यो पर ब्याज को व्यय के रूप में क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए।	अन्यो पर ब्याज में मध्यस्थ के अधिनिर्णय के अनुसार अंतर रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर वीपीटी को भुगतान किए गए रु. 22.67 लाख का ब्याज शामिल है। अयोग्य इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने पर सेवा कर विभाग को किए गए भुगतानों के लेखा पर शेष रु. 4.89 लाख।
	(च). सेवा रियायत करार के अधीन दायित्व से संबंधित वित्त लागत का समावेशन।	एससीए के अधीन दायित्व के संबंध में कोई भी वित्तीय लागत स्वीकार्य व्ययों के रूप में शामिल नहीं की गई है। प्रपत्र 6क देखें जिसमें कुल लागत में समायोजन के रूप में सभी वर्षों के लिए आईएनडी एस के अनुसार परिवर्तन लागत शामिल नहीं किया गया है।
	(छ). वर्ष 2016-17 में रु. 46.30 लाख की सीमा तक प्रतिबद्ध उतराई में कमी के लिए प्रभारों का औचित्य बतायें, प्रभार दंडात्मक प्रकृति के हैं।	प्रतिबद्ध उतराई में कमी के लिए प्रभार प्रपत्र 1 में एआरआर गणना के लिए व्यय रूप में सुविचारित नहीं किया गया है। इसे 2016-17 तुलन पत्र में परिचालन व्यय के रूप में दर्शाया गया है परंतु इसे वर्ष 2017-18 में पुनर्समूहन के रूप में राजस्व के मुकाबले निवल किया गया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाए कि दिशानिर्देश व्यय की केवल कुछ मदों अर्थात् रॉयल्टी, ऋणों पर ब्याज, अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान, स्लो मूविंग वस्तुसूची और अन्य प्रावधान ही कुल व्यय से समायोजित करते हैं। यह मद किसी अस्वीकृत के अधीन शामिल नहीं है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए कि यह संविदित उतराई दर अर्जित नहीं करने के लिए क्षतिपूर्ति है और ज्यादातर यह हुक प्वाइंट से कार्गो लेने के लिए हमारे ग्राहकों द्वारा घाट पर पिछले पोतों के कार्गो की अनिकासी के कारण होता है।
	(ज). वर्ष 2016-17 के लिए सुविचारित रु. 276.85 लाख की परिवर्तन लागत के लिए प्रावधान हेतु औचित्य।	परिवर्तन के लिए प्रावधान अन्य व्ययों के हिस्से के रूप में सुविचारित किया गया है और तत्पश्चात आईजीएपी पर पहुंचने के लिए आईएनडी एस समायोजन रूप में हटाया गया है (प्रपत्र 6क देखें)।
(vii).	प्रपत्र 3 – कार्य पूंजी का परिकलन: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 के अनुसार, कार्य पूंजी के परिकलन के लिए मानदंड केपिटल पुर्जों की वस्तुसूची के एक वर्ष के औसत उपभोग तक और वस्तुसूची की अन्य मदें ईंधन को छोड़कर भंडारों के छह माह के औसत उपभोग तक सीमित किया गया है। रोकड़ शेषजमा पर सीमा एक माह के रोकड़ व्यय होंगे। सांविदिक बाध्यताओं के अनुसार भूस्वामी पत्तन को पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क के अग्रिम भुगतान और राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान विविध देनदारों के हिस्सेदारों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। टीजी 2019 में उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में, प्रपत्र सं. 3 में कार्य पूंजी के परिकलन के संबंध में, वीएसपीएल निम्नलिखित स्पष्ट/प्रेषित करें:-	
	(क). वीएसपीएल ने कार्य पूंजी के परिकलन में रु. 0.024 लाख रोकड़ पर विचार किया गया है जोकि निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं पाया गया है। कार्य पूंजी परिकलन के लिए रोकड़ व्यय सही करें और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 के अनुसार वर्ष 2018-19 के एक माह के रोकड़ व्यय के रूप में विचार करें। स्पष्ट करने के लिए, मूल प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी 2020 में वीएसपीएल द्वारा प्रेषित लागत विवरण के अनुसार, रोकड़ व्यय रु. 1063.75 लाख (अर्थात् वर्ष 2018-19 के लिए रु. 14366.92 लाख – आईजीएपी के अनुसार रु. 1601.94 लाख मूल्यहास/12 = रु. 1063.75 लाख) परिगणित होता है। वीएसपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पालन के लिए जरूरी संशोधन करे।	टीएमपी द्वारा दिए गए सूत्र के आधार पर, औसत रोकड़ व्यय प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार टीएमपी द्वारा उपलब्ध करवाये गए उक्त संशोधित सूत्र के अनुसार संशोधित किया गया है।

	<p>(ख). केपिटल पुर्जों के संबंध में, वीएसपीएल ने केपिटल पुर्जों के एक वर्ष के औसत उपभोग के रूप में रु. 458 लाख के आंकड़े दिए हैं। तथापि, वीएसपीएल ने क्र.सं. (i) पर कार्य पूंजी के परिकलन में केपिटल पुर्जों के लिए स्वीकार्य वस्तुसूची के रूप में रु. 399.96 लाख पर विचार किया है। इस प्रकार, इन दो आंकड़ों में बेमेल है। इसे शोधित करें। वीएसपीएल यह दर्शाये कि किस शीर्ष के अधीन इस मद को वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों में लिया गया है।</p>	<p>वीएसपीएल द्वारा एक माह का औसत उपभोग रु. 458 लाख है। तथापि, पुर्जों की क्लोजिंग वस्तुसूची रु. 399.96 लाख की सीमा तक है जोकि कार्य पूंजी गणना के लिए सुविचारित किया गया है।</p> <p>टीएमपी मार्च 2019 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की टिप्पणी 9 देखें। इस शीर्ष में रु. 8.13 लाख का ईंधन स्टॉक भी शामिल है जोकि टीजी 2019 के अनुसार कार्य पूंजी गणना में स्वीकार्य नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा इसे उचित ढंग से अलग रखा गया है।</p>												
	<p>(ग). टीजी 2019 के अनुसार और प्रपत्र-3 के अधीन निर्धारित टिप्पणी के अनुसार, साविदिक बाध्यताओं के अनुसार भूस्वामी पत्तन को पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क के अग्रिम भुगतान और राजस्व हिस्सेदारी/रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान विविध देनदारों के हिस्सेदारों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। वीएसपीएल द्वारा वीपीटी के साथ किए गए एलए के अनुसार, वीएसपीएल से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि राजस्व हिस्सेदारी अथवा पट्टा किराये का कोई अग्रिम भुगतान किया जाए। इसलिए, पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश में यथा प्रतिवेदित, लाइसेंस करार से आने वाली मदों में से कोई भी विविध देनदारों के रूप में विचार के पात्र नहीं है। उसके विपरीत, वीएसपीएल ने प्रपत्र-3 में रु. 1998.30 लाख पर विचार किया है जोकि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार नहीं है। वीएसपीएल दिशानिर्देश स्थिति का पालन करने के लिए इस मद में कार्य पूंजी के परिकलन में जरूरी शोधन करें।</p>	<p>लाइसेंस करार के खंड 5.2 के अनुसार, वीएसपीएल ने भूमि पट्टे के लिए वीपीटी के साथ पट्टा करार किया है। पट्टा करार के अनुसार किराया अग्रिम रूप में भुगतान किया जाएगा। वीएसपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा वीपीटी के साथ किए गए पट्टा करार की प्रति भेजी थी जिसमें वीएसपीएल से पट्टा किराये का अग्रिम भुगतान करने की अपेक्षा करता है।</p> <p>तदनुसार, टर्मिनल और एक्जिम पार्क के लिए वीपीटी को पट्टा किराये संशोधित प्रशुल्क प्रपत्र 3 में दर्शाये गए हैं।</p> <p>तत्पश्चात, वीएसपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा टर्मिनल एवं एक्जिम पार्क के लिए वीपीटी के साथ पट्टा करार की एक-एक प्रति भेजी थी।</p>												
(viii).	<p>सूचकांकित एआरआर:</p> <p>वीएसपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर रु. 19,311.47 लाख के अनुमानित एआरआर का 3.45 प्रतिशत तक सूचकांकन किया था। विचार किया जाने वाला लागू सूचकांकन वर्ष 2019-20 के लिए 3.45 प्रतिशत की बजाय 4.26 प्रतिशत है। अतः वीएसपीएल 3.45 प्रतिशत के स्थान पर 4.26 प्रतिशत के सूचकांकन कारक को लागू करते हुए एआरआर संशोधित करें।</p>	<p>एआरआर 4.26 प्रतिशत का सूचकांकन कारक लागू करते हुए संशोधित किया गया है।</p>												
(ix).	<p>एआरआर (प्रपत्र-7) में सुविचारित आईजीएएपी के अनुसार अचल परिसंपत्ति विवरण:</p> <p>लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार, संयंत्र तथा मशीनरी एवं वाहनों के लिए वर्ष 2018-19 में निपटान क्रमशः रु. 808.77 लाख और रु. 10.37 लाख है। इसके विपरीत, वीएसपीएल ने क्रमशः रु. 1455.30 लाख और रु. 12.39 लाख पर विचार किया है जोकि वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित निपटान आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। अतः, वीएसपीएल वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार निपटान के आंकड़ों पर विचार करें। परिणामस्वरूप, आईजीएएपी और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाम (आरओसीई) के अधीन मूल्यहास आंकड़ों में भी जरूरी शोधन करें।</p>	<p>आईएनडी एस को ट्रांजिशन पर, वीएसपीएल ने 01 अक्टूबर 2014 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी पीपीई के दुलाई मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया था। तदनुसार, संयंत्र तथा मशीनरी और वाहनों का दुलाई मूल्य वर्ष 2018-19 में निपटानों के रूप में दर्शाया गया है।</p> <p>आईजीएएपी के अनुसार, परिसंपत्तियों का कुल मूल्य प्रपत्र 7 में निपटानों के रूप में दर्शाया गया है। परिसंपत्ति की बिक्री में नुकसान को प्रपत्र 6 ख में मद रूप में दर्शाया गया है और इसलिए प्रशुल्क प्रारूपों में कोई बदलाव अपेक्षित नहीं है।</p> <p>आईजीएएपी और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार निपटान में अंतर इसलिए है क्योंकि वित्तीय विवरण आईएनडी एस के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इसलिए सेवा रियायत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आईजीएएपी के अधीन परिसंपत्तियों के जीवनकाल से भिन्न है।</p> <p>यह अंतर वीएसपीएल द्वारा प्रपत्र 6क और 6ख में आईएनडी एस समायोजन के रूप में पर्याप्ततः समायोजित किए गए हैं।</p> <table><tr><td></td><td></td><td>संयंत्र और मशीनरी</td><td>वाहन</td></tr><tr><td>सकल मूल्य</td><td>क</td><td>1,455.30</td><td>12.39</td></tr><tr><td>01.10.14 को दुलाई</td><td>ख</td><td>1,202.68</td><td>10.37</td></tr></table>			संयंत्र और मशीनरी	वाहन	सकल मूल्य	क	1,455.30	12.39	01.10.14 को दुलाई	ख	1,202.68	10.37
		संयंत्र और मशीनरी	वाहन											
सकल मूल्य	क	1,455.30	12.39											
01.10.14 को दुलाई	ख	1,202.68	10.37											

		<table><tr><td>मूल्य</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30.0.14 तक मूल्यहास</td><td>ग</td><td>252.62</td><td>2.02</td></tr><tr><td>01.10.14 से निपटान तक मूल्यहास</td><td>घ</td><td>348.23</td><td>6.47</td></tr><tr><td>कुल मूल्यहास</td><td>ग+घ</td><td>600.85</td><td>8.49</td></tr><tr><td>बिक्री प्रोसीड्स</td><td>ङ</td><td>808.77</td><td>5.26</td></tr><tr><td>परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि</td><td>क-(ग+घ)- ङ</td><td>45.68</td><td>(1.36)</td></tr></table>	मूल्य				30.0.14 तक मूल्यहास	ग	252.62	2.02	01.10.14 से निपटान तक मूल्यहास	घ	348.23	6.47	कुल मूल्यहास	ग+घ	600.85	8.49	बिक्री प्रोसीड्स	ङ	808.77	5.26	परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	क-(ग+घ)- ङ	45.68	(1.36)												
मूल्य																																						
30.0.14 तक मूल्यहास	ग	252.62	2.02																																			
01.10.14 से निपटान तक मूल्यहास	घ	348.23	6.47																																			
कुल मूल्यहास	ग+घ	600.85	8.49																																			
बिक्री प्रोसीड्स	ङ	808.77	5.26																																			
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	क-(ग+घ)- ङ	45.68	(1.36)																																			
2.	राजस्व अनुमानन (प्रपत्र-4):  राजस्व के अनुमानन के संबंध में, निम्नलिखित बिन्दु देखें:																																					
(i).	<p>घाटशुल्क प्रभार और स्टीवडोरिंग प्रभार:</p> <p>घाटशुल्क प्रभारों और स्टीवडोरिंग प्रभारों से राजस्व केवल कुछ कार्गो मदों जैसे कोयला, उर्वरक, स्टीम कोयला, पेट कोक, जिप्सम, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और अन्य के लिए अनुमानित किए गए हैं। सभी अन्य कार्गो के लिए जिसके लिए प्रशुल्क प्रस्तावित किए गए हैं, वीएसपीएल ने घाटशुल्क प्रभारों और स्टीवडोरिंग प्रभारों से किसी राजस्व का अनुमान नहीं लगाया है। इसके अलावा, ऐसी कार्गो मदों के लिए जिनके लिए घाटशुल्क और स्टीवडोरिंग राजस्व अनुमानित किए गए हैं, यह देखा गया है कि यह केवल विदेशी कार्गो के लिए है और तटीय कार्गो के लिए नहीं है।</p>	<p>निम्नलिखित पिछले 3 वर्षों के लिए वीएसपीएल द्वारा प्रहस्तित औसत मात्रा के कार्गोवार ब्योरे हैं। तदनुसार, राजस्व एआरआर में कार्गो मदों के लिए अनुमानित किए गए हैं। सभी अन्य कार्गो मदों के लिए जिसके लिए प्रशुल्क प्रस्तावित किए गए हैं, वीएसपीएल प्रहस्तन करने की स्थिति में होगा जब कभी ग्राहक हमारे टर्मिनल के माध्यम से इन कार्गो का प्रहस्तन करते हैं।</p> <p>पिछले तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर तटीय कार्गो परिकल्पित नहीं किए गए हैं और इन्हें तटीय कार्गो के लिए लागू शर्तों और दरों पर मौजूदा नीतियों के अनुसार प्रहस्तित किया जाएगा।</p> <table><tr><td>विवरण</td><td>औसत प्रतिवर्ष (लाख मी.ट.)</td><td>% कार्गो</td></tr><tr><td>कोकिंग कोयला</td><td>28.74</td><td>42.00</td></tr><tr><td>स्टीम कोयला</td><td>15.28</td><td>22.33</td></tr><tr><td>जिप्सम</td><td>6.20</td><td>9.06</td></tr><tr><td>चूनापत्थर</td><td>2.70</td><td>3.94</td></tr><tr><td>मैगनीज अयस्क</td><td>1.71</td><td>2.50</td></tr><tr><td>लौह अयस्क</td><td>3.91</td><td>5.71</td></tr><tr><td>पेट कोक</td><td>7.10</td><td>10.37</td></tr><tr><td>उर्वरक</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>बाक्साइट</td><td>2.29</td><td>3.34</td></tr><tr><td>अन्य</td><td>0.50</td><td>0.74</td></tr><tr><td>-</td><td>68.43</td><td>100.00</td></tr></table>	विवरण	औसत प्रतिवर्ष (लाख मी.ट.)	% कार्गो	कोकिंग कोयला	28.74	42.00	स्टीम कोयला	15.28	22.33	जिप्सम	6.20	9.06	चूनापत्थर	2.70	3.94	मैगनीज अयस्क	1.71	2.50	लौह अयस्क	3.91	5.71	पेट कोक	7.10	10.37	उर्वरक	-	-	बाक्साइट	2.29	3.34	अन्य	0.50	0.74	-	68.43	100.00
विवरण	औसत प्रतिवर्ष (लाख मी.ट.)	% कार्गो																																				
कोकिंग कोयला	28.74	42.00																																				
स्टीम कोयला	15.28	22.33																																				
जिप्सम	6.20	9.06																																				
चूनापत्थर	2.70	3.94																																				
मैगनीज अयस्क	1.71	2.50																																				
लौह अयस्क	3.91	5.71																																				
पेट कोक	7.10	10.37																																				
उर्वरक	-	-																																				
बाक्साइट	2.29	3.34																																				
अन्य	0.50	0.74																																				
-	68.43	100.00																																				
(ii).	प्रशुल्क मदें मौजूदा एसओआर में निर्धारित की गई हैं और संशोधित प्रशुल्क के साथ प्रस्तावित एसओआर में शामिल भी किया गया है; परंतु निम्नलिखित प्रशुल्क मदों के लिए प्रपत्र-4 में वीएसपीएल द्वारा किसी राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया है:																																					
(क).	तटीय पोत के लिए बर्थ किराया प्रभार।	<p>वीएसपीएल ने वार्षिक मात्राओं के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण तटीय पोतों को प्रहस्तित नहीं किया है। इसलिए, तटीय पोतों से आय की परिकल्पना नहीं की गई है। वीएसपीएल ने 100 प्रतिशत विदेशी पोतों पर विचार करते हुए राजस्व का अनुमान लगाया है।</p> <p>यदि तटीय पोतों के लिए कुछ मात्रा का अनुमान लगाया जाता है तो राजस्व में 40 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी और राजस्व अपेक्षा तदनुसार बढ़ेगी</p>																																				

		जोकि वांछनीय नहीं पाया गया है।																
	(ख). पोतों के अति विराम के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार।	वीएसपीएल ने पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल एक या दो मामलों में दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार वसूल किए हैं। इसलिए, इस प्रशुल्क के लिए आय का अनुमान नहीं लगाया गया है।																
	(ग). पोतों को पानी की आपूर्ति के लिए प्रभार।	वीएसपीएल ने पिछले 3 वर्षों के दौरान पोतों को पानी की आपूर्ति के लिए प्रभार संग्रहीत नहीं किए हैं। इसलिए, आय की परिकल्पना नहीं की गई है।																
	(घ). पोतांतरण कार्गों पर प्रभार	जैसाकि ऊपर दिया गया है।																
	(ङ). विलंबशुल्क प्रभार (आयात/निर्यात/पोतांतरण)।	जैसाकि ऊपर दिया गया है।																
	(च). तटीय कार्गों के लिए तट परिचालन सेवाएं	जैसाकि ऊपर दिया गया है।																
	(छ). उपस्कर की तैनाती के लिए प्रभार:  (i). तटीय कार्गों के लिए 104 टन एचएमसी।  (ii). धूल निवारण प्रणाली प्रभार (ब्रेक बल्क)।  (iii). 120 टन इलैक्ट्रॉनिक मोशन वे ब्रिज के लिए भारतोलन प्रभार।	तट प्रहस्तन से राजस्व के अधीन शामिल किया गया है।  (i). जैसाकि ऊपर दिया गया है।  (ii). ब्रेक बल्क प्रहस्तित नहीं किया जाता है।  (iii). यह वैकल्पिक सेवा है।																
	(ज). अन्य सेवाओं के लिए प्रभार।	--																
(iii).	उपर्युक्त (i) और (ii) के संबंध में, वीएसपीएल से यह पुष्टि करने का अनुरोध है कि वर्ष 2018-19 में उपर्युक्त मदों के लिए वीएसपीएल द्वारा कोई भी कार्गो यातायात/सेवाएं प्रदत्त नहीं की जाती हैं और वर्ष 2018-19 के दौरान कोई राजस्व अर्जित नहीं हुआ था। यदि वर्ष 2018-19 में वीएसपीएल द्वारा यातायात प्रहस्तित नहीं किया गया था, वीएसपीएल उपर्युक्त मदों के लिए राजस्व अनुमानन के लिए आधार रूप में वर्ष 2016-17 और/अथवा 2017-18 के यातायात पर विचार करे। वीएसपीएल दरमान के सरलीकरण पर विचार करे और उन प्रशुल्क मदों को हटाये जिनके लिए वीएसपीएल द्वारा प्रदत्त किए जाने के लिए प्रस्तावित सेवाएं और यातायात परिकल्पित नहीं किया गया है।	वीएसपीएल ने वार्षिक मात्राओं के मामले में पिछले 3 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण तटीय पोतों को प्रहस्तित नहीं किया है, तटीय पोतों से आय परिकल्पित नहीं की गई है। तटीय मात्रा लगभग 6.5 प्रतिशत है।  तथापि, वीएसपीएल ने केवल विदेशी पोतों पर विचार करते हुए 100 प्रतिशत के लिए राजस्व का अनुमान लगाया है, जोकि तटीय पोतों से राजस्व की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक राजस्व है।  प्रशुल्क मदें प्रस्तावित की गई हैं यदि ग्राहक हमारे टर्मिनल के माध्यम से इन कार्गों का प्रहस्तन करते हैं तब यह लागू होगा। वीएसपीएल के बहु कार्गो टर्मिनल होते हुए और कुछ कार्गों की मौसमी प्रकृति पर विचार करते हुए, दरें निर्धारित किए जाने की जरूरत महसूस की गई है।																
(iv).	यह देखा गया है कि मसौदा दरमान में प्रस्तावित दरों के सापेक्ष प्रपत्र 4 में राजस्व के अनुमानन के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित प्रशुल्क दरों के संबंध में निम्नलिखित कुछ मदों के लिए मामूली बेमेल है:  <div>रु./प्रति मी.ट.</div> <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>मसौदा एसओ आर में प्रस्तावित दरें (विदेशी कार्गों के लिए)</th><th>प्रपत्र-4 में राजस्व अनुमानन के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित दरें (विदेशी कार्गों के लिए)</th></tr><tr><td>(i).</td><td>घाटशुल्क प्रभार</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(क)</td><td>पेट कोक</td><td>57</td><td>45</td></tr><tr><td>(ख)</td><td>अन्य</td><td>76</td><td>40</td></tr></table>	क्र.सं.	विवरण	मसौदा एसओ आर में प्रस्तावित दरें (विदेशी कार्गों के लिए)	प्रपत्र-4 में राजस्व अनुमानन के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित दरें (विदेशी कार्गों के लिए)	(i).	घाटशुल्क प्रभार			(क)	पेट कोक	57	45	(ख)	अन्य	76	40	सुझाव के अनुसार जरूरी परिवर्तन किए गए हैं।
क्र.सं.	विवरण	मसौदा एसओ आर में प्रस्तावित दरें (विदेशी कार्गों के लिए)	प्रपत्र-4 में राजस्व अनुमानन के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित दरें (विदेशी कार्गों के लिए)															
(i).	घाटशुल्क प्रभार																	
(क)	पेट कोक	57	45															
(ख)	अन्य	76	40															

	<table><tr><td>(2)</td><td>स्टीवडोरिंग प्रभार</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(क)</td><td>मैगनीज अयस्क</td><td>40</td><td>36</td></tr><tr><td>(ख)</td><td>अन्य</td><td>60</td><td>40</td></tr></table> <p>वीएसपीएल से अनुरोध है कि उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में राजस्व अनुमानन में जरूरी शोधन करें।</p>	(2)	स्टीवडोरिंग प्रभार			(क)	मैगनीज अयस्क	40	36	(ख)	अन्य	60	40	
(2)	स्टीवडोरिंग प्रभार													
(क)	मैगनीज अयस्क	40	36											
(ख)	अन्य	60	40											
3.	दरमान:													
(i).	<p>सामान्य निबंधन एवं शर्तें:</p> <p>प्राधिकरण ने समय-समय पर सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे वीएसपीएल सहित बीओटी परिचालकों के लिए सामान्य अंगीकरण आदेश पारित किया था और सभी महापत्तन न्यासों और वीएसपीएल सहित वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों से अनुरोध किया गया था कि एसओआर में उपयुक्त टिप्पणियां शामिल की जाएं। तथापि, वीएसपीएल ने निम्नलिखित सामान्य अंगीकरण आदेश के अनुसार प्रस्तावित एसओआर में उपयुक्त टिप्पणियां शामिल नहीं की थी:</p>													
	<p>(क). केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 38/2018-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई 2018 के अनुसार श्रीलंका अथवा बंगलादेश के क्षेत्रीय जलमार्गों के माध्यम से एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक जाने वाले जलयानों और कार्गो के लिए रियायती तटीय प्रशुल्क के लिए निर्धारित प्रावधान से संबंधित सामान्य अंगीकरण आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 में संशोधन आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 25 सितंबर 2018।</p>	<p>पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए पोत के वर्गीकरण हेतु प्रणाली और पोत संबंधित प्रभारों (वीआरसी) की वसूली के लिए मानदंड हेतु संशोधन आदेश सं. टीएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 के अनुसार प्रावधान संशोधित एसओआर में शामिल की गई है।</p>												
	<p>(ख). सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर बीओटी टर्मिनलों द्वारा सामान्य अंगीकरण आदेश के अनुसार दो वर्षों की अवधि के लिए सभी महापत्तन न्यासों और वहां पर परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के दरमानों में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) द्वारा प्रदत्त की जाने वाली लॉजिस्टिक डाटा बैंक सेवा के लिए कंटेनरों पर अनिवार्य उपयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की वसूली के लिए प्रावधान शामिल करते हुए सामान्य आदेश के रूप में प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/12/2019-एमयूसी दिनांक 24 जुलाई 2019 पारित किया था वह वीएसपीएल के मामले में भी लागू होगा।</p> <p>वीएसपीएल इन सामान्य आदेशों में विनिर्दिष्ट एसओआर में प्रावधान शामिल करे।</p>	<p>आदेश सं. टीएमपी/12/2019-एमयूसी के अनुसार अनिवार्य उपयोक्ता प्रभार (एमयूसी) के लिए प्रावधान विशेष रूप से कंटेनरों के लिए है। वीएसपीएल कोई कंटेनर कार्गो प्रहस्तन नहीं कर रहा है, इसलिए यह लागू नहीं है।</p>												
(ii).	<p>वीएसपीएल ने निम्नलिखित नई प्रशुल्क मदों का प्रस्ताव किया है:</p> <p>(क). बाक्साइट के लिए घाटशुल्क प्रभार।</p> <p>(ख). बाक्साइट और मैगनीज अयस्क के लिए स्टीवडोरिंग प्रभार।</p>	<p>वीएसपीएल ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 2.29 लाख मी.ट. बाक्साइट की औसत मात्रा का प्रहस्तन किया है, जोकि प्रहस्तित कुल कार्गो के 3.34 प्रतिशत के समकक्ष है, उक्त प्रभारों की वसूली पर भविष्य में विसंगति से बचने के लिए पृथक घाटशुल्क और स्टीवडोरिंग दरों का प्रस्ताव किया गया है। बाक्साइट और मैगनीज अयस्क के लिए प्रस्तावित स्टीवडोरिंग दरें सीमेंट विलंकर जैसे बल्क कार्गो के अनुसार हैं। तथापि, बाक्साइट के बिना, हमारी मात्रा घटकवार पर 99.5 प्रतिशत पूर्वानुमानित की गई है। हम शेष 0.5 प्रतिशत के अधीन</p>												

	प्रस्तावित नई प्रशुल्क मदों के लिए आधार स्पष्ट करें। राजस्व अनुमान में इन नई प्रशुल्क मदों से राजस्व को नहीं लिया गया है। वीएसपीएल इन नई मदों के लिए अनुमानित राजस्व अनुमान शामिल करे यदि वर्ष 2018-19 के दौरान कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया हो।	बाक्सइट का प्रहस्तन कर सकते हैं और इसलिए कोई पूर्वानुमान नहीं दिया गया है।
(iii).	<p>पिछले संशोधन के दौरान वीएसपीएल ने यह उल्लेख करते हुए रेलवे साइडिंग, प्रशासन तथा अनुरक्षण प्रभारों को हटाने का प्रस्ताव किया था कि यह प्रशुल्क मद वीएसपीएल द्वारा संग्रहीत नहीं की जा रही है। वीएसपीएल ने अब रेलवे अनुरक्षण प्रभारों तथा साइडिंग प्रभारों के लिए रु. 6/- प्रति टन की दर से अनुसूची 4.2 के अधीन इस प्रशुल्क मद को पुनः-शुरू करने का प्रस्ताव किया है।</p> <p>यह देखा गया है कि पिछले संशोधन से पूर्व के प्रशुल्क आदेश अर्थात् आदेश सं. टीएमपी/5/2011-वीएसपीएल दिनांक 11 अक्टूबर 2011 में, रेलवे साइडिंग प्रभारों के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क रु. 3.20 प्रति टन था जिसे बढ़ाकर रु. 6.00 प्रति टन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधित प्रशुल्क मद के लिए आधार स्पष्ट करें। राजस्व अनुमान में इन नई प्रशुल्क मदों से राजस्व को नहीं लिया गया है। वीएसपीएल इन नई मदों के लिए संभावित राजस्व अनुमान शामिल करे भले ही वर्ष 2018-19 के दौरान कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया हो।</p>	<p>नया प्रशुल्क शामिल करते समय 2010 के दौरान छूट दर प्रस्तावित की गई थी। हमारे सह-पत्र दिनांक 24 अगस्त 2011 का अनुलग्नक-VIII देखें जिसमें हमने राजस्व अपेक्षा भेजी है। व्यय में वृद्धि पर विचार करते हुए अब हमने रु. 6 प्रति मी.ट. की दर का प्रस्ताव किया है।</p> <p>हमने बल्क सामग्री प्रहस्तन प्रणाली के माध्यम से प्रहस्तित कोयले के लिए 100 प्रतिशत और सभी अन्य कार्गो के लिए 60 प्रतिशत पर विचार करते हुए राजस्व का अनुमान लगाया है।</p>
(iv).	<p>बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को कार्यान्वित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 8.2.2 विनिर्दिष्ट करता है कि एसओआर तैयार करते समय, बीओटी परिचालक जहां तक संभव होगा अपने मौजूदा एसओआर में यथामूल्य घाटशुल्क दर, यदि कोई हो, के साथ जाएगा और इस कार्गो के प्रहस्तन अथवा बाजार निर्धारित प्रशुल्क पर विशेष ध्यान रखते हुए इन मामलों में विशिष्ट घाटशुल्क दर निर्धारित करता है।</p> <p>पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान भी, प्राधिकरण ने उक्त कार्गो के प्रहस्तन के समय अपेक्षित विशेष ध्यान, यदि कोई हो, और प्रहस्तन की लागत के आधार पर बिजली सामान तथा मशीनरी के लिए इकाई दरों का प्रस्ताव करने के लिए वीएसपीएल को सलाह दी थी। तथापि, वीएसपीएल ने बिजली सामान और मशीनरी के लिए यथामूल्य आधार पर घाटशुल्क दरों का प्रस्ताव किया है। इस परिप्रेक्ष्य में, वीएसपीएल पिछले प्रशुल्क आदेश में प्रदत्त सलाह के अनुसार और वर्किंग दिशानिर्देशों के अनुपालन में यथामूल्य दर प्रस्तावित करने की बजाय प्रासंगिक कार्गो प्रहस्तित करने की लागत के संदर्भ में कार्गो के भार अथवा मात्रा के आधार पर बिजली सामान और मशीनरी के लिए घाटशुल्क दर का प्रस्ताव करे।</p>	जैसाकि पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान सूचित किया गया है, ये दो माल बहुत कम पाई जाने वाली मदें हैं और सामान्यतः प्रहस्तित नहीं की जाती हैं। इसलिए, सुविचारित की जाने वाली प्रहस्तन की लागत और अन्य कारक आने वाले समय में अनुभव से प्राप्त किए जाएंगे। अतः हम वर्तमान के लिए यथामूल्य दर को जारी रखने का अनुरोध करते हैं।
(v).	<p>मौजूदा दरमानों में, अनुसूची 2.1.2 खंड 2.1.4 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बर्थ अधिग्रहणता के बाद पोत के अति विराम के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार निर्धारित करती है। अनुसूची 2.1.4 लगभग 34 कार्गो मदों के बारे में आयात कार्गो और निर्यात कार्गो अलग-अलग के लिए घटकवार प्रति पोत प्रति पाली आउटपुट निर्धारित करती है।</p> <p>प्रस्तावित दरमानों में, वीएसपीएल ने अनुसूची 2.1.4 को युक्तिसंगत बनाया है/संशोधित किया है और घटकों के 5 समूह के लिए प्रतिदिन आउटपुट का प्रस्ताव किया है। इस</p>	

	संबंध में, वीएसपीएल निम्नलिखित स्पष्टीकरण भेजे:																																																												
	(क). प्रस्तावित संशोधन के लिए कारण।	प्रस्तावित संशोधन शुष्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन और दंडात्मक प्रभारों की वसूली के मानदंडों पर ट्रेड परिपत्र सं. 907 दिनांक 30-06-2018 और ट्रेड 912 दिनांक 09-07-2018 द्वारा वीपीटी मानदंडों के अनुसार है। (प्रतिलिपि संलग्न)																																																											
	(ख). प्रस्तावित पोत आउटपुट टनों में प्रतिदिन पर पहुंचने के लिए आधार। पांच कार्गो समूहों के प्रत्येक समूह के लिए पिछले तीन वर्षों के लिए वास्तविक औसत प्रतिदिन आउटपुट भी भेजे।	<div>निम्नलिखित पिछले तीन वर्षों के वास्तविक औसत प्रतिदिन आउटपुट हैं:</div> <table><tr><th rowspan="2">कार्गो</th><th colspan="4">औसत उत्तराई दर</th></tr><tr><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>औसत</th></tr><tr><td>कोकिंग कोयला</td><td>22,720</td><td>23,550</td><td>22,735</td><td>23,002</td></tr><tr><td>स्टीम कोयला</td><td>16,176</td><td>15,636</td><td>14,430</td><td>15,414</td></tr><tr><td>जिप्सम</td><td>16,899</td><td>16,694</td><td>12,995</td><td>15,530</td></tr><tr><td>चूनापत्थर</td><td>12,205</td><td>13,790</td><td>13,446</td><td>13,147</td></tr><tr><td>मैगनीज अयस्क</td><td>12,079</td><td>11,976</td><td>5,702</td><td>9,919</td></tr><tr><td>लौह अयस्क</td><td>16,973</td><td>14,530</td><td>12,535</td><td>14,679</td></tr><tr><td>पेट कोक</td><td>16,447</td><td>13,151</td><td>16,809</td><td>15,469</td></tr><tr><td>उर्वरक</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>बाक्साइट</td><td>13,574</td><td>15,013</td><td>19,301</td><td>15,963</td></tr><tr><td>अन्य</td><td>4,416</td><td>7,135</td><td>8,891</td><td>6,814</td></tr></table>	कार्गो	औसत उत्तराई दर				2016-17	2017-18	2018-19	औसत	कोकिंग कोयला	22,720	23,550	22,735	23,002	स्टीम कोयला	16,176	15,636	14,430	15,414	जिप्सम	16,899	16,694	12,995	15,530	चूनापत्थर	12,205	13,790	13,446	13,147	मैगनीज अयस्क	12,079	11,976	5,702	9,919	लौह अयस्क	16,973	14,530	12,535	14,679	पेट कोक	16,447	13,151	16,809	15,469	उर्वरक	-	-	-	-	बाक्साइट	13,574	15,013	19,301	15,963	अन्य	4,416	7,135	8,891	6,814
कार्गो	औसत उत्तराई दर																																																												
	2016-17	2017-18	2018-19	औसत																																																									
कोकिंग कोयला	22,720	23,550	22,735	23,002																																																									
स्टीम कोयला	16,176	15,636	14,430	15,414																																																									
जिप्सम	16,899	16,694	12,995	15,530																																																									
चूनापत्थर	12,205	13,790	13,446	13,147																																																									
मैगनीज अयस्क	12,079	11,976	5,702	9,919																																																									
लौह अयस्क	16,973	14,530	12,535	14,679																																																									
पेट कोक	16,447	13,151	16,809	15,469																																																									
उर्वरक	-	-	-	-																																																									
बाक्साइट	13,574	15,013	19,301	15,963																																																									
अन्य	4,416	7,135	8,891	6,814																																																									
	(ग). वीएसपीएल ने विभिन्न कार्गो मदों को एक समूह में समूहित किया है और टन प्रतिदिन प्रस्तावित किया है। वीएसपीएल पुष्टि करे कि दोनों के साथ समूहित घटकों के लिए प्रहस्तन दर एकसमान/समान हैं।	<div>वीपीटी ने शुष्क बल्क कार्गो के प्रहस्तन के मानदंडों और दंडात्मक प्रभारों की वसूली पर ट्रेड परिपत्र सं. 907 दिनांक 30.06.2018 और ट्रेड 912 दिनांक 09.07.2018 जारी किए थे।</div> <div>यह पुष्टि की गई है कि एकसाथ समूहित घटकों के लिए प्रहस्तन दरें एकसमान/समान हैं।</div>																																																											
	(घ). प्रपत्र-5 में, वीएसपीएल ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधित मानदंड आउटपुट प्रति जलयान बर्थ दिवस (ओएसबीडी) मानदंडों के अनुसार हैं। वीएसपीएल व्याख्यायित करे कि कौन-से ओएसबीडी मानदंड अंगीकृत किए गए हैं और टीजी 2019 के अधीन बीओटी परिचालकों जो पहले टीजी 2005 द्वारा शासित किए जाते थे, के लिए उन मानदंडों की प्रयोज्यता का संदर्भ दें।																																																												
(vi).	<div>मौजूदा दरमानों में, अनुसूची 2.1.2 खंड 2.1.4 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बर्थ अधिग्रहणता के बाद पोत के अति विराम के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार निर्धारित करती है। अनुसूची 2.1.2 (i) दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों को आकर्षित किए बिना कार्गो परिचालन के पूरा होने के बाद बर्थ अभिग्रहण के लिए अनुमत खंड 2.1.4. अनुसूची 2.1.2 (i) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बर्थ अभिग्रहणता के बाद पोत के अतिविराम के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार निर्धारित करता है।</div> <div>प्रस्तावित दरमान में, वीएसपीएल ने अब ऐसे किसी पोत के लिए 10 घंटे से 4 घं तक कार्गो परिचालन के पूरा होने के बाद विराम के लिए बर्थ अभिग्रहणता की अनुमत अवधि कम करने का प्रस्ताव किया है जो "सिकयोरिंग" की अपेक्षा करता है और खाद्यान्न पोत धमीकरण की अपेक्षा करते हैं और सभी</div>	<div>ये संशोधन हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर और वीपीटी द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार प्रस्तावित किए गए हैं। कम किए गए घंटे पर्याप्त पाये गए थे क्योंकि वहां इस तरह के बहुत ही कम मामले थे। इसलिए, प्रपत्र-4 में अनुमान में राजस्व भी सुविचारित नहीं किया गया था।</div>																																																											



	अन्य मामलों में 7 घंटे से 4 घंटे। वीएसपीएल प्रस्तावित संशोधन का आधार स्पष्ट करे और पुष्टि करे कि क्या इसका राजस्व प्रभाव प्रपत्र 4 में लिया गया है।	
(vii).	विदेशगामी पोत के लिए वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि बर्थ सं. ईक्यू-8 के लिए बर्थ किराया प्रभागों में 11.24 प्रतिशत की वृद्धि, बर्थ सं. ईक्यू-9 के लिए बर्थ किराये में वृद्धि 1.12 प्रतिशत परिगणित होती है। तथापि, तटीय पोत के लिए वृद्धि क्रमशः 80.03 प्रतिशत और 62.88 प्रतिशत परिगणित होती है। इसी तरह, तटीय श्रेणी के लिए पानी की आपूर्ति हेतु प्रभागों और दंडात्मक बर्थ किराया प्रभागों में प्रस्तावित वृद्धि विदेशी श्रेणी के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क की अपेक्षा अधिक है। तटीय श्रेणी के लिए प्रस्तावित दरों में तीव्र वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि वीएसपीएल यह पुनः कहते हुए तटीय कंटेनर के लिए दर प्रचलित विनिमय दर के साथ निर्धारित की है और तब इसे उसके 60 प्रतिशत पर पैगिंग किया गया था जोकि सरकार की प्रचलित लागू तटीय रियायत नीति के अनुसार नहीं है। सरकार की तटीय रियायत नीति प्रत्येक सामान्य संशोधन के दौरान तटीय कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन दर के लिए प्रचलित विनिमय दर के लिए प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में पुनर्कथन स्वीकृत करने के लिए संशोधित नहीं की गई है। अतः, वीएसपीएल प्रस्ताव की जांच करे और सरकार की तटीय रियायत नीति का पालन करने के लिए जरूरी शोधन करे। परिणामस्वरूप, प्रपत्र 4 में राजस्व अनुमानन भी उपर्युक्त टिप्पणी के आलोक में वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली संशोधित दरों के अनुसार संशोधित किया जाए।	जैसाकि वीएसपीएल ने वार्षिक मात्राओं के मामले में पिछले 3 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण तटीय पोत प्रहस्तित नहीं किए हैं, इसलिए तटीय पोतों से आय की परिकल्पना नहीं की गई है। और इसलिए, प्रपत्र 4 में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है।  तटीय दरें सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार प्रस्तावित एसओआर में संशोधित की गई हैं।  लागू तटीय दरें विदेशी पोत प्रशुल्क के 60 प्रतिशत नहीं हैं जोकि नीति की भावना के अनुसार नहीं है।
(viii).	यह देखा गया है कि तटीय कार्गो के लिए लौह अयस्क, लौह अयस्क गुट्टिकाएं और ताप कोयला हेतु घाटशुल्क दर और स्टीवडोरिंग प्रभार विदेशी कार्गो के लिए प्रस्तावित दरों पर 60 प्रतिशत की रियायत लागू करते हुए प्रस्तावित किए गए हैं। इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमओएस की तटीय रियायत नीति के अनुसार, पीओएल उत्पादों सहित क्रूड, लौह अयस्क और ताप कोयला तटीय रियायत के लिए हकदार नहीं है। तटीय रियायत नीति के अनुसार, तटीय घाटशुल्क दर और इन मदों के लिए स्टीवडोरिंग विदेशी दर पर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/78/2018-एनएमपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए एनएमपीटी के हाल ही के प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, एनएमपीटी के स्पष्टीकरण के आधार पर, यह विदित है कि पेट कोक पेट्रोलियम उत्पादों के समकक्ष है। इसलिए, तटीय रियायत नीति के अनुसार, यह कार्गो तटीय रियायत के लिए हकदार नहीं है। अतः वीएसपीएल तटीय रियायत नीति के अनुसार जरूरी शोधन करे।	कोयला, ताप और गैर-ताप दोनों के राजस्व अनुमान के लिए, कम्पनी ने केवल पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर केवल विदेशी पोतों पर विचार किया है। हालांकि संशोधित एसओआर में, ताप कोयला से इतर कोयला दुलाई करने वाले तटीय पोतों के लिए रियायत प्रशुल्क नीति के अनुसार प्रस्तावित की गई है, राजस्व अनुमानों बदलाव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी कोयले विदेशी पोतों के लिए सुविचारित किए जाते हैं।  संशोधित प्रस्तावित एसओआर में, वीएसपीएल ने ताप कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क गुट्टिकाओं और पेट कोक के लिए तटीय रियायत का प्रस्ताव किया है।
(ix).	इसके अलावा, वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित मशीनरी के लिए घाटशुल्क दर इस मद के लिए विदेशी और तटीय कार्गो दोनों के लिए एकसमान है। यह कार्गो 40 प्रतिशत की तटीय रियायत के लिए हकदार है। प्रस्तावित दर को सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार सही किया जाए और राजस्व अनुमान भी तदनुसार शोधित किए जाएं।	संशोधित प्रस्तावित एसओआर में, वीएसपीएल ने मशीनरी के लिए तटीय रियायत का प्रस्ताव किया है।
4.	पूर्व अवधि अधिशेष	
(i).	प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 3.1.2 विनिर्दिष्ट करता है	पिछले प्रशुल्क चक्र में विश्वास किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक भौतिक

	<p>कि उन परिचालकों के मामले में जिन्होंने न्यायालयों का रूख किया था, इस दिशानिर्देशों के अधीन प्रथम प्रशुल्क निर्धारण की अवधि तक अधिशेष/ घाटा 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा जिसके नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:—</p> <p><i>" वास्तविक भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन प्रचलित प्रशुल्क निर्धारित करते समय विश्वास किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में निर्धारित प्रशुल्क वैधता अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। यदि कार्यनिष्पादन भिन्नता पूर्वानुमानों की तुलना में + अथवा – 20 प्रतिशत पाई जाती है तो प्रशुल्क भावी प्रभाव से समायोजित किया जाएगा। ऐसा करते समय पहले से प्रोद्भूत लाभ/हानि का 50 प्रतिशत प्रशुल्क संशोधित करते समय समायोजित किया जाएगा।"</i></p> <p>अतः वीएसपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के अधीन पूर्व प्रशुल्क संशोधन कार्यवाहियों में यथा किए गए पिछले प्रशुल्क चक्र में विश्वास किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन दर्शाता विवरण भेजे और ऐसे मामले में अनुमानित एआरआर से जरूरी समायोजन करे जिसमें भौतिक और वित्तीय दोनों पैरामीटरों में भिन्नता +/-20 प्रतिशत है।</p>	<p>और वित्तीय कार्यनिष्पादन दर्शाता विवरण संलग्न किया गया है। एफवाई 2017–18, 2018–19 और 2019–20 (सीमित लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर दिसंबर 2019 तक) के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों और प्रपत्रों के बीच व्यय और आय के मिलान पर विवरण भी संलग्न किया है। पूर्वानुमान दिसंबर 2019 तक 9 महीनों के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक के लिए लगाये गए हैं। भौतिक और वित्तीय दोनों पैरामीटरों में +/–20 प्रतिशत (जनवरी 2020 से मार्च 2020 पर भी विचार करते हुए) कोई भिन्नता नहीं है और प्रशुल्क चक्र के लिए रु. 631 लाख का घाटा है। 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए हम वास्तविक आंकड़े अद्यतन करेंगे जब एक बार अभिलेखों की लेखापरीक्षा हो जाए।</p>																																			
(ii).	<p>प्राधिकरण ने पैरा 16(xv)(ग) में पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश सं. टीएमपी/19/ 2017–वीएसपीएल दिनांक 19 जनवरी 2018 के दौरान, स्वयं की एचएमसी की मरम्मतों और अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाते समय, 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 2016–17 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित व्यय का अनुमान लगाने के लिए वीएसपीएल के दृष्टिकोण पर विचार किया है और वीएसपीएल के स्वामित्व वाली एचएमसी द्वारा प्रहस्तित किए जाने की उम्मीद वाले टनभार के लिए समायोजित किया था। अपने स्वयं के एचएमसी के अनुरक्षण के लिए वीएसपीएल द्वारा यथा अनुमानित मरम्मत और अनुरक्षण लागत पर विचार किया गया था और वक्त में यह कहा गया था कि वास्तविक आंकड़ों की अनुमानों से समीक्षा की जाएगी और, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन के दौरान अनुमानों पर विश्वास करने के कारण लाभ प्रोद्भूत किया गया है, इसे दिशानिर्देशों के अनुसार अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित किया जाएगा।</p> <p>अतः वीएसपीएल वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए पिछले संशोधन के दौरान सुविचारित मरम्मत और अनुरक्षण लागत के अनुमान के विपरीत वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े पिछले प्रशुल्क आदेश पर निर्णय का पालन करने के लिए क्रमशः रु. 1113.43 लाख, रु. 1145.27 लाख और रु. 1178.01 लाख पर है।</p>	<p>बार–बार खराबी और मरम्मतों के कारण नियंत्रण और व्यय से बाहर है, वीएसपीएल ने नवंबर 2018 से आगे अपनी हारबर मोबाइल क्रेनों में से एक को बन्द कर दिया है। उक्त क्रेन दिसंबर 2019 के बाद कबाड़ के रूप में बेच दी गई थी। शेष हारबर मोबाइल क्रेन के लिए महत्वपूर्ण मरम्मत और अनुरक्षण व्यय नहीं है क्योंकि इसे कम की गई क्षमता के साथ अलग किया जा रहा है। उक्त कारणों के कारण (कम हुई क्षमता के साथ अन्य क्रेन के उपयोग और एक क्रेन को बन्द करना), स्वयं की क्रेनों द्वारा प्रहस्तित मात्रा कम की गई है इससे व्यय भी पिछले दो वर्षों में कम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप किराये पर ली गई क्रेनों द्वारा मात्रा में वृद्धि हुई है और तत्संबंधी व्यय में वृद्धि हुई है।</p> <p>निम्नलिखित अनुमानित व्यय के मामले में वास्तविक व्यय के ब्योरे हैं:—</p> <table><tr><th>मरम्मत और अनुरक्षण</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th></tr><tr><td>पूर्वानुमानित</td><td>1,113.44</td><td>1,145.27</td><td>1,178.01</td></tr><tr><td>वास्तविक आंकड़े</td><td>1,076.64</td><td>1,078.39</td><td>999.35</td></tr><tr><td>अंतर</td><td>3.42%</td><td>6.20%</td><td>17.88%</td></tr></table> <p>किराये पर ली गई और स्वयं की क्रेनों द्वारा प्रहस्तित मात्राओं के ब्योरे का भी पता लगायें।</p> <table><tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">किराये पर ली गई क्रेन द्वारा मात्रा</th><th colspan="2">स्वयं की क्रेनों द्वारा मात्रा</th></tr><tr><th>मी.ट. लाखों में</th><th>%</th><th>मी.ट. लाखों में</th><th>%</th></tr><tr><td>एफवाई 2017-18</td><td>36.30</td><td>56.81</td><td>27.60</td><td>42.99</td></tr><tr><td>एफवाई 2018-19</td><td>41.32</td><td>69.20</td><td>18.39</td><td>30.80</td></tr></table>	मरम्मत और अनुरक्षण	2017-18	2018-19	2019-20	पूर्वानुमानित	1,113.44	1,145.27	1,178.01	वास्तविक आंकड़े	1,076.64	1,078.39	999.35	अंतर	3.42%	6.20%	17.88%	वर्ष	किराये पर ली गई क्रेन द्वारा मात्रा		स्वयं की क्रेनों द्वारा मात्रा		मी.ट. लाखों में	%	मी.ट. लाखों में	%	एफवाई 2017-18	36.30	56.81	27.60	42.99	एफवाई 2018-19	41.32	69.20	18.39	30.80
मरम्मत और अनुरक्षण	2017-18	2018-19	2019-20																																		
पूर्वानुमानित	1,113.44	1,145.27	1,178.01																																		
वास्तविक आंकड़े	1,076.64	1,078.39	999.35																																		
अंतर	3.42%	6.20%	17.88%																																		
वर्ष	किराये पर ली गई क्रेन द्वारा मात्रा		स्वयं की क्रेनों द्वारा मात्रा																																		
	मी.ट. लाखों में	%	मी.ट. लाखों में	%																																	
एफवाई 2017-18	36.30	56.81	27.60	42.99																																	
एफवाई 2018-19	41.32	69.20	18.39	30.80																																	

		<table><tr><td>एफयू 2019-20 (दिस.)</td><td>36.99</td><td>78.94</td><td>9.87</td><td>21.06</td></tr><tr><td></td><td>114.61</td><td></td><td>55.86</td><td></td></tr></table> <p>जैसाकि ऊपर बताया गया है, पिछले प्रशुल्क चक्र के दौरान लगाये गए अनुमानों पर विश्वास करने से कोई लाभ उपार्जित नहीं हुआ है और कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।</p>	एफयू 2019-20 (दिस.)	36.99	78.94	9.87	21.06		114.61		55.86																																																																			
एफयू 2019-20 (दिस.)	36.99	78.94	9.87	21.06																																																																										
	114.61		55.86																																																																											
(iii).	<p>पैरा 16(xx) में पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश सं. टीएमपी/19/2017-वीएसपीएल दिनांक 19 जनवरी 2018 के दौरान, “अन्य व्यय” शीर्ष के अधीन सीमाशुल्क खनन प्रभारों का अनुमान लगाते समय, वीएसपीएल ने इस व्यय के मुकाबले वर्ष 2017-18 (अगले दो वर्षों के लिए, इस मद में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गई थी) में रु. 90.18 लाख का अनुमान लगाया था इसे वीएसपीएल द्वारा प्रेषित व्ययों के ब्रेकअप के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2016-17 में शून्य बताया गया है। वीएसपीएल द्वारा किए गए निवेदनों से, यह दिखाई देता है कि ये प्रभार वर्ष 2014-15 से 2016-17 अवधि के लिए मुकदमेबाजी में हैं। वर्ष 2017-18 के लिए रु. 90.18 लाख का अनुमान अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 अवधि के लिए वीएसपीएल को जारी सीमाशुल्क मांग नोट दिनांक 22 जून 2017 के लिए रु. 47.13 लाख है। इस संबंध में, आदेश के पैरा 16(xx) में, यह उल्लेख किया गया है कि यदि, वास्तविक आंकड़ों के साथ अनुमानों की समीक्षा करते समय अगले प्रशुल्क संशोधन के समय, यह देखा गया है कि इस मद के अधीन स्वीकृत अनुमान वीएसपीएल द्वारा प्रोद्भूत नहीं किया गया है, पूर्व संशोधन में अनुमत व्यय समायोजित किया जाएगा अर्थात् मौजूदा संशोधन में खारिज किया जाएगा।</p> <p>अतः वीएसपीएल लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार सीमाशुल्क खनन प्रभारों के लिए वर्ष 2017-18 से आगे के लिए वीएसपीएल द्वारा प्रोद्भूत वास्तविक व्यय भेजे।</p>	<p>यह मामला अभी भी न्यायाधीन है। वीएसपीएल मांग की रोक के लिए न्यायालय आदेश की शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क द्वारा की गई आवधिक मांग का 50 प्रतिशत भेज रहा है। तथापि, संपूर्ण व्यय बही खातों में दिया गया है।</p> <p>सीमाशुल्क मैनिंग प्रभार:</p> <table><tr><td></td><td>2017-18</td><td>2018-19</td><td>2019-20</td></tr><tr><td>पूर्वानुमानित</td><td>90.17</td><td>91.98</td><td>93.82</td></tr><tr><td>वास्तविक</td><td>448.10</td><td>106.95</td><td>79.35</td></tr><tr><td>अंतर</td><td>396%</td><td>16.27%</td><td>-15.42%</td></tr></table> <p>निम्नलिखित सीमाशुल्क आयुक्त से प्राप्त मांग के ब्योरो और तत्संबंधी वर्षों के अधीन बुक किए गए व्यय हैं।</p> <table><tr><td>के लिए प्राप्त मांग</td><td>कुल राशि</td><td>2017-18</td><td>2018-19</td><td>2019-20</td></tr><tr><td>जनवरी 2012 से जून 2014</td><td>137.77</td><td>137.77</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>जुलाई 2014 से सितंबर 2017</td><td>263.21</td><td>263.21</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>अक्टूबर 2017 से मार्च 2018</td><td>47.13</td><td>47.13</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>अप्रैल से जून 2018</td><td>29.86</td><td>-</td><td>29.86</td><td>-</td></tr><tr><td>जुलाई से सितंबर 2018</td><td>25.18</td><td>-</td><td>25.18</td><td>-</td></tr><tr><td>अक्टूबर से दिसंबर 2018</td><td>26.21</td><td>-</td><td>26.21</td><td>-</td></tr><tr><td>जनवरी से मार्च 2019</td><td>25.69</td><td>-</td><td>25.69</td><td>-</td></tr><tr><td>अप्रैल से जून 2019</td><td>26.93</td><td>-</td><td>-</td><td>26.93</td></tr><tr><td>जुलाई से सितंबर 2019</td><td>26.21</td><td>-</td><td>-</td><td>26.21</td></tr><tr><td>अक्टूबर से दिसंबर 2019</td><td>26.21</td><td>-</td><td>-</td><td>26.21</td></tr><tr><td></td><td>634.39</td><td>448.10</td><td>106.95</td><td>79.35</td></tr></table>		2017-18	2018-19	2019-20	पूर्वानुमानित	90.17	91.98	93.82	वास्तविक	448.10	106.95	79.35	अंतर	396%	16.27%	-15.42%	के लिए प्राप्त मांग	कुल राशि	2017-18	2018-19	2019-20	जनवरी 2012 से जून 2014	137.77	137.77	-	-	जुलाई 2014 से सितंबर 2017	263.21	263.21	-	-	अक्टूबर 2017 से मार्च 2018	47.13	47.13	-	-	अप्रैल से जून 2018	29.86	-	29.86	-	जुलाई से सितंबर 2018	25.18	-	25.18	-	अक्टूबर से दिसंबर 2018	26.21	-	26.21	-	जनवरी से मार्च 2019	25.69	-	25.69	-	अप्रैल से जून 2019	26.93	-	-	26.93	जुलाई से सितंबर 2019	26.21	-	-	26.21	अक्टूबर से दिसंबर 2019	26.21	-	-	26.21		634.39	448.10	106.95	79.35
	2017-18	2018-19	2019-20																																																																											
पूर्वानुमानित	90.17	91.98	93.82																																																																											
वास्तविक	448.10	106.95	79.35																																																																											
अंतर	396%	16.27%	-15.42%																																																																											
के लिए प्राप्त मांग	कुल राशि	2017-18	2018-19	2019-20																																																																										
जनवरी 2012 से जून 2014	137.77	137.77	-	-																																																																										
जुलाई 2014 से सितंबर 2017	263.21	263.21	-	-																																																																										
अक्टूबर 2017 से मार्च 2018	47.13	47.13	-	-																																																																										
अप्रैल से जून 2018	29.86	-	29.86	-																																																																										
जुलाई से सितंबर 2018	25.18	-	25.18	-																																																																										
अक्टूबर से दिसंबर 2018	26.21	-	26.21	-																																																																										
जनवरी से मार्च 2019	25.69	-	25.69	-																																																																										
अप्रैल से जून 2019	26.93	-	-	26.93																																																																										
जुलाई से सितंबर 2019	26.21	-	-	26.21																																																																										
अक्टूबर से दिसंबर 2019	26.21	-	-	26.21																																																																										
	634.39	448.10	106.95	79.35																																																																										

5.	प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 1.9 के अनुसार, बीओटी परिचालक संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ किए गए मौजूदा रियायत करार में दिए गए प्राक्धानों द्वारा बाध्य जारी रहेगा। समानान्तरतः, बीओटी परिचालक इन दिशानिर्देशों से बाध्य होगा, संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ पृथक करार द्वारा। वीएसपीएल और वीपीटी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित वीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को एमओएस पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी (पीटी-IV) दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा एमओएस द्वारा अग्रेषित निर्धारित प्रारूप के अनुसार पृथक करार की प्रति भेजे।	हमने वीपीटी से अनुरोध किया है। वीएसपीएल आने वाले समय में प्रस्तुत कर देगा। तथापि, वीएसपीएल वीपीटी को पहले ही पुष्टि कर चुका है कि वीएसपीएल अपने प्रश्न के जवाब में प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अधीन 1.4. 2020 से प्रशुल्क संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने को स्वीकार करता है। (प्रतिलिपि संलग्न)।  तत्पश्चात, वीएसपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 6 अप्रैल 2020 द्वारा वीएसपीएल द्वारा हस्ताक्षरित करार की प्रति भेजी थी।  [करार पर वीपीटी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाने हैं जोकि अभी भेजा जाना है।]
----	---	--

8. हमारे पत्र दिनांक 3 मार्च 2020 द्वारा वीपीटी से भी यह अनुरोध किया गया था कि कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण 10 मार्च 2020 तक भेजे जाएं। वीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 18 मार्च 2020 द्वारा अपना उत्तर भेजा था। हमारे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण और वीपीटी द्वारा प्रेषित तदनुसूची उत्तर नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	वीपीटी द्वारा प्रेषित उत्तर																							
(i).	वीएसपीएल द्वारा अपने प्रपत्र-1 में यथा प्रेषित एआरआर के परिकलन पर टिप्पणियां भेजें।	<p>वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वीएसपीएल द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी और इसकी स्वीकार्यता निम्नवत् है:-</p> <table><tr><th></th><th>भुगतान की गई रॉयल्टी</th><th>स्वीकार्यता</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>रु. 693.96</td><td>रु. 519.57</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>रु. 791.82</td><td>रु. 592.84</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>रु. 876.35</td><td>रु. 656.12</td></tr></table> <p>2019-20 के लिए वृद्धि कारक 4.26 प्रतिशत है परंतु प्रपत्र-1 के क्र.सं. 10 द्वारा यथा सुविचारित 3.45 प्रतिशत नहीं है।</p>		भुगतान की गई रॉयल्टी	स्वीकार्यता	2016-17	रु. 693.96	रु. 519.57	2017-18	रु. 791.82	रु. 592.84	2018-19	रु. 876.35	रु. 656.12											
	भुगतान की गई रॉयल्टी	स्वीकार्यता																							
2016-17	रु. 693.96	रु. 519.57																							
2017-18	रु. 791.82	रु. 592.84																							
2018-19	रु. 876.35	रु. 656.12																							
(ii).	<p>प्रपत्र-4 में, वीएसपीएल ने नीचे दिए गए अनुसार और राजस्व अनुमानन के लिए 68,43,271 टीईयू औसत यातायात के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वास्तविक यातायात दर्शाया था। वीपीटी उक्त वर्षों के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित वास्तविक यातायात और राजस्व अनुमानन में वीएसपीएल द्वारा सुविचारित 68,43,271 टीईयू के औसत यातायात की पुष्टि करे।</p> <table><tr><th colspan="3">वास्तविक यातायात टीईयू में</th><th rowspan="2">औसत</th></tr><tr><th>वर्ष1 (2016-17)</th><th>वर्ष2 (2017-18)</th><th>वर्ष3 (2018-19)</th></tr><tr><td>63,24,345</td><td>71,55,969</td><td>70,89,500</td><td>68,43,271</td></tr></table>	वास्तविक यातायात टीईयू में			औसत	वर्ष1 (2016-17)	वर्ष2 (2017-18)	वर्ष3 (2018-19)	63,24,345	71,55,969	70,89,500	68,43,271	<p>वीएसपीएल द्वारा 2016-17 से 2018-19 तक प्रहस्तित वास्तविक यातायात (मीट्रिक टनों में) निम्नवत् है:-</p> <table><tr><th></th><th>यातायात</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>6362933</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>7092286</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>7102977</td></tr><tr><td>कुल</td><td>20558196</td></tr><tr><td>औसत</td><td>6852732</td></tr></table> <p>वीएसपीएल द्वारा उल्लिखित यातायात का औसत 68,56,605 परिगणित होता है परंतु 68,43,271 नहीं।</p>		यातायात	2016-17	6362933	2017-18	7092286	2018-19	7102977	कुल	20558196	औसत	6852732
वास्तविक यातायात टीईयू में			औसत																						
वर्ष1 (2016-17)	वर्ष2 (2017-18)	वर्ष3 (2018-19)																							
63,24,345	71,55,969	70,89,500	68,43,271																						
	यातायात																								
2016-17	6362933																								
2017-18	7092286																								
2018-19	7102977																								
कुल	20558196																								
औसत	6852732																								
(iii).	वीएसपीएल द्वारा अपने प्रपत्र-4 में यथा प्रेषित प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर राजस्व के अनुमानन पर अपनी टिप्पणियां भी भेजें।	कोई टिप्पणी नहीं करनी है।																							

(iv).	आईएनडी एस के अधीन वीएसपीएल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए पट्टा किराया क्रमशः रु. 478.88 लाख, रु. 251.55 लाख और रु. 544.00 लाख प्रतिवेदित करते हैं। प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.3.2 के अनुसार, यदि आईएनडी एस और आईजीएपी के अधीन प्रतिवेदित व्यय में भिन्नता पाई जाती है तो आईजीएपी के अनुसार आंकड़ों पर विचार करते हुए और आईएनडी एस को छोड़ते हुए एआरआर परिकलन में जरूरी समायोजन किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में, वीपीटी से अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 से 2018/19 के लिए इस संबंध में वीएसपीएल द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराया भेजे और यह भी पुष्टि करें कि यह लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार है।	वर्ष 2016-17 से 2018/19 के लिए वीएसपीएल द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक पट्टा किराये निम्नवत् हैं:- <table><tr><th></th><th>भुगतान किया गया वास्तविक पट्टा किराया</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>रु. 493.38 लाख</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>रु. 375.43 लाख</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>रु. 625.02 लाख</td></tr></table>		भुगतान किया गया वास्तविक पट्टा किराया	2016-17	रु. 493.38 लाख	2017-18	रु. 375.43 लाख	2018-19	रु. 625.02 लाख
	भुगतान किया गया वास्तविक पट्टा किराया									
2016-17	रु. 493.38 लाख									
2017-18	रु. 375.43 लाख									
2018-19	रु. 625.02 लाख									
		उपर्युक्त राशियों में रु. 25.10 करोड़ के विवादित किराये शामिल नहीं हैं।								
(v).	प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 1.9 क अनुसार, बीओटी परिचालक संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ किए गए मौजूदा रियायत करार में दिए गए प्रावधानों द्वारा बाध्य रहेगा। समानान्तरतः, बीओटी परिचालक संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ पृथक करार द्वारा इस दिशानिर्देश द्वारा बाध्य होना जारी रहेगा। वीपीटी वीएसपीएल और वीपीटी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित वीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को पत्र सं. पीआर-140/20/2009-पीजी (पीटी-IV) दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा एमओएस द्वारा अग्रेषित निर्धारित प्रारूप के अनुसार पृथक करार की प्रति भेजे।	प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 क अधीन कोई ऐसा पृथक करार वीएसपीएल द्वारा आज तक नहीं किया गया है।								

9.1. पूर्व अनुच्छेद में दिए गए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजते समय, वीएसपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा संशोधित प्रस्ताव भेजा था जिसमें संशोधित प्रपत्र-1 (एआरआर) और संशोधित प्रपत्र-4 (राजस्व अनुमानन) शामिल किया गया है।

(i). वीएसपीएल द्वारा प्रेषित संशोधित एआरआर परिकलन की सार स्थिति नीचे तालिकाबद्ध की गई है:

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	विवरण		वर्ष1 (2016-17)	वर्ष2 (2017-18)	वर्ष3 (2018-19)
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	टिप्पणी 1			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)		11,438.27	13,641.12	14,793.96
(ii).	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)		3,124.96	2,511.19	2,187.39
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)		14,563.23	16,152.31	16,981.35
(2).	ऐसी मदों के मामले में समायोजन जहां आईएनडीएस (लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार) और आईजीएपी के अनुसार प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता हो	प्रपत्र 6क और टिप्पणी 2			
(i).	मूल्यहास		152.03	150.85	143.33
(ii).	सूचीबद्ध की जाने वाली अन्य व्यय मदें, यदि कोई हों		(703.37)	(490.69)	(341.20)
	समायोजनों का जोड़ 2=(i)+(ii)		(551.34)	(339.84)	(197.87)
(3).	समायोजन घटायें:				
(i).	पत्तन को भुगतान की गई वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी		693.96	791.82	876.35

क्र.सं.	विवरण		वाई1 (2016-17)	वाई2 (2017-18)	वाई3 (2018-19)
(ii).	ऋणों पर ब्याज		3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	अशोध और आशंकित ऋणों के लिए प्रावधान		8.22	80.62	31.03
(iv).	धीमे चलने वाली वस्तुसूची के लिए प्रावधान		-	-	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हों		-	-	-
	3 का जोड़ = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]		3,777.37	3,358.59	3,072.60
(4).	जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के अनुसार स्वीकार्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	प्रपत्र 2 और टिप्पणी 3	519.57	592.84	656.12
(5).	कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (5=1+2-3)		10,754.09	13,046.72	14,367.00
(6).	क्र.सं. 5 के औसत व्यय = [वाई1+वाई2+वाई3]/3		12,722.60		
(7).	नियोजित पूंजी				
	(i). बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथवा वाई3 के 31 दिसंबर को सकल अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) (आईजीएपी के अनुसार)		34,749.18		
	(ii). जोड़ें: बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथवा वाई3 के 31 दिसंबर को प्रगतिधीन केपिटल वर्क (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)		6.73		
	(iii). जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्किंग केपिटल	प्रपत्र 3 और टिप्पणी 4 के अनुसार	1,717.02		
	(क). वस्तुसूची		-		
	(ख). विविध देनदार		-		
	(ग). रोकड़		-		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़		-		
	(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)+(iii)]		36,472.94		
(8).	क्र.सं.7(iv) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाम		5,835.67		
(9).	31 मार्च वाई3 अथवा यथा लागू वाई3 के 31 दिसंबर को वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)		18,558.27		
	[(6)+(8)]				
(10).	उदाहरण के लिए वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन, यदि वाई वाई4 2019-20 हो, तो लागू डब्ल्यूपीआई 4.26 प्रतिशत है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर (9) x 1.0345 होगा।		19,348.86		
(11).	ऊपर क्र.सं. 10 में यथा दिया गया अधिकतम सूचकांकित एआरआर		19,348.86		
(12).	ऊपर क्र.सं. 11 पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित एसओआर पर राजस्व अनुमानन	प्रपत्र 4 और टिप्पणी 5 के अनुसार	17,356.00		

- (ii). वीएसपीएल ने वर्ष वाई1, वाई2 और वाई3 के दौरान बीओटी परिचालक द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात की औसत के लिए प्रपत्र 4 में प्रस्तावित प्रशुल्क एवं मौजूदा प्रशुल्क के लिए राजस्व अनुमानन की गणना भेजी है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर अनुमानित कुल राजस्व रु. 17,356/- लाख है।
- 9.2. वीएसपीएल ने प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रपत्र सं. 1, 2, 3, 4, 6क, 6ख और 7 भी भेजा है।
10. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।
11. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है—
- (i). विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) का दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए आदेश सं. टीएमपी/19/2017-वीएसपीएल दिनांक 19 जनवरी 2018 द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें लागत जमा मूल्यनिर्धारण माडल विनिर्दिष्ट किया गया था और संशोधित एसओआर 26 फरवरी 2018 को राजपत्र सं. 78 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात, इस प्राधिकरण ने वीएसपीएल द्वारा दाखिल किए गए समीक्षा आवेदन का निपटान करते हुए एक आदेश सं. टीएमपी/24/2018-वीएसपीएल दिनांक 03 अक्टूबर 2018 पारित किया गया था। एसओआर की वैधता 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की गई थी।
- (ii). पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन नीति निदेश के रूप में, बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 जारी किए थे जोकि पहले 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित किए जाते थे। प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के जारी होने के परिणामस्वरूप, एमओएस द्वारा, वीएसपीएल के मामले में प्रशुल्क निर्धारण कार्यवाही प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को लागू करने के लिए जारी वर्किंग दिशानिर्देशों में किए गए विनिर्दिष्टों द्वारा शासित की जाती है।
- वीएसपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 और वर्किंग दिशानिर्देश 2019 के अधीन अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी 2020 दाखिल किया था। वीएसपीएल ने हमारे द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण के साथ संशोधित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर), मसौदा एसओआर और राजस्व के संशोधित अनुमान अपने ईमेल दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा भेजे थे। मामले की कार्यवाही के दौरान वीएसपीएल, पत्तन और सेल द्वारा किए गए निवेदनों के साथ वीएसपीएल द्वारा अपने ईमेल दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा दाखिल अंतिम संशोधित प्रस्ताव पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित संशोधित लागत विवरण और संशोधित राजस्व अनुमान प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है।
- (iii). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.1 प्रत्येक बीओटी परिचालक से अपेक्षा करता है कि एआरआर का मूल्यांकन किया जाए जोकि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 और इस प्राधिकरण द्वारा जारी वर्किंग दिशानिर्देशों और प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित 31 मार्च वाई3 को लिए गए नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिशत की दर से प्रतिलाभ के अधीन प्रस्ताव जमा किए जाने के समय तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों (वाई1), (वाई2) और (वाई3) के अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय के जोड़ का औसत है।
- (ख). वीएसपीएल ने प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित तीन वर्षों अर्थात् 2016-17 (वाई1), 2017-18 (वाई 2) और 2018 (वाई3) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर मूल्यांकन किया था। एआरआर का मूल्यांकन करते समय, वीएसपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में यथा निर्धारित वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए औसत वार्षिक व्ययों पर पहुंचने के लिए एआरआर परिकलन में अस्वीकार्य व्ययों को शामिल नहीं किया है। वीएसपीएल द्वारा अनुमानित एआरआर सही पाया गया है और इसलिए निम्नलिखित अनुच्छेद में स्पष्ट किए गए कारणों से कुछ संशोधनों के सिवाय मामले की कार्यवाही के दौरान प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर विचार किया गया है।
- (i). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.2, साथ-साथ, विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामलों में बीओटी परिचालक द्वारा भूस्वामी पत्तन को देय रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी को प्रशुल्क परिकलन में लिया जाएगा जिनमें 29 जुलाई 2003 से पहले बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था, इसे एआरआर परिकलन में अगले उच्चतम बोलीदाता की सीमा तक लेखा में लिया जाएगा।
- तदनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान, तदनुकूपी अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यथा प्रदर्शित राजस्व हिस्सेदारी क्रमशः रु. 693.96 लाख, रु. 791.82 लाख और रु. 876.35 लाख को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि वीएसपीएल के मामले में बोली लगाने की प्रक्रिया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, इसलिए अगले उच्चतम बोलीदाता की सीमा अर्थात् 12.81 प्रतिशत तक राजस्व हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान एआरआर परिकलन में क्रमशः रु.519.57 लाख, 592.84 लाख और रु. 656.12 लाख सुविचारित किया गया है। यह 2019 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के अनुसार है।
- (ii). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.3.1 (ii) के अनुसार, ऋणों पर ब्याज, अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान, धीमी चलने वाली मालसूची आदि के लिए प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं।
- तदनुसार, वीएसपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में ऋणों पर ब्याज क्रमशः रु. 3075.19 लाख, रु. 2486.14 लाख और रु. 2165.22 लाख, रु. 8.22 लाख, रु. 80.62 लाख और रु. 31.03 लाख को शामिल नहीं किया है।

वीएसपीएल द्वारा एआरआर परिकलन में वर्ष 2016-17 के लिए रु. 27.56 लाख की सीमा तक अन्यो पर ब्याज को लिया गया है। वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि अन्यो पर ब्याज में मध्यस्थ के अधिनियम के अनुसार विभिन्न रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर वीपीटी को भुगतान किए गए रु. 22.67 लाख शामिल हैं और रु. 4.89 लाख अपात्र इनपुट ऋणों पर सेवा कर विभाग को किए गए ब्याज भुगतानों के लेखा पर है। चूंकि वीएसपीएल द्वारा किए गए ये ब्याज भुगतान दंडात्मक प्रकृति के हैं जिन्हें हमारे द्वारा एआरआर परिकलन में शामिल नहीं किया गया है ताकि वीएसपीएल की चूक के लिए उपयोक्ताओं पर बोझ न पड़े।

- (iii). खंड 2.3.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि यदि आईएनडी एस और आईजीएपी (जैसे मूल्यहास) के अधीन प्रतिवेदित व्यय में भिन्नता होती है तो आईजीएपी के अनुसार आंकड़ों पर विचार करते हुए और आईएनडी एस आंकड़ों को शामिल नहीं करते हुए एआरआर परिकलन में जरूरी समायोजन किए जाएंगे। वीएसपीएल के लेखापरीक्षित लेखे आईएनडी एस शिकायत हैं। वीएसपीएल ने दिशानिर्देशों की स्थिति का अनुपालन करने के लिए आईजीएपी के अनुसार इन मदों को लेने के लिए एआरआर परिकलन में शामिल नहीं दर्शाते हुए क्रमशः वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आईएनडी एस से आईजीएपी परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान, पट्टा किराया, उपदान, अन्य वित्त प्रभार, विकास कल लागत, पुनर्स्थापन लागत के लिए “अन्य व्यय” शीर्षक के अधीन मूल्यहास में जरूरी समायोजन किया है। इसके अलावा, वीएसपीएल ने पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दिए गए एआरआर परिकलन के प्रयोजन के लिए आईएनडी एस से आईजीएपी को अधीन प्रतिवेदित लेखापरीक्षित आंकड़ों से इसके द्वारा किए गए समायोजन स्पष्ट किए हैं। वीएसपीएल ने प्रपत्र 6क में अपेक्षित गणनाएं भेजी हैं जिसे प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है और इसपर विश्वास किया गया है।

विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित, वीएसपीएल द्वारा यथा प्रेषित वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए पट्टा किराया पर विचार किया गया है।

- (ग). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.1 में निर्धारित प्रावधानों और वर्किंग दिशानिर्देशों तथा ऊपर चर्चा किए गए समायोजनों के आधार पर, वीएसपीएल वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए रु. 127.13 करोड़ के औसत व्ययों पर पहुंचा है। हमारी गणना के अनुसार संशोधित औसत व्यय ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार वर्ष 2016-17 में किए गए एक संशोधन के लेखा पर रु. 127.13 करोड़ होता है।

- (iv). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.5 के अनुसार, नियोजित पूंजी में सकल अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) (भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (आईजीएपी) के अनुसार) जमा निर्धारित मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों और कार्यगत पूंजी में आईएनडी एस के अधीन प्रतिवेदित आंकड़ों से पुनः शुरू किए जाने वाले वर्ष वार्ड 3 के 31 मार्च/31 दिसंबर को कार्य पूंजी शामिल है। वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे आईएनडी एस के अधीन रु. 298.65 करोड़ की सकल अचल टेन्नीबल परिसंपत्तियां रिपोर्ट करते हैं। वीएसपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.5 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार आईजीएपी के अनुसार रु. 347.49 करोड़ की सकल अचल परिसंपत्तियों पर विचार किया है। वीएसपीएल ने प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित आईजीएपी के अनुसार सकल अचल परिसंपत्तियां का परिकलन देते हुए निर्धारित प्रपत्र 7 भेजा है। सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित आईजीएपी के अनुसार वीएसपीएल द्वारा सुविचारित 2018-19 को सकल अचल परिसंपत्तियों पर विश्वास किया गया है और विचार किया गया है।

वीएसपीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यथा दर्शाये गए अनुसार प्रगतिधीन पूंजी रु. 6.73 पर विचार किया है।

- (ख). कार्य पूंजी में प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 के अनुसार, वस्तुसूची, विविध देनदार और रोकड़ शेषजमा शामिल हैं। कार्य पूंजी के परिकलन के लिए निर्धारित मानदंड ईंधनों के अलावा भंडारों के छह माह के औसत उपभोग पर वस्तुसूची की अन्य मदों और केपिटल पुर्जों के लिए वस्तुसूची के एक वर्ष के औसत उपभोग तक सीमित किया गया है। वीएसपीएल ने केपिटल पुर्जों का वार्षिक उपभोग रु. 458.00 लाख बताया है। तथापि, कार्य पूंजी के परिकलन के लिए, वीएसपीएल ने रु. 399.96 लाख की केपिटल पुर्जों की क्लोजिंग वस्तुसूची पर विचार किया है। यह निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं है। अतः, यह मद संशोधित की गई है और रु. 458.00 लाख पर केपिटल पुर्जों के एक वर्ष के औसत उपभोग घटा ईंधन रु. 8.13 लाख अर्थात् रु. 449.87 लाख पर विचार किया है।

रोकड़ शेषजमा को प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिकलित किया देखा गया है।

प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को परिचालित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के साथ पठित प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 के अनुसार, सांविधिक बाध्यताओं से आने वाले भूस्वामी पत्तन को पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान कार्य पूंजी के परिकलन के लिए विविध देनदार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। वीएसपीएल ने अपने संशोधित प्रस्ताव में वर्ष 2018-19 में वीपीटी को इसके द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम पट्टा किराये का 50 प्रतिशत होते हुए कार्य पूंजी परिकलन में रु. 253.31 लाख को लिया है। वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस करार दिनांक 28 नवंबर 2001 के खंड 5.2 के अनुसार, वीएसपीएल ने क्रमशः करार दिनांक 29 जुलाई 2005 और दिनांक 29 जुलाई 2015 द्वारा एक्जिम पार्क में भूमि के लिए टर्मिनल के पट्टे के लिए वीपीटी के साथ पट्टा करार किया था। दोनों पट्टा करारों के अनुसार, वीएसपीएल से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप में पट्टा किराये की अदायगी करे।



वर्ष 2018-19 के लिए वीएसपीएल द्वारा वीपीटी को भुगतान किए गए शुल्क रु. 506.62 लाख बताये गए हैं। उसका 50 प्रतिशत रु. 253.31 लाख होता है जोकि कार्य पूंजी के परिकलन में वीएसपीएल द्वारा सुविचारित किया गया है। यह दिशानिर्देश स्थिति और अनुसरित सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार पाया गया है जहां प्रत्येक वर्ष लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जाता है।

(ग). ऊपर स्पष्ट किए गए संशोधनों के अधीन, वीएसपीएल द्वारा परिगणित कुल नियोजित पूंजी रु. 364.73 करोड़ के स्थान पर संशोधित नियोजित पूंजी रु. 365.23 करोड़ परिगणित होती है। वीएसपीएल द्वारा सुविचारित नियोजित पूंजी पर प्रतिलाम (आरओसीई) 16 प्रतिशत की दर से रु. 58.36 करोड़ है। संशोधित आरओसीई संशोधित नियोजित पूंजी के आधार पर रु. 58.44 करोड़ परिगणित होता है।

(व). एआरआर में तीन वित्तीय वर्षों 2016-17 से 2018-19 के लिए व्यय की औसत और 16 प्रतिशत आरओसीई शामिल है। वीएसपीएल द्वारा निर्धारित एआरआर रु. 185.58 करोड़ (रु. 127.22 करोड़ + रु. 58.36 करोड़) है। हमारे द्वारा परिगणित संशोधित एआरआर रु. 185.57 करोड़ (रु. 127.13 करोड़ + रु. 58.44 करोड़) है। इसके अलावा, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.8 के अनुसार, उक्त एआरआर को वर्ष 2019-20 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से सूचकांकित किए जाने की जरूरी है जोकि 4.26 प्रतिशत है। 4.26 प्रतिशत लागू करते हुए वीएसपीएल द्वारा मूल्यांकित सूचकांकित अधिकतम एआरआर रु. 193.49 करोड़ है। हमारे द्वारा किए गए संशोधित एआरआर परिकलन के अनुसार, संशोधित सूचकांकित एआरआर वर्ष 2019-20 (रु. 185.57 \* करोड़ 1.0426) के लिए रु. 193.48 करोड़ परिगणित होता है। इसमें पूर्व अवधि समायोजन शामिल नहीं किया गया है। पूर्व अवधि से संबंधित विश्लेषण अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है।

वीएसपीएल द्वारा प्रेषित एआरआर गणना की अंतिम विस्तृत गणना जिसे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है, पर विश्वास किया गया है। यह ऊपर स्पष्ट किए गए मामूली संशोधन के अधीन है। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित विस्तृत एआरआर गणना और हमारे द्वारा संशोधित एआरआर क्रमशः **अनुलग्नक- I (क) और (ख)** के रूप में संलग्न किया गया है।

(vi). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 3.1.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि बीओटी परिचालकों के मामले में जो इस प्राधिकरण के पिछले आदेश के खिलाफ न्यायालय नहीं गए थे, 2019 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन प्रशुल्क के प्रथम निर्धारण के दौरान प्रशुल्क निर्धारण की अवधि तक पूर्व अवधि के लिए अधिशेष/घाटा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के खंड 2.13 के अनुसार किया गया था।

पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित अनुमान वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए है। इसलिए, इन तीन वर्षों के लिए वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष अनुमानों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। वीएसपीएल ने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर पूर्व अवधि 2017-18 और 2018-19 के लिए लागत विवरण भेजा है। वर्ष 2019-20 अभी भी खत्म नहीं हुआ है और लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः वीएसपीएल ने वर्ष 2019-20 के लिए अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक नौ महीनों के वास्तविक आंकड़ों और वर्ष 2019-20 के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित अनुमानों के साथ वास्तविक आंकड़ों के तुलना प्रयोजन के लिए जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक तीन महीनों के लिए अनुमानों पर विचार किया है। वीएसपीएल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित व्यय के मिलान विवरण भेज है और वर्ष 2019-20 के लिए अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक नौ महीनों के वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया गया है और लागत विवरण में व्यय पर विचार किया गया है। तथापि, वर्ष 2019-20 अभी खत्म हुआ ही है, इस वर्ष के लेखापरीक्षित लेख उपलब्ध नहीं हैं। अतः, यह प्राधिकरण पूर्व अवधि विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, वीएसपीएल द्वारा अनुसरित दृष्टिकोण के आधार पर आगे जाता है, परंतु 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अगले प्रशुल्क चक्र के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के दौरान समीक्षा की जाएगी।

वीएसपीएल द्वारा प्रेषित मिलान विवरण के आधार पर, पूर्व अवधि विवरण में वीएसपीएल द्वारा सुविचारित आंकड़े अनुवर्ती अनुच्छेदों में यथा स्पष्ट किए गए कुछ संशोधनों के अधीन विश्लेषण में सुविचारित किए गए हैं। तथापि, वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों की वीएसपीएल के अगले प्रशुल्क संशोधन के दौरान वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

(vii). विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(क). 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान वीएसपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात प्रशुल्क आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 और समीक्षा आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2018 में अनुमानित कुल रु. 189.73 लाख टन के लिए क्रमशः तदनुरूपी अवधि के लिए 62.00, 63.24 और 64.49 लाख टन के अनुमानित यातायात के विपरीत क्रमशः 71.16, 70.90 और 71.93 लाख टन कुल 213.98 लाख टन है।

वीपीटी ने वीएसपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात 63.63, 70.92 और 71.03 लाख टन और कुल यातायात 205.58 लाख टन बताया है। वीपीटी द्वारा प्रेषित यातायात आंकड़े वीएसपीएल द्वारा प्रतिवेदित वास्तविक यातायात की अपेक्षा कम हैं। यातायात आंकड़ों में अंतर वीपीटी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः, इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, वीएसपीएल द्वारा प्रेषित वास्तविक यातायात आंकड़े सुविचारित किए गए हैं।

भौतिक कार्यानिष्पादन में भिन्नता 12.78 प्रतिशत सकारात्मक है और जोकि +/-20 प्रतिशत से कम पाया गया है।

(ख). वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित आय अनुमान आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से वास्तविक आय से इस तरह तुलना के लिए प्रशुल्क आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 और समीक्षा आदेश दिनांक 03 अक्टूबर 2018 में प्रदत्त प्रशुल्क वृद्धि के प्रभाव को देखने के लिए समायोजित किए गए हैं।

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 जून 2015 द्वारा संप्रेषित भारत के महाधिवक्ता की राय यह है कि परिचालक द्वारा अपने लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अर्जित वास्तविक आय पर विचार किया जाना चाहिए और कोई कल्पित आय नहीं होनी चाहिए। अतः, पूर्व अवधि के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों

में यथा प्रतिवेदित वास्तविक आय और मिलान विवरणों के साथ वीएसपीएल द्वारा यथा भेजे गए वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों/अनुमानों पर विचार किया गया है।

मिलान विवरण से यह देखा गया है कि वीएसपीएल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित वास्तविक राजस्व और वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों/अनुमानों से रु. 945.79 लाख, रु. 609.28 लाख और रु. 470.47 लाख कम किया गया है। यह अलग किया जाना आंतरिक सड़कों की सफाई तथा रैक सफाई द्वारा इकट्ठा किए गए कार्गो से कबाड़ बिक्री और ईपीसीजी के अधीन प्राप्त आय के लिए है। चूंकि ये आय टर्मिनल के लेखा पर वीएसपीएल को प्रोद्भूत हुई है, इसलिए इन मदों को हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में एफएमआई के अधीन लिया गया है।

(ग). पिछले संशोधन के दौरान तैयार किए गए लागत विवरण में मूल्यहास के अनुमान आईजीएएपी पर आधारित है। वर्ष 2016-17 से, वीएसपीएल ने लेखांकन की आईएनडी एसस पद्धति का अनुसरण किया है। इसकी तुलना करने के लिए, वीएसपीएल ने आईजीएएपी के अधीन मूल्यहास आंकड़ों पर विचार किया है और इसका आईएनडी एसस आंकड़ों से मिलान किया है। वीएसपीएल द्वारा यथा सुविचारित मूल्यहास आंकड़ों पर विश्वास किया गया है और विचार किया गया है।

(घ). वीएसपीएल ने पिछली अवधि के लागत विवरण में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए क्रमशः रु. 248.29 लाख, रु. 538.55 लाख और रु. 502.15 लाख के पट्टा किराये पर विचार किया है। जब वीपीटी ने वीएसपीएल द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराये पर सूचना मांगी थी तो पतन ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए रु. 375.43 लाख और रु. 625.02 लाख का वास्तविक पट्टा किराया दर्शाया था। वीपीटी ने वर्ष 2019-20 के लिए आंकड़े नहीं भेजे हैं।

पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान सुविचारित वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए अनुमान वीएसपीएल द्वारा अनुसरित आईजीएएपी के अनुसार तत्कालीन लेखांकन पद्धति पर आधारित था। वीएसपीएल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए पूर्व अवधि हेतु लागत विवरण में सुविचारित आईएनडी एसस से आईजीएएपी आंकड़ों के अधीन वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित पट्टा किराये का मिलान भेजा है और इस संबंध में किया गया समायोजन प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा प्रपत्र 7 में विधिवत् प्रमाणित किया गया है और इसलिए इसपर विचार किया गया है।

(ङ). मिलान विवरण से यह देखा गया है कि वीएसपीएल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के पूर्व अवधि लागत विवरण को तैयार करते समय वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधानों को अलग नहीं रखा गया है। तथापि, वीएसपीएल ने प्रपत्र 1 में एआरआर परिकलन में इस संबंध में जरूरी समायोजन किया था। इसलिए, हमारे द्वारा तैयार किया गया पूर्व अवधि हेतु लागत विवरण में, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, वीपीटी ने आईएनडी एसस से आईजीएएपी तक उपदान भुगतान के संबंध में जरूरी समायोजन नहीं किया है जबकि इसने एआरआर के परिकलन में इसे शामिल नहीं किए जाने के लिए जरूरी समायोजन किया है। इसलिए, पूर्व अवधि लागत विवरण में समान समायोजन किया गया है।

(च). इसके अलावा, वीएसपीएल ने, व्यय साइड में स्क्रेप वस्तुसूची की खरीद के लिए रु. 144.19 लाख कम किया है। चूंकि कार्गो की सफाई से स्क्रेप की बिक्री से अंतर्संबंधित आय हमारे द्वारा पूर्व अवधि के लिए एफएमआई के अधीन सुविचारित किया गया है, इसलिए व्यय की तदनुरूपी प्रकृति हमारे द्वारा तैयार की गई पूर्व अवधि के लागत विवरण में ली गई है।

(छ). वीएसपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लिए वीपीटी को भुगतान की गई स्वीकार्य राजस्व हिस्सेदारी पर विचार किया है।

(ज). इस प्राधिकरण द्वारा अनुसरित सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2019-20 के प्रत्येक वर्ष के लिए वीएसपीएल द्वारा ऋणों पर ब्याज को भी शामिल नहीं किया गया है।

(झ). तत्समय लागू 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अधीन पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान सुविचारित नियोजित पूंजी निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवल अचल परिसंपत्तियां + कार्य पूंजी है। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित निवल अचल परिसंपत्तियां आईएनडी एसस पर आधारित है। वीएसपीएल ने आरओसीई के परिकलन के प्रयोजन के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए रु. 16,953.29 लाख, रु. 14,965.08 लाख और रु. 13,414.52 लाख की नियोजित पूंजी पर विचार किया है।

प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित वीएसपीएल द्वारा यथा प्रेषित आईजीएएपी के अधीन निवल अचल परिसंपत्तियां वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए क्रमशः रु. 18,398.11 लाख, रु. 16,906.02 लाख और रु. 15,281.49 लाख है। पूर्व अवधि के लिए नियोजित पूंजी के परिकलन में वीएसपीएल द्वारा सुविचारित निवल अचल परिसंपत्तियां प्रपत्र 7 से मेल नहीं खाती हैं जिसे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है। चूंकि प्रपत्र 7 में वीएसपीएल द्वारा प्रेषित आईजीएएपी के अधीन निवल अचल परिसंपत्तियां प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है, इसलिए पूर्व अवधि के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए इसपर विचार किया गया है।

कार्य पूंजी मानदंडों के अनुसार सुविचारित की गई है। उपभोग किए गए भंडार और पुर्जे 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार लिए गए हैं। रोकड़ शेषजमा को दिशानिर्देश स्थिति के अनुसार एक माह के रोकड़ व्यय पर विचार किया गया है। तत्संबंधी वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यथा प्रतिवेदित मौजूदा देयताओं पर विचार किया गया है। उपर्युक्त समायोजनों के अधीन, कार्य पूंजी नकारात्मक परिगणित होती है और इसलिए इसे शून्य माना गया है।

(ञ). तदनुरूपी अवधि के वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष 2017-18 से 2019-20 के अनुमानों की समीक्षा के लागत विवरण की प्रति **अनुलग्नक-II** रूप में संलग्न की गई है।

(ड). पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की तुलना का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

(रु. करोड़ों में)

विवरण	पूर्ण अवधियों में वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए सकल		भिन्नता प्रतिशत में
	प्रशुल्क आदेश के अनुसार अनुमान	वास्तविक आंकड़े	
यातायात (लाख टनों में)	189.73	213.98	12.78%
कुल परिचालन आय	405.67	485.56	19.69%
एफएमई घटाव एफएमआई सहित कुल व्यय, मूल्यह्रास और उपरिव्यय	329.67	399.48	21.17%
प्रतिलाम से पहले अधिशेष/घाटा	76.00	86.08	13.26%
नियोजित पूंजी (औसत)	158.32	168.62	6.50%
नियोजित पूंजी पर 16 प्रतिशत प्रतिलाम	76.00	80.93	6.50%
आरओसीई के बाद निवल अधिशेष (पूर्व अधिशेष के समायोजन से पहले)	0.00	5.15	--

(ढ). 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि से संबंधित पूर्व अवधि के संदर्भ में विश्लेषण के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

- (i). वीएसपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक कुल यातायात 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान 189.73 लाख टन के अनुमानित यातायात के विपरीत 213.98 लाख टन है। भौतिक पैरामीटरों अर्थात् प्रहस्तित वास्तविक यातायात में भिन्नता अनुमानों की तुलना में 12.78 प्रतिशत सकारात्मक है।
- (ii). वीएसपीएल द्वारा अर्जित परिचालन आय 19.69 प्रतिशत की सकारात्मक भिन्नता के परिणामस्वरूप तदनुरूपी अवधि के लिए रु. 405.67 करोड़ के अनुमानन के मुकाबले रु. 485.56 करोड़ है।
- (iii). व्यय साइड पर, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए वास्तविक सकल व्यय तदनुरूपी अवधि के लिए पिछले आदेश में सुविचारित रु. 329.67 करोड़ के अनुमानित व्यय के मुकाबले रु. 399.49 करोड़ है। इस प्रकार कुल वास्तविक व्यय पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमानित व्यय में तुलना में 21.17 प्रतिशत की सकारात्मक भिन्नता दर्शाता है।
- (iv). 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए औसत नियोजित पूंजी रु. 158.32 करोड़ की औसत अनुमानित नियोजित पूंजी के मुकाबले रु. 168.62 करोड़ है। नियोजित औसत पूंजी में भिन्नता 6.50 प्रतिशत नकारात्मक आती है।
- (v). हमारे द्वारा तैयार किए गए पूर्व अवधि के संशोधित लागत विवरण के अनुसार, वीएसपीएल ने स्वीकार्य लागत के बाद रु. 5.15 करोड़ का कुल सकल अधिशेष और 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 16 प्रतिशत आरओसीई अर्जित किया है।
- (vi). इस प्रकार औसत नियोजित पूंजी पर अर्जित औसत वार्षिक प्रतिलाम 17.02 प्रतिशत परिगणित होता है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

(रु. करोड़ों में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	औसत
प्रतिलाम से पहले वास्तविक अधिशेष/घाटा	30.61	29.41	26.07	86.09 (कुल) 28.70 (औसत)
वास्तविक नियोजित पूंजी	183.98	169.06	152.82	168.62 (औसत)
नियोजित पूंजी पर अर्जित वास्तविक प्रतिलाम	16.64%	17.40%	17.06%	17.02%

- (vii). प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के अनुसार, यदि पूर्व प्रशुल्क चक्र के वास्तविक भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा  $+ / (-)$  20 प्रतिशत से अधिक भिन्नता दिखाई देती है तो ऐसे प्रोद्भूत लाभ/हानि का 50 प्रतिशत अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित किया जाएगा। एमओएस द्वारा यथा संप्रेषित एजी की राय के अनुसार भी, भौतिक और वित्तीय पैरामीटर दोनों में भिन्नता को खंड 2.13 के प्रयोजन के लिए लेखा में लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, एजी की राय के अनुसार, यदि भौतिक और वित्तीय पैरामीटर दोनों में भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक रहती है तो अधिशेष का 20 प्रतिशत परिचालक द्वारा बनाये रखने की अनुमति दी जाएगी। यह केवल 20 प्रतिशत से अधिक अधिशेष है जो परिचालक और उपयोक्ताओं के बीच बराबर अर्थात् 50:50 बांटा जाएगा। नटशेल में, अतिरिक्त अधिशेष के 60 प्रतिशत को परिचालक के पास बनाये रखने की अनुमति दी गई है और 40 प्रतिशत अतिरिक्त भावी प्रशुल्क में समायोजन पर विचार करते हुए उपयोक्ताओं द्वारा शेयर किया जाना है।
- उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि भौतिक पैरामीटर अर्थात् प्रहस्तित वास्तविक यातायात में भिन्नता 20 प्रतिशत अर्थात् 12.78 प्रतिशत सकारात्मक से कम पाई जाती है और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के रूप में वित्तीय कार्यनिष्पादन सकारात्मक होता है परंतु भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो (16 प्रतिशत पर 20 प्रतिशत भिन्नता 19.20 प्रतिशत होती है)। चूंकि दोनों पैरामीटरों में भिन्नता  $+ / (-)$  20 प्रतिशत से कम पाई गई है, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.13 के निर्वर्णन पर एजी की राय का अनुसरण करते हुए मौजूदा प्रशुल्क चक्र में पूर्व अवधि अधिशेष के समायोजन के लिए कोई मामला नहीं है।
- (ग). जैसाकि ऊपर बताया गया है, चूंकि वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित लेखे इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने के समय उपलब्ध नहीं है, मौजूदा प्रशुल्क संशोधन कार्यवाही में वीएसपीएल द्वारा प्रेषित वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक आंकड़ों/अनुमानों के साथ पिछले प्रशुल्क आदेश में सुविचारित वर्ष 2019-20 के अनुमानों की तुलना और पूर्व अवधि विश्लेषण में सुविचारित की अगली समीक्षा के समय वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित लेखों के संदर्भ में पुनः समीक्षा की जाएगी। भिन्नता के कारण भावी प्रशुल्क में किया जाने वाला समायोजन, यदि कोई हो, लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाएगा।
- (ट). पैरा 16 (xx) में पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश दिनांक 19 जनवरी 2018 के दौरान, “अन्य व्यय” शीर्षक के अधीन सीमाशुल्क मैनिंग प्रमारों का अनुमान लगाते समय, वीएसपीएल ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 में प्रतिवेदित शून्य व्यय के मुकाबले आगामी वर्षों में 2 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2017-18 में रु. 90.18 लाख का अनुमान लगाया था। वर्ष 2017-18 के लिए रु. 90.18 लाख का अनुमान, अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 अवधि के लिए वीएसपीएल को जारी किए गए सीमाशुल्क मांग नोट दिनांक 22 जून 2017 के आधार पर और प्रशुल्क आदेश में कहा गया है कि यदि वास्तविक आंकड़ों के साथ अनुमानों की समीक्षा करते समय अगले प्रशुल्क संशोधन के समय यह देखा जाता है कि इस मद के अधीन स्वीकृत अनुमान वीएसपीएल द्वारा प्रोद्भूत नहीं किया गया है तो पिछले संशोधन में स्वीकृत व्यय मौजूदा संशोधन में समायोजित अर्थात् खारिज किया जाएगा। वीएसपीएल ने तीन वर्षों 2017-18 से 2019-20 के प्रत्येक वर्ष के लिए इस मद के अधीन प्रतिवेदित वास्तविक व्यय भेजे हैं और स्पष्ट किया है कि यह मामला अभी भी न्यायाधीन है और वीएसपीएल मांग पर रोक के लिए न्यायालय के आदेश की शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क द्वारा की जाने वाली आवधिक मांग का 50 प्रतिशत भेज रहा है। तीन वर्षों 2016-17 से 2019-20 के प्रत्येक वर्ष के लिए वीएसपीएल द्वारा प्रतिवेदित व्यय पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमानित स्तर से अधिक पाया जाता है। ऐसी स्थिति में, इस लेखा पर किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- (ठ). इसके अलावा, पैरा 16(xv)(ग) में पिछले प्रशुल्क संशोधन आदेश के दौरान, वीएसपीएल के स्वामित्व वाली एचएमसी की मरम्मत और अनुरक्षण लागत के अनुमान के संबंध में यह बताया गया था कि वीएसपीएल ने वर्ष 2016-17 के लिए अपनी स्वयं की एचएमसी के लिए एएमसी का नवीकरण नहीं किया था। तथापि, अप्रत्याशित खराबी के मद्देनजर, पिछले वर्षों में एएमसी के अधीन उपभोग किए गए पुर्जों का मूल्य, पिछले वर्ष के लिए व्यय को आधार रूप में लिया गया है और वीएसपीएल द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए व्यय के अनुमान के लिए सुविचारित किया गया था। वीएसपीएल द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण उक्त आदेश में सुविचारित किया गया था और यह कहा गया था कि वास्तविक आंकड़ों की अनुमानों से समीक्षा की जाएगी और, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन के दौरान अनुमानों पर विश्वास करने के कारण लाभ प्रोद्भूत होता है तो इसे दिशानिर्देशों के अनुसार अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित किया जाएगा।
- इस संबंध में जब वीएसपीएल से वास्तविक आंकड़ों की मांग की गई थी, वीएसपीएल ने स्पष्ट किया था कि बार-बार खराबी और मरम्मत नियंत्रण से बाहर होने के कारण, वीएसपीएल ने नवंबर 2018 से अपनी एक एचएमसी का परिचालन बंद कर दिया था और दिसंबर 2019 के बाद स्क्रैप के रूप में बेच दिया था। इस तरह, स्वयं की क्रेनों द्वारा प्रहस्तित मात्रा कम हुई है और किराये पर ली गई क्रेनों के व्यय में वृद्धि हुई है। वीएसपीएल ने इस संबंध में वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष अनुमानों के ब्योरे दिए हैं जोकि पूर्व अनुच्छेदों में दिए गए हैं। वीएसपीएल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले प्रशुल्क चक्र के दौरान लगाये गए अनुमानों पर विश्वास करते हुए कोई लाभ प्रोद्भूत नहीं हुआ है और कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है। वीएसपीएल द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर और यह भी स्वीकार करते हुए कि पूर्व अवधि विश्लेषण, भिन्नता दोनों पैरामीटरों अर्थात् भौतिक और वित्तीय में भिन्नता  $+ / (-)$  20 प्रतिशत से अधिक पाई गई है, इसलिए इस कारण किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- (viii). जैसाकि पूर्व अनुच्छेदों में बताया गया है, संशोधित सूचकांकित अधिकतम एआरआर वर्ष 2019-20 के लिए रु. 193.48 करोड़ निर्धारित किया गया था। जैसाकि पूर्व अनुच्छेदों में विश्लेषण में बताया गया है, पूर्व अनुच्छेदों में दिए गए विश्लेषण के आधार पर पूर्व अवधि समायोजन के लिए कोई मामला नहीं है।
- (ix). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.10 के अनुसार, एसओआर तैयार करने के लिए, सुविचारित किया जाने वाला यातायात संबद्ध पत्तन द्वारा विधिवत् प्रमाणित वर्ष वार्ड1, वार्ड2 और वार्ड3 के दौरान बीओटी परिचालक द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात का

औसत होगा। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित औसत यातायात 68.43 लाख टन है। वीपीटी ने वीएसपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक यातायात 66.63, 70.92 और 71.03 लाख टन पेश किया है और तीन वर्षों के यातायात का औसत 68.53 लाख टन परिगणित किया है। वीपीटी द्वारा प्रेषित औसत यातायात में 0.10 लाख टन की मामूली भिन्नता है। भिन्नता के कारण वीपीटी द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए हैं। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, राजस्व अनुमानन के लिए वीएसपीएल द्वारा सुविचारित वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 68.43 लाख टन के औसत यातायात पर विश्वास किया गया है।

वीएसपीएल ने उद्धरित करते हुए तटीय पोत/कार्गो से राजस्व का अनुमान नहीं लगाया है कि पिछले तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर कोई तटीय कार्गो परिकल्पित नहीं किए गए हैं। वीएसपीएल ने दंडात्मक बर्ध किराया प्रभारों का अनुमान नहीं लगाया है। जब स्पष्टीकरण मांगा गया था, इसने बताया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान केवल एक या दो मामलों में उसे इस मद से राजस्व अर्जित हुआ था और इसलिए इस प्रशुल्क के लिए किसी आय का अनुमान नहीं लगाया गया है।

- (ख). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.11.1 वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार की ताकतों को जवाब देने के लिए अनुमानित एआरआर के भीतर दरें निर्धारित करने के लिए बीओटी परिचालकों को अधिकार देता है। वीएसपीएल का प्रस्ताव दिशानिर्देश प्रावधान के भीतर है।

संशोधित प्रस्ताव में वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि को पूर्व अनुच्छेदों में तालिकाबद्ध किया गया है और इसलिए दोहराया नहीं गया है। वीएसपीएल ने कहा है कि वह वीपीटी और पड़ोसी निजी पत्तनों जैसे गंगावरम में स्टीवडोरों, बीओटी परिचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। उपयोक्ता वीपीटी में निम्नतम दरों वाले के पास जाते हैं। ऐसी स्थिति में, लम्बी बातचीत के बाद वीआरसी और सीआरसी में प्रशुल्क वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वीएसपीएल ने कहा है कि उसने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जलयान और कार्गो हित के लिए संतुलित प्रशुल्क वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

प्रस्तावित प्रशुल्क पर, वीएसपीएल ने पूर्ण एआरआर की पूर्ति की परिकल्पना नहीं की है। अनाच्छादित छूटा एआरआर अंतर रु. 19.92 करोड़ है।

- (ग). वीएसपीएल का मौजूदा एसओआर बर्ध सं. ईक्यू 8 और ईक्यू 9 के लिए एकसमान बर्ध किराया प्रभार निर्धारित करता है। प्रस्तावित एसओआर में, वीएसपीएल द्वारा दूसरे बीओटी परिचालक अर्थात् एमओपीटी में एसडब्ल्यूपीएल, इसी तरह वीएसपीएल में दो बर्ध हैं जिनमें से एक परंपरागत और दूसरा अभियंत्रणीकृत प्रहस्तन के लिए है, द्वारा अनुसरित दृष्टिकोण अंगीकृत करते हुए ईक्यू 8 और ईक्यू 9 के लिए पृथक बर्ध किराया प्रभार प्रस्तावित किया है। ईक्यू 8 बर्ध जोकि अभियंत्रणीकृत बर्ध है, के लिए बर्ध किराया प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि 11.24 प्रतिशत है और ईक्यू 9 बर्ध के लिए 1.12 प्रतिशत की मामूली वृद्धि प्रस्तावित की गई है। स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया लि0 (सेल) ने कहा है कि बर्ध किराया प्रभार में प्रस्तावित वृद्धि से उनपर 11.2 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा।

वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि 11.2 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि में से, वर्ष 2019-20 के लिए 4.26 प्रतिशत का वृद्धि कारक है। शेष वृद्धि केवल 6.94 प्रतिशत परिगणित होती है जिसे इस तरह प्रस्तावित किया गया है कि अनुमानित वार्षिक राजस्व अपेक्षा पूरी हो जाए। वीएसपीएल ने औचित्य दिया है कि प्रस्तावित बर्ध किराया प्रभारों पर भी, यह वीपीटी में अन्य बीओटी टर्मिनलों, गंगावरम पत्तन एवं एमओपीटी में परिचालन कर रहे एसडब्ल्यूपीएल की अपेक्षा अभी भी बहुत कम हैं। इसके अलावा, बर्ध सं. ईक्यू 8 में अभियंत्रणीकृत परिचालनों से उपयोक्ताओं द्वारा कम वापिसी समय का लाभ उठाया जा रहा है।

- (घ). वीएसपीएल ने बताया है कि घाटशुल्क दर और स्टीवडोरिंग दरों में प्रस्तावित वृद्धि वीपीटी की दरों में एकसमानता बनाये रखने और अनुमानित एआरआर की पूर्ति करने के लिए भी है। कुछ कार्गो मदों के लिए ही, प्रस्तावित घाटशुल्क दर वीपीटी के एसओआर में निर्धारित दरों की अपेक्षा अधिक है। एचएमसी प्रभार में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है। वीएसपीएल ने नई प्रशुल्क मदों अर्थात् (क). बाक्सड्राई के लिए घाटशुल्क प्रभार और (ख). बाक्सड्राई और मैगनीज अयस्क के लिए स्टीवडोरिंग प्रभार का प्रस्ताव किया है। वीपीटी में बाक्सड्राई के लिए घाटशुल्क दर रु. 50/- प्रति टन है। वीएसपीएल द्वारा रु. 40/- प्रति टन की दर से प्रस्तावित घाटशुल्क दर वीपीटी में घाटशुल्क दर से कम है। वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित बाक्सड्राई और मैगनीज अयस्क के लिए स्टीवडोरिंग दरें सीमेंट क्लंकर जैसे बल्क कार्गो के अनुसार बताया गया है। वीएसपीएल ने इन मदों से किसी राजस्व का अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, रु. 19.92 करोड़ का राजस्व अंतर अनाच्छादित रह गया है। इसलिए, इन नई प्रशुल्क मदों से राजस्व, यदि कोई हो, प्रोद्भूत होता है तो इसे अनाच्छादित रह गए राजस्व अंतर में समाहित किया जा सकता है। अतः इन दो नई मदों के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क वीएसपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया है।

- (ङ). पिछले संशोधन से पहले एसओआर में, रेलवे साइडिंग, प्रशासन और अनुरक्षण प्रभारों के लिए प्रशुल्क रु. 3.20 प्रति टन पर निर्धारित किया गया था। पिछले संशोधन के दौरान, वीएसपीएल ने यह कहते हुए इस प्रशुल्क मद को हटाने का प्रस्ताव किया था कि यह वीएसपीएल द्वारा वसूल नहीं किया जा रहा है। वीएसपीएल ने अब रेलवे अनुरक्षण और साइडिंग प्रभारों के लिए प्रभारों के लिए रु. 6/- प्रति टन की दर से अनुसूची 4.2 के अधीन इस प्रशुल्क मद को अब दोबारा शामिल करने का प्रस्ताव किया है। सेल ने यह कहते हुए इस प्रशुल्क मद पर आपत्ति उठाई है कि वीपीटी वीएसपीएल साइडिंग सहित वीपीटी के भीतर साइडिंग के उपयोग के लिए टर्मिनल प्रभार पहले से वसूल कर रहा है। इसलिए, साइडिंग के अनुरक्षण के लिए पृथक प्रभार का बोझ उपयोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता और यह तत्संबंधी पतलों के लिए रेलवे प्रशुल्क निर्धारण के परिदृश्य के भीतर होना चाहिए।

वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि वीएसपीएल ने टर्मिनल के भीतर अपने बर्धों को अन्कापेली गेट से रेलवे लाइनों का निर्माण किया है और यह अधिसूचित निजी साइडिंग है और वेसे वीएसपीएल रेलवे साइडिंग के अनुरक्षण के लिए संचयी व्यय और संबद्ध प्रशासनिक व्यय प्रोद्भूत करता है। वीएसपीएल ने पुष्टि की है कि यह प्रशुल्क मद उनकी संपूर्ण रेलवे लाइनों के अनुरक्षण के लिए

वीपीटी द्वारा संग्रहीत साइडिंग प्रभागों से भिन्न है। जैसाकि पहले बताया गया है इस मद के लिए प्रशुल्क पूर्व-संशोधित एसओआर में वीएसपीएल के एसओआर में प्रचलित था। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर और यह भी स्वीकार करते हुए कि राजस्व अनुमान इस प्रशुल्क मद से राजस्व लेते हैं, इसलिए प्रस्तावित प्रशुल्क अनुमोदित किया गया है।

- (च). तट प्रहस्तन परिचालनों के लिए, रु. 65/- प्रति टन की मौजूदा दर को बढ़ाकर रु. 81/- प्रति मी.ट. किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि तट प्रहस्तन वीएसपीएल के लिए उच्चतम लागत है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण उपाय है और एनसीएलटी, तट प्रहस्तन लागत में वृद्धि हुई है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों जैसे तारपुलिन से ढकना आदि का ध्यान रखने के लिए अतिरिक्त लागत प्रोद्भूत की गई है। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर और यह भी स्वीकार करते हुए कि राजस्व अनुमान राजस्व अनुमान इस प्रशुल्क मद से राजस्व लेते हैं, और इसलिए प्रस्तावित प्रशुल्क अनुमोदित किया गया है।
- (छ). संशोधित दरमान में प्रस्तावित दरों पर, वीएसपीएल ने रु. 173.56 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है। वीएसपीएल ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार यथा अपेक्षित, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए तदनुसूची औसत यातायात के लिए प्रस्तावित एसओआर में प्रत्येक प्रशुल्क मद दर्शाते हुए राजस्व अनुमान की विस्तृत गणना दी है। राजस्व अनुमान विवरण सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित राजस्व अनुमान पर विश्वास किया गया है।
- (ख). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 1.9 के अनुसार, बीओटी परिचालक संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ किए गए मौजूदा रियायत करार में दिए गए उपबंधों से बंधा रहेगा। समानान्तरतः, बीओटी परिचालक संबद्ध महापत्तन न्यास के साथ हुए पृथक करार द्वारा इन दिशानिर्देशों से बंधा रहेगा। वीएसपीएल ने बताया है कि इसने इस संबंध में वीपीटी को अनुरोध किया है और आने वाले समय में इसे जमा करेगा। तथापि, वीएसपीएल ने वीपीटी को लिखित पुष्टि पहले ही भेज दी थी कि यह प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अधीन 1.4.2020 से प्रशुल्क संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव जमा करना स्वीकार करता है। तत्पश्चात्, वीएसपीएल ने अपने द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पृथक करार की प्रति भेजी है। तथापि, इसपर वीपीटी के हस्ताक्षर नहीं हैं। वीएसपीएल से अनुरोध है कि एमओएस द्वारा अपने पत्र दिनांक 08 मार्च 2019 द्वारा वीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को अग्रेषित निर्धारित प्रारूप के अनुसार पृथक करार की वीएसपीएल तथा वीपीटी दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रति हमारे रिकार्ड के लिए भेजे।
- (xi). उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, वीएसपीएल द्वारा प्रेषित और संशोधित लागत विवरण के आधार पर हमारे द्वारा यथा सुविचारित अधिकतम सूचकांकन एआरआर का सार नीचे दिया गया है:-

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	वीएसपीएल द्वारा प्रेषित एआरआर परिकलन	हमारे द्वारा संशोधित एआरआर परिकलन
1	वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए औसत स्वीकार्य व्यय (वाई1+वाई2+वाई3)/3	127.23	127.13
2	31.03.2019 को प्रगतिधीन कार्य पूंजी सहित 31.03.2019 को नियोजित पूंजी और मानदंडों के अनुसार कार्य पूंजी	364.73	365.23
3	16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	58.35	58.44
4	31 मार्च 2019 को एआरआर (4=2+3)	185.58	185.57
5	वर्ष 2019-20 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन (वर्ष 2019-20 के लिए 4.26 प्रतिशत)	193.49	193.48
6	अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	193.49	193.48
7	प्रस्तावित दर पर आईजीटीपीएल द्वारा अनुमानित राजस्व	173.56	173.56
8	राजस्व अंतर	19.93	19.92

- (xii). बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 को कार्यान्वित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देश का खंड 8.2.2 विनिर्दिष्ट करता है कि एसओआर तैयार करते समय, बीओटी परिचालक जहां तक संभव होगा अपने एसओआर में यथामूल्य घाटशुल्क दर के साथ जाएंगे और इस कार्गो के प्रहस्तन के लिए रखे जाने वाले विशेष ध्यान अथवा बाजार निर्धारित प्रशुल्क को ध्यान में रखते हुए इन मामलों में विशिष्ट घाटशुल्क दर निर्धारित करेगा।

वीएसपीएल ने बिजली के सामानों और मशीनरी के लिए यथामूल्य आधार पर घाटशुल्क दरों का प्रस्ताव करना जारी रखा है। वीएसपीएल ने इस मामले की कार्यवाही के दौरान, पिछले प्रशुल्क आदेश में प्रदत्त सुझाव के अनुसार और वर्किंग दिशानिर्देशों के अनुपालन में यथामूल्य दर

प्रस्तावित करने की बजाय प्रासंगिक कार्यों के प्रहस्तन की लागत के संदर्भ में कार्यों के भार अथवा मूल्य के आधार पर बिजली के सामानों और मशीनरी के लिए घाटशुल्क दर का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया गया था।

वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि ये दो सामान ही कम मिलने वाली मदें हैं और टर्मिनल में इनका सामान्य तौर पर प्रहस्तन नहीं किया जाता है। इसलिए, विचार किए जाने वाले प्रहस्तन की लागत और अन्य कारक अनुभव से प्राप्त होंगे। अतः वीएसपीएल ने वर्तमान के लिए यथामूल्य दर को जारी रखने का अनुरोध किया है। मौजूदा प्रस्ताव में, प्रति इकाई आधार पर घाटशुल्क निर्धारित करने के लिए वीपीटी का कोई प्रस्ताव नहीं होने के कारण, इन दो कार्यों मदों के लिए घाटशुल्क दर वीएसपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित यथामूल्य दरों पर निर्धारित किए जाने की अनुमति दी गई है। तथापि, वीएसपीएल को यह सलाह दी जाती है कि अगले संशोधन के दौरान वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 8.2.2 में किए गए प्रावधान का अनुपालन करने के लिए यथामूल्य आधार की बजाय इकाई दर पर विशिष्ट घाटशुल्क दर प्रस्तावित किए जाने की संभावना का पता लगाये और समीक्षा करें।

- (xiii). मौजूदा दरमान में, अनुसूची 2.1.2 अनुसूची जिसमें 37 कार्यों मदों के लिए आयात कार्यों और निर्यात कार्यों के लिए अलग-अलग घटकवार प्रति पोत प्रति पाली आउटपुट निर्धारित किए गए हैं, में एसओआर में निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिगणित बर्थ अभिग्रहण के बाद पोत के अधिक रुकने के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार निर्धारित करती है। प्रस्तावित दरमानों में, वीएसपीएल ने अनुसूची 2.1.4 को युक्तिसंगत बनाया है/संशोधित किया है और घटकों के 6 समूहों के लिए प्रतिदिन आउटपुट प्रस्तावित किया है। वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधन शुष्क बल्क कार्यों के प्रहस्तन के मानदंडों पर वीपीटी ट्रेड परिपत्र दिनांक 09.07.2018 के अनुसार है। सेल सहित किसी भी उपयोगिता ने प्रस्तावित युक्तिसंगत मानदंडों पर आपत्ति नहीं उठाई है।

इसके अलावा, पोत के अति विराम के लिए दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार की वसूली के लिए, वीएसपीएल ने 10/7 बजे से 4 बजे तक कार्यों परिचालन के पूरा होने के बाद विराम के लिए बर्थ अभिग्रहण की अनुमत अवधि को कम करने का प्रस्ताव किया है। वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित घंटों में कटौती इसके पूर्व अनुभव पर आधारित है और वीपीटी द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार है तथा वह घटाये गए घंटे पर्याप्त पाये गए हैं क्योंकि विलंब के ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आधार पर, मौजूदा अनुसूची 2.1.2 और 2.1.4 में वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया गया है।

- (xiv). यह देखा गया है कि विदेशगामी पोत के लिए वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि बर्थ सं. ईक्यू-8 के लिए 11.24 प्रतिशत और बर्थ सं. ईक्यू-9 के लिए बर्थ किराये में 1.12 प्रतिशत की वृद्धि परिगणित होती है। तथापि, तटीय पोत के लिए वृद्धि क्रमशः 80.03 प्रतिशत और 62.88 प्रतिशत परिगणित होता है। इसी तरह, दंडात्मक बर्थ किराया प्रभारों में और तटीय श्रेणी के लिए पानी की आपूर्ति हेतु प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि विदेशी श्रेणी के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि से अधिक है। तटीय श्रेणी के लिए प्रस्तावित दरों में तीव्र वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि वीएसपीएल प्रचलित विनिमय दर के साथ इसे पुनःउल्लेख करते हुए तटीय कंटेनर के लिए दर पर पहुंचा है और तब इसे उसके 60 प्रतिशत पर पैग किया गया है जोकि सरकारी की प्रचलित लागू तटीय रियायत नीति के अनुसार नहीं है। सरकार की तटीय रियायत नीति प्रत्येक सामान्य संशोधन के दौरान तटीय कार्यों/कंटेनर प्रहस्तन दर के लिए प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में दोबारा शुरू करने की अनुमति देने के लिए संशोधित नहीं की गई है। जब वीएसपीएल से अनुरोध किया गया था कि सरकार की तटीय रियायत नीति का पालन करने के लिए जरूरी शोधन करें और परिणामस्वरूप राजस्व अनुमानन को संशोधित करें, वीएसपीएल ने बताया है कि तटीय दरें सरकारी की तटीय रियायत नीति के अनुसार संशोधित प्रस्तावित एसओआर में संशोधित की गई हैं। तथापि, यह देखा गया है कि वीएसपीएल ने उपर्युक्त मदों के लिए तटीय पोत के लिए दरों के मामले में प्रस्तावित एसओआर में जरूरी शोधन नहीं किए हैं। उपर्युक्त मदों अर्थात् बर्थ किराया प्रभार, दंडात्मक बर्थ किराया प्रभार और पानी की आपूर्ति के लिए प्रभारों के लिए तटीय पोत दरें सरकार की तटीय रियायत नीति का पालन करने के लिए संशोधित एसओआर में संशोधित की गई हैं अर्थात् प्रचलित विनिमय दर के संदर्भ में वीएसपीएल द्वारा किया गया रिस्टेटमेंट हटाया गया है और तटीय पोत के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि इसके विदेशी पार्ट के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क वृद्धि के प्रतिशत के बराबर किया गया है। इसका राजस्व अनुमानन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वीएसपीएल ने पूर्व यथा उल्लिखित तटीय पोत से किसी राजस्व का अनुमान नहीं लगाया है।

- (xv). मूल प्रस्ताव में, तटीय कार्यों के लिए लौह अयस्क, लौह अयस्क गुट्टिकाएं और ताप कोयला के लिए घाटशुल्क दर और स्टीवडोरिंग प्रभार विदेशी कार्यों के लिए प्रस्तावित दरों पर 60 प्रतिशत की रियायत लागू करते हुए प्रस्तावित किए गए हैं। इस संबंध में, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमओएस की तटीय रियायत नीति के अनुसार, पीओएल उत्पादों सहित क्रूड, लौह अयस्क और ताप कोयला तटीय रियायत के लिए हकदार नहीं हैं। तटीय रियायत नीति के अनुसार, तटीय कार्यों के लिए इन मदों हेतु घाटशुल्क दर और स्टीवडोरिंग दर विदेशी दर के बराबर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/78/2018-एनएमपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा अनुमोदित एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए एनएमपीटी के हाल ही के प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, एनएमपीटी के स्पष्टीकरण के आधार पर, यह विदित है कि पेट कोक पेट्रोलियम उत्पादों के समकक्ष है। इसलिए, तटीय रियायत नीति के अनुसार, यह कार्यों तटीय रियायत के लिए भी हकदार नहीं है।

संशोधित प्रस्तावित एसओआर में, तटीय ताप कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क गुट्टिकाओं और पेट कोक के लिए वीएसपीएल द्वारा प्रस्तावित घाटशुल्क दर विदेशी दर के बराबर है जोकि सही पाया गया है और इसलिए अनुमोदित किया गया है।

तथापि, स्टीवडोरिंग प्रभारों के अधीन, वीएसपीएल ने तटीय ताप कोयला, लौह अयस्क और पेट कोक के लिए जरूरी शोधन नहीं किए हैं। इसलिए, संशोधित एसओआर में, सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार विदेशी दर के बराबर इन मदों के लिए तटीय कार्यों हेतु स्टीवडोरिंग दरें निर्धारित करते हुए जरूरी शोधन किया गया है क्योंकि वे तटीय रियायत के लिए हकदार नहीं हैं।

- (xvi). वीएसपीएल ने निर्यातों/आयातों को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित घंटों के बाद सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नतर प्रभारों से संबंधित मौजूदा टिप्पणी सं. 18 को हटा दिया है जिसे एमओएस के पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी.V दिनांक 03 फरवरी 2016 के अनुसरण में शामिल किया गया था जिसके आधार पर एक सामान्य अंगीकरण आदेश सं. टीएएमपी/14/2016-विविध दिनांक 16 फरवरी 2016

जारी किया गया था। मौजूदा टिप्पणी सं. 18 संशोधित एसओआर में निर्धारित रहेगी क्योंकि इसे सभी महापत्तनों और बीओटी परिचालकों के एसओआर में एकसमान रूप से निर्धारित किया गया है और यह सामान्य अंगीकरण आदेश पर आधारित है।

- (xvii). निःशुल्क अवधि के बाद खंड-3.6.2 के अधीन भंडारण प्रमारों से संबंधित मौजूदा टिप्पणी वीएसपीएल द्वारा थोड़ी संशोधित की गई है। दूसरा पखवाड़ा प्रमारों के अलावा 30 दिनों के बाद और 45 दिनों तक भंडारण के लिए रु. 3/- प्रति टन की दर से भंडारण प्रमारों की वसूली से संबंधित मौजूदा खंड हो हटाया गया है। वीएसपीएल ने 45 दिनों के बाद भंडारण प्रमारों को बनाये रखा है। प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया गया है क्योंकि युक्तिकरण से उपयोक्ताओं को राहत मिलेगी।
- (xviii). वीएसपीएल ने रु. 140/- प्रति टन की समेकित दर की वसूली से संबंधित बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए खंड-4.5 (सामग्री प्रहस्तन प्रणाली) के अधीन मौजूदा टिप्पणी को हटाने का प्रस्ताव किया है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मर्दे उपलब्ध करवाई गई हों। वीएसपीएल ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक को समेकित सेवाएं लेनी होती हैं और वीएसपीएल ने रियायत वापिस ले ली है। ऐसी स्थिति में, अनुसूची के अधीन मौजूदा टिप्पणी रिबन्डेंट है। प्रस्तावित हटाया जाना अनुमोदित किया गया है।
- (xix). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, एसओआर को 1 जनवरी से प्रासंगिक वर्ष के 31 दिसंबर के बीच आने वाले भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा। ऐसे समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्ष के 1 मई से आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। वीएसपीएल ने इस संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तावित नहीं की है। मौजूदा संशोधन में, वर्ष 2019-20 से संबंधित 4.26 प्रतिशत का वार्षिक सूचकांकन लिया गया है। ऐसी स्थिति में, वे वर्ष 2020-21 के लिए अर्थात् 1 मई 2020 से प्रशुल्क में वार्षिक सूचकांकन के लिए हकदार हैं। चूंकि 1 मई 2020 पहले ही निकल चुकी है, इसलिए वीएसपीएल संशोधित एसओआर के लागू होने के दिन को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एसओआर में वार्षिक सूचकांकन के लिए हकदार होगा। इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए घोषित 60 प्रतिशत की दर से वार्षिक सूचकांकन प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अधीन 1.13 प्रतिशत है। इसलिए, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित एसओआर को वीएसपीएल द्वारा 1.13 प्रतिशत से सूचकांकित किए जाने और इसके लागू होने की तारीख से संशोधित एसओआर लागू किए जाने की जरूरत है। अन्य बीओटी परिचालकों के मामले में अनुमोदित वार्षिक सूचकांकन के संबंध में प्रासंगिक टिप्पणी वीएसपीएल के एसओआर में निर्धारित की गई है।
- (xx). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 4.9 खंड 2.12 में यथा उल्लिखित वार्षिक सूचकांकन के अधीन तीन वर्षों के प्रशुल्क वैधता चक्र निर्धारित करता है। अतः संशोधित एसओआर की वैधता एसओआर में निर्धारित वार्षिक सूचकांकन के अधीन संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित की गई है।
- (xxi). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 4.8 विनिर्दिष्ट करता है कि साधारणतः इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश राजपत्र में आदेश के अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद से लागू होगा। तदनुसार, संशोधित एसओआर राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा। वीएसपीएल का मौजूदा एसओआर 31 मार्च 2019 तक वैध है। उस समय तक, संशोधित एसओआर के प्रभावी होने तक यह वित्तीय वर्ष 2020-21 की लगभग शुरुआत होगी। इसलिए, मौजूदा एसओआर को समाप्ति की तारीख से संशोधित एसओआर के लागू होने तक विस्तारित किया माना गया है।
- (xxii). यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वीएसपीएल ने हारबर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) के प्रशुल्क में इस प्राधिकरण द्वारा की गई रु. 72.75 प्रति टन से रु. 36.70 प्रति टन की कटौती की सीमा तक माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अक्टूबर 2011 के प्रशुल्क आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका सं. 2011 का 33402 दाखिल की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अगले आदेशों तक रु. 72.75 प्रति टन प्रभारित और वसूल करने की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश 19 दिसंबर 2011 का पारित किया था। माननीय न्यायालय ने भी वीएसपीएल को निदेश दिया है कि सभी ऐसे प्रशुल्क 22.12.2011 के बाद एचएमसी पर वसूल और संग्रहीत किए जाएंगे, याचिकाकर्ता ऐसे प्रत्येक लेनदेन का लेखा रखेगा और यदि याचिकाकर्ता अपनी रिट याचिका में सफल नहीं रहता है तो विवादित आदेश के अधीन निर्धारित रु. 36.70 प्रति टन के प्रशुल्क से अधिक वीएसपीएल द्वारा संग्रहीत राशि माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों के अधीन होंगे। रिट याचिका का माननीय न्यायालय द्वारा अभी निपटान किया जाना है।

इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/18/2014-वीएसपीएल दिनांक 15 मई 2015 और आदेश सं. टीएमपी/19/2017-वीएसपीएल दिनांक 19 जनवरी 2018 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अनुवर्ती प्रशुल्क संशोधन के दौरान, वीएसपीएल ने पूर्व अवधि विश्लेषण के प्रयोजन के लिए वर्ष 2011-12 से 2013-14 और 2014-15 और 2015-16 के लिए वार्षिक लेखों में आदेश दिनांक 15 मई 2015 के लागू होने में दूरित संशोधन तक 7 जुलाई 2015 तक विचार किया था। वीएसपीएल को रु. 72.75 प्रति टन की पूर्व-संशोधित दर संग्रहीत करने के लिए वीएसपीएल को अनुमति देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के विशिष्ट अंतरिम आदेश और वीएसपीएल को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निदेश के मद्देनजर कि संग्रहीत भिन्न राजस्व के लिए पृथक खाते रखे जाएंगे जोकि न्यायालय के निर्णय के अधीन है, वर्ष 2011-12 से 2013-14 और 2014-15 तथा 2015-16 के लिए 7 जुलाई 2015 तक वार्षिक लेखों में प्रतिवेदित एचएमसी से वास्तविक राजस्व वीएसपीएल द्वारा किए गए तरह पूर्व अवधि विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सुविचारित किया गया था।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 और 2014-15 तथा 2015-16 के लिए 7 जुलाई 2015 तक की अवधि के लिए प्रशुल्क आदेश दिनांक अक्टूबर 2011 के अनुसार एचएमसी के लिए वीएसपीएल द्वारा संग्रहीत किए जाने योग्य राजस्व के संबंध में समेकित स्थिति और आदेश सं. टीएमपी/19/2017-वीएसपीएल दिनांक 19 जनवरी 2018 के पैरा 16(vi)(घ) में यथा तालिकाबद्ध वीएसपीएल द्वारा प्रेषित विवरण के आधार पर, संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:



वर्ष	माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 19.12.2011 के अनुसरण में एचएमसी किराये पर लेने से वीएसपीएल द्वारा संग्रहीत राजस्व	अक्तूबर 2011 आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित रु. 38.70 प्रति टन की दर से एचएमसी के किराये के लिए संग्रहीत राजस्व	माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर 19.12.2011 (माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख) से 09.07.2015 अर्थात् जनवरी 2018 आदेश में मूल्यांकित मई 2015 आदेश में अनुमोदित संशोधित दर तक इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एचएमसी के लिए दर से अधिक वीएसपीएल द्वारा संग्रहीत मिन राजस्व
2011-12 (19.12.2011 से) (टिप्पणी क देखें)	22,018,254	17,582,150	4,435,744
2012-13	82,924,841	65,957,810	16,967,031
2013-14	90,609,219	70,753,209	19,856,011
जोड़ — क (आदेश दिनांक 15 मई 2015 के पैरा 12(iv) (ख) में यथा प्रेषित)	<b>195,552,314</b> (टिप्पणी ख देखें)	<b>154,293,529</b>	<b>41,258,786</b>
2014-15	124,291,963	101,128,145	23,163,818
2015-16 (7.7.2015 तक)	24,240,493	19,624,686	4,615,808
जोड़ ख	<b>148,532,456</b> टिप्पणी (ग) देखें	<b>120,752,831</b>	<b>27,779,625</b>
सकल जोड़ (क+ख)	<b>344,084,770</b>	<b>275,046,359</b>	<b>69,038,411</b>

- (क). माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में वीएसपीएल को निदेश दिया गया था कि 22.12.2011 के बाद संग्रहीत मिन लेवी का खाता अलग रखा जाए। तथापि, वीएसपीएल ने 19.12.2011 अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख से ब्योरे भेजे हैं।
- (ख). वीएसपीएल ने मई 2015 आदेश की कार्यवाही के दौरान बताया था कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत रु. 72.75 की वसूली करने में समर्थ नहीं हैं। वीएसपीएल द्वारा प्रेषित विवरण दर्शाते हैं कि वीएसपीएल ने रु. 38.95 प्रति टन से रु. 49.50 प्रति टन के बीच में एचएमसी के किराये के लिए मिन-मिन दरें संग्रहीत की हैं।
- (ग). इस मामले की कार्यवाही के दौरान वीएसपीएल द्वारा प्रेषित विवरण दर्शाता है कि वीएसपीएल ने 1 अप्रैल 2014 से 7 जुलाई 2015 तक की अवधि के लिए रु. 38.20 प्रति टन से रु. 47.74 प्रति टन के बीच में एचएमसी के किराया प्रभार संग्रहीत किए हैं।

जनवरी 2018 आदेश में, इस प्राधिकरण ने निर्णय दिया था कि वीएसपीएल ने 2011-12 अर्थात् 19 दिसंबर 2011 से माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की तारीख 7 जुलाई 2015 तक की अवधि के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क रु. 690.38 लाख प्रशुल्क से अधिक इसके द्वारा संग्रहीत कुल मिन राजस्व का मूल्यांकन किया था। वीएसपीएल द्वारा कुल मिन संग्रहण वीएसपीएल द्वारा दाखिल रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है।

जैसाकि पहले बताया गया है, उक्त अवधि के लिए पूर्व अवधि विश्लेषण में, इस प्राधिकरण ने लंबित मुकदमेबाजी के कारण एचएमसी के लिए वीएसपीएल द्वारा वास्तव में संग्रहीत आय पर विचार किया था। इस प्रकार, जैसाकि जनवरी 2018 के आदेश में निर्णय दिया गया है, यथा मूल्यांकित वीएसपीएल द्वारा संग्रहीत रु. 690.38 लाख का मिन राजस्व वीएसपीएल द्वारा दाखिल रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है।

यहां पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि पत्र सं. टीएमपी/46/2015-विविध दिनांक 24 जुलाई 2015 द्वारा वीएसपीएल को यह संप्रेषित किया गया था कि चुनौती दिए गए प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/5/2011-वीएसपीएल दिनांक 11 अक्तूबर 2011 से तत्काल पहले के प्रशुल्क चक्र के लिए परिमाणित अधिशेष और वीएसपीएल द्वारा चुनौती दिए गए उक्त आदेश में निर्धारित प्रशुल्क की पोट परिवहन मंत्रालय (एमओएस) पत्र सं. 14019/20/2009-पीजी दिनांक 12 जून 2015 के आधार पर समीक्षा की जाएगी, परंतु माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से, क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

तदनुसार, अगस्त 2015 में माननीय न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करने के कदम उठाये गए थे जिसमें माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई थी कि इस प्राधिकरण को एमओएस द्वारा दिए गए निदेशानुसार भारत के विद्वत महाधिवक्ता की राय को लागू करने के लिए अक्तूबर 2011 के

आदेश की समीक्षा करने की अनुमति दी जाए। मामला अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के बाद, एमओएस के पत्र के आधार पर अधिशेष/(घाटा) परिमाणित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

- (xxiii). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार, दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं, इसी तरह, रियायतें और छूट निम्नतम स्तर हैं। वीएसपीएल निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर रियायतें और छूट दे सकता है।
- (ख). यदि सुविचारित रिकार्ड अथवा किन्हीं अन्य उचित कारणों से कोई त्रुटि दिखाई देती है तो वीएसपीएल भारत के राजपत्र में पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/कारण देते हुए निर्धारित प्रशुल्क की समीक्षा के लिए इस प्राधिकरण का रुख कर सकता है।

12.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, वीएसपीएल का संशोधित दरमान अनुमोदित किया गया है जिसे अलग-से अधिसूचित किया गया है।

12.2. वीएसपीएल का संशोधित दरमान और शर्तें भारत के राजपत्र में संशोधित एसओआर को अधिसूचित करने वाले आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होंगी और संशोधित एसओआर के लागू होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रदत्त अनुमोदन उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

12.3. प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 7 के अनुसार, वीएसपीएल टीएमपी को प्रहस्तित कार्गो यातायात और जलयान बर्थ दिवस आउटपुट पर नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद 90 दिनों के भीतर वीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। टीएमपी द्वारा जो भी कोई अन्य सूचना मांगी जाएगी तो वह भी उसे समय-समय पर भेजी जाएगी। वीएसपीएल को सलाह दी जाती है कि अपेक्षित सूचना नहीं रोकी जाएगी।

12.4. वीएसपीएल के दरमान की अगली समीक्षा के दौरान, वास्तविक राजस्व और वास्तविक यातायात की एआरआर और तत्काल पूर्व प्रशुल्क चक्र में विश्वास किए गए यातायात से तुलना की जाएगी। यदि, ऐसी समीक्षा पर, भौतिक और वित्तीय पैरामीटरों दोनों में भिन्नता  $\pm 20$  प्रतिशत से अधिक रहती है तो अधिशेष/घाटा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 3.2.1 के अनुसार अगले प्रशुल्क चक्र की वार्षिक राजस्व अपेक्षा में समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./119/2020-21]

**अनुबंध-I (क)**

**प्रपत्र - 1**

वीएसपीएल द्वारा प्रेषित महापत्तन न्यासों में परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रशुल्क नीति, 2019 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन				
रु. लाखों में				
क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
(1).	<b>कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)</b>			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	11,438.27	13,641.12	14,793.96
(ii).	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)	3,124.96	2,511.19	2,187.39
	<b>कुल व्यय 1=(i)+(ii)</b>	<b>14,563.23</b>	<b>16,152.31</b>	<b>16,981.35</b>
(2).	<b>ऐसी मदों के मामले में समायोजन जहां आईएनडीएस (लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार) और आईजीएपी के अनुसार प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता है</b>			
(i).	मूल्यहास	152.03	150.85	143.33
(ii).	अन्य व्यय मदें, यदि कोई हों, सूचीबद्ध करें	(703.37)	(490.69)	(341.20)
	<b>समायोजनों का जोड़ 2=(i)+(ii)+ —</b>	<b>(551.34)</b>	<b>(339.84)</b>	<b>(197.87)</b>

(3).	<b>समायोजन घटायें:</b>			
(i).	पत्तन को भुगतान की वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	693.96	791.82	876.35
(ii).	ऋणों पर ब्याज	3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	अशोध्य और संदेहपूर्ण ऋणों के लिए प्रावधान	8.22	80.62	31.03
(iv).	स्लो मूविंग इनवेट्री के लिए प्रावधान			
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो			
	<b>3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] का जोड़</b>	<b>3,777.37</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	<b>जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के अनुसार स्वीकार्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी</b>	519.57	592.84	656.12
(5).	<b>कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (5 = 1+2+3)</b>	<b>10,754.09</b>	<b>13,046.72</b>	<b>14,367.00</b>
(6).	क्र.सं. 5 के औसत व्यय = $[Y1 + Y2 + Y3] / 3$	<b>12,722.60</b>		
(7).	<b>नियोजित पूंजी</b>			
	(i). बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथवा 31 दिसंबर वाई3 को सकल अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) (आईजीएएपी के अनुसार)	<b>34,749.18</b>		
	(ii). जोड़ें: बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथवा 31 दिसंबर वाई3 को प्रगतिधीन केपिटल कार्य (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	<b>6.73</b>		
	(iii). जोड़ें: प्रशुल्क नीति, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य पूंजी			
	(क). वस्तुसूची	399.96		
	(ख). विविध देनदार	253.31		
	(ग). रोकड़	1,063.76		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	1,717.02		
	<b>(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)]</b>	<b>36,472.94</b>		

(8).	क्र.सं. 7(iv) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	5,835.67
(9).	31 मार्च वाई3 अथवा 31 दिसंबर वाई3 को यथा लागू वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [ (6)+ (8) ]	18,558.27
(10).	वर्ष वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन, उदाहरण के लिए यदि वाई4 2019-20 है, तो लागू डब्ल्यूपीआई 4.26 प्रतिशत है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर (9) x 1.0426 होगा	19,348.86
(11).	उपर्युक्त क्र.सं. 10 में यथा दी गई अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	19,348.86
(12).	उपर्युक्त क्र.सं. 11 पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित एसओआर पर राजस्व अनुमानन	17,356.00

अनुलग्नक-1 (ख)

प्रपत्र - 1

वीएसपीएल द्वारा प्रेषित और टीएएमपी द्वारा संशोधित महापत्तन न्यासों में परिचालन कर रहे बीओटी परिचालकों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रशुल्क नीति, 2019 के अधीन वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन				
रू. लाखों में				
क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	11,438.27	13,641.12	14,793.96
(ii).	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)	3,124.96	2,511.19	2,187.39
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	14,563.23	16,152.31	16,981.35
(2).	ऐसी मदों के मामले में समायोजन जहां आईएनडीएस (लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार) और आईजीएपी के अनुसार प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता है			
(i).	मूल्यहास	152.03	150.85	143.33
(ii).	अन्य व्यय मदें, यदि कोई हों, सूचीबद्ध करें	(703.37)	(490.69)	(341.20)
	समायोजनों का जोड़ 2=(i)+(ii)+ —	(551.34)	(339.84)	(197.87)
(3).	समायोजन घटायें:			

(i).	पत्तन को भुगतान की वास्तविक रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी	693.96	791.82	876.35
(ii).	ऋणों पर ब्याज	3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	अन्यों पर ब्याज	27.56	-	-
(iv).	अशोध्य और संदेहपूर्ण ऋणों के लिए प्रावधान	8.22	80.62	31.03
(v).	स्लो मूविंग इनवेट्री के लिए प्रावधान			
(vi).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो			
	<b>3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] का जोड़</b>	<b>3,804.93</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	<b>जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के अनुसार स्वीकार्य रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी</b>	519.57	592.84	656.12
(5).	<b>कुल समायोजनों के बाद कुल व्यय (5 = 1+2+3)</b>	<b>10,726.53</b>	<b>13,046.72</b>	<b>14,367.00</b>
(6).	क्र.सं. 5 के औसत व्यय = $[Y1 + Y2 + Y3] / 3$	<b>12,713.42</b>		
(7).	<b>नियोजित पूंजी</b>			
	(i). बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथवा 31 दिसंबर वाई3 को सकल अचल परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर) (आईजीएएपी के अनुसार)	<b>34,749.18</b>		
	(ii). जोड़ें: बीओटी परिचालक द्वारा अनुसरित 31 मार्च वाई3 अथवा 31 दिसंबर वाई3 को प्रगतिधीन केपिटल कार्य (लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार)	<b>6.73</b>		
	(iii). जोड़ें: प्रशुल्क नीति, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य पूंजी			
	(क). वस्तुसूची	449.87		
	(ख). विविध देनदार	253.31		
	(ग). रोकड़	1,063.76		
	(घ). (क)+(ख)+(ग) का जोड़	1,766.93		
	<b>(iv). कुल नियोजित पूंजी [(i)+(ii)-(iii)]</b>	<b>36,522.85</b>		
(8).	<b>क्र.सं. 7(iv) पर 16 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ</b>	<b>5,843.66</b>		

(9).	31 मार्च वाई3 अथवा 31 दिसंबर वाई3 को यथा लागू वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) [ (6)+ (8) ]	18,557.07
(10).	वर्ष वाई4 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत की दर से एआरआर में सूचकांकन, उदाहरण के लिए यदि वाई4 2019-20 है, तो लागू डब्ल्यूपीआई 4.26 प्रतिशत है और वर्ष वाई4 के लिए सूचकांकित एआरआर (9) x 1.0426 होगा	19,347.61
(11).	उपर्युक्त क्र.सं. 10 में यथा दी गई अधिकतम सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	19,347.61
(12).	उपर्युक्त क्र.सं. 11 पर अनुमानित अधिकतम सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित एसओआर पर राजस्व अनुमानन	17,356.00

अनुलग्नक-II

विज्ञान सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

(रु. लाखों में)

बीएसपीएल द्वारा प्रेषित और टीएएमपी द्वारा संशोधित वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए बीएसपीएल के पूर्व अवधि कार्यनियन्त्रण का विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	प्रशुल्क समीक्षा आदेश दिनांक 03.10.2018 में विश्वास किए गए अनुमान				वास्तविक आंकड़े						प्रतिशतता में विलंबता (%)
		2017-18	2018-19	2019-20	जोड़	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20	2019-20	जोड़	
								(रिम. तक)	जन. से मार्च	अप्रैल से मार्च		
	यातायात (टनो में)	6200000	6324000	6449000	18973000	7115969	7089500	5394679	1798226	7192905	21398375	12.78%
	क्षमता (टनो में)	7700000	7700000	7700000	23100000	7700000	7700000	5775000	1925000	7700000	23100000	
I	कुल परिचालन आय											
	(i) पोत संबंधित आय	1414.01	1676.90	1788.97	4,879.88	1984.29	2,467.26	1,824.35	608.12	2432.47	6,884.02	
	(ii) कार्गो संबंधित आय	11482.44	11984.02	12221.01	35,687.47	13168.74	14,179.17	10,743.34	3,581.11	14324.45	41,672.36	
	जोड़ - I	12896.44	13660.91	14009.99	40567.34	15153.03	16,646.43	12,567.69	4,189.23	16756.92	48,556.38	19.69%
II	परिचालन लागतें (मूल्यहास अविरिक्त)											
	(i) परिचालन और प्रत्यक्ष लेबर	467.12	490.86	508.17	1466.15	489.01	481.16	410.29	136.76	547.05	1,517.22	
	(ii) अनुरक्षण लेबर	569.65	581.04	592.66	1743.36	590.74	678.98	540.62	180.21	720.82	1,990.55	
	(iii) उपस्कर चालन लागतें	1648.78	1707.38	1768.37	5124.53	1675.66	1,656.98	1,289.26	429.75	1719.02	5,051.66	
	(iv) अनुरक्षण निकर्षण	101.69	103.72	105.79	311.20	142.12	-	-	-	0.00	142.12	
	(v) रॉयल्टी/राज स्व हिस्सेदारी	469.89	479.29	488.76	1437.94	592.84	656.12	491.27	163.76	655.03	1,903.99	
	(vi) उपस्कर किराया	4080.38	4237.39	4399.31	12717.08	4713.88	5,541.86	4,441.87	1,480.62	5922.50	16,178.24	
	(vii) रिवाचत करार के अनुसार देय पट्टा किराये	133.24	134.59	135.96	403.80	248.29	538.55	376.61	125.54	502.15	1,288.98	
	(viii) बीमा	70.32	71.72	73.16	215.20	76.95	106.37	84.12	28.04	112.16	295.48	
	(ix) अन्य व्यय	526.40	537.58	548.99	1612.97	1604.16	1621.97	1070.89	356.96	1427.86	4,653.99	
	(x) तकनीकी सेवा शुल्क	12.16	12.16	12.16	36.48	12.16	12.16	9.12	3.04	12.16	36.48	
	जोड़ - II	8079.63	8355.73	8633.33	25068.70	10145.81	11294.15	8714.06	2904.69	11618.74	33,058.70	31.87%
					32967.87						39947.92	21.17%
III	मूल्यहास	1517.03	1512.57	1488.17	4517.77	1586.32	1571.20	1218.40	406.13	1624.53	4,782.05	5.85%

IV	उपरिव्यय											
	(i) प्रबंधन तथा प्रशासन उपरिव्यय	1078.63	1100.70	1123.22	3302.55	1278.96	1,422.87	1,014.02	338.01	1352.02	4,053.86	22.75%
	(ii) प्राथमिक व्यय और अप्रिंट भुगतान राइट-ऑफ	33.10	33.10	33.10	99.30	33.10	33.10	24.83	8.28	33.10	99.30	
	<b>जोड़ - IV</b>	<b>1111.74</b>	<b>1133.80</b>	<b>1156.32</b>	<b>3401.86</b>	<b>1312.06</b>	<b>1,455.97</b>	<b>1,038.84</b>	<b>346.28</b>	<b>1385.12</b>	<b>4,153.16</b>	
V	परिचालन अतिशेष(पाटा) (I) - (II) - (III) - (IV)	<b>2188.04</b>	<b>2658.80</b>	<b>2732.16</b>	<b>7579.01</b>	<b>2108.83</b>	<b>2,325.11</b>	<b>1,596.39</b>	<b>532.13</b>	<b>2128.52</b>	<b>6,562.46</b>	- 13.41%
VI	वित्त और विविध आय (एफएमआई)											
	(i) एनए के अनुसार प्राप्ति योग्य छूटप्राप्त टर्मिनल मूल्य	6.06	6.79	7.61	20.46	6.06	6.79	5.71	1.90	7.61	20.46	
	(ii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	945.79	609.28	352.85	117.62	470.47	2,025.54	
	कुल एफएमआई	6.06	6.79	7.61	20.46	951.85	616.07	358.56	119.52	478.08	2,046.00	
VII	वित्त और विविध व्यय (एफएमई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-			-	
VIII	एफएमआई घटाव एफएमई (VI) - (VII)	6.06	6.79	7.61	20.46	951.85	616.07	358.56	119.52	478.08	2,046.00	
IX	ज्याज और कर से पहले अतिशेष (V) + (VIII)	<b>2194.10</b>	<b>2665.59</b>	<b>2739.76</b>	<b>7599.47</b>	<b>3060.88</b>	<b>2,941.18</b>	<b>1,954.95</b>	<b>651.65</b>	<b>2606.60</b>	<b>8,608.46</b>	13.28%
X	नियोजित पूंजी	17369.84	15824.17	14302.90	15832.30	18398.11	16906.02	15281.49		15281.49	16,861.87	6.50%
XI	आरओसीई - अधिकृतम स्वीकार्य	2779.17	2531.87	2288.46	7599.51	2943.70	2,704.96	1,833.78	611.26	2445.04	8,093.70	
XII	क्षमता उपयोग	81%	82%	84%	82%	92%	92%	93%	93%		93%	
XIII	क्षमता उपयोग के लिए समायोजित आरओसीई	2779.17	2531.87	2288.46	7599.51	2943.70	2,704.96	1,833.78	611.26	2445.04	8,093.70	6.50%
XIV	निवल अतिशेष(पाटा) (IX) - (XIII)	<b>(585.07)</b>	<b>133.72</b>	<b>451.30</b>	<b>(0.04)</b>	<b>116.98</b>	<b>236.21</b>	<b>121.17</b>	<b>40.39</b>	<b>161.56</b>	<b>514.76</b>	
XV	निवल अतिशेष(पाटा) परिचालन आय के प्रतिशत रूप में (XIV/I)	-4.54%	0.98%	3.22%		0.77%	1.42%	0.96%	0.96%	0.96%	1.06%	
XVI	बीसव निवल अतिशेष(पाटा) परिचालन के प्रतिशत रूप में	-0.11%				1.05%						

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 26th June, 2020

**No.TAMP/11/2020-VSPL.**—This Authority, in exercise of the powers conferred on it under Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), had disposed of the proposal received from the Vizag Seaport

Private Limited (VSPL) for general revision of its Scale of Rates for the vessels handled by it at berths EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust, in the Meeting of this Authority held on 1 June 2020. However, considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the Scale of Rates, approved by this Authority, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately. Accordingly, the revised Scale of Rates approved by this Authority on 1 June 2020 was notified in the Gazette of India on 18 June 2020 vide Gazette No.212. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the VSPL for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No.TAMP/11/2020-VSPL**

**Vizag Seaport Private Limited**

- - -

**Applicant**

**QUORUM:**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 1<sup>st</sup> day of June 2020)

This case relates to the proposal dated 30 January 2020 forwarded by the Vizag Seaport Private Limited (VSPL) vide its e-mails dated 31 January 2020 and 11 February 2020 for general revision of its SOR for the vessels handled by it at berths EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2.1. The existing SOR of VSPL was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/19/2017-VSPL dated 19 January 2018 which was notified in the Gazette of India on 26 February 2018 vide Gazette No.78. In the said tariff Order dated 19 January 2018, based on the deficit reflected in the cost statement, Shore handling charges were increased from `45 per tonne to `65 per tonne (44% increase), BMHS charges were decreased from `150 per tonne to `140 per tonne (7% increase), Railway siding charges were deleted, Dust suppression system charge was increased from `1.50 per tonne to `2.00 per tonne (33% increase), Wharfage charges were increased in range of 5% to 34% as proposed by VSPL and Berth hire charge was increased from 0.0072 US\$ to 0.0083 US\$ (15% increase).

2.2. Subsequently, this Authority had passed an Order No.TAMP/24/2018-VSPL dated 03 October 2018 disposing of the Review Application filed by VSPL which was notified vide Gazette No.413 dated 06 November 2018. The said Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2020. In the said review Order dated 03 October 2018, berth hire charge was revised to US\$ 0.0089 per GRT per hour which was given prospective effect after expiry of 30 days from the date of notification in the Gazette of India.

3.1. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG (Pt.IV) dated 05 March 2019 has issued a Tariff Guidelines for BOT operators operating in all Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed this Authority to act accordingly with immediate effect. The Tariff Guidelines for BOT operators operating in Major Port Trust and previously governed by 2005 Tariff Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 07 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019 after consultation with Major Port Trusts and the BOT operators governed under the erstwhile 2005 Tariff Guidelines.

3.2. As per Clause 4.2 of the Tariff Guidelines, 2019, each BOT Operator shall submit the proposed SOR, 60 days prior to the expected date of implementation of its SOR i.e. by 31 January 2020. In this regard, the VSPL was vide our letter dated 31 January 2020 was requested to file its proposal for General Revision of its Scale of Rates, following Tariff Guidelines, 2019, read with the Working Guidelines issued to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, immediately.

4.1. In this backdrop, the VSPL has filed its proposal dated 31 January 2020 following Tariff Policy, 2019 for fixation of tariff in respect of EQ 8 and EQ 9 berths at VPT for a period of three years from 01 April 2020. The VSPL has submitted the following:

- (i). SOR has been drawn with revenue lower than the ceiling ARR based on our commercial judgment and the Scale of Rates of VPT and other terminals in Vizag.
- (ii). Separate berth hire rates are proposed for EQ 8 berth under mechanized cargo operation and EQ 9 berth under non mechanised operations.



- (iii). In line with the Annual Revenue Requirement (ARR) and considering the SOR of VPT and other berths, increase in tariff is proposed on various cargo related charges as detailed in Form 5.

4.2. The VSPL has furnished detailed computation of ARR under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form-4.

- (i). A summary position of ARR computation furnished by VSPL is tabulated below:

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(1).	<b>Total Expenditure</b> (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	11,438.25	13,641.12	14,794.00
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	3,124.96	2,511.19	2,187.39
	<b>Total Expenditure 1=(i)+(ii)</b>	<b>14,563.21</b>	<b>16,152.31</b>	<b>16,981.39</b>
(2).	<b>Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP</b>			
(i).	Depreciation	152.03	150.85	143.33
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	(703.37)	(490.69)	(341.20)
	<b>Total of Adjustments 2=(i)+(ii)</b>	<b>(551.34)</b>	<b>(339.84)</b>	<b>(197.87)</b>
(3).	<b>Less Adjustments:</b>			
(i).	Actual Royalty/ Revenue share paid to the port	693.96	791.82	876.35
(ii).	Interest on loans	3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	8.22	80.62	31.03
(iv).	Provision for slow moving inventory	-	-	-
(v).	Other provisions, if any	-	-	-
	<b>Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]</b>	<b>3,777.37</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	<b>Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019</b>	520.00	593.00	656.00
(5).	<b>Total Expenditure after Total Adjustments</b> (5=1+2-3)	<b>10,754.50</b>	<b>13,046.88</b>	<b>14,366.92</b>
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1+Y2+Y3]/3	<b>12,722.77</b>		
(7).	<b>Capital Employed</b>			
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)			34,749.18
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			6.73
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			2,398.28
	(a). Inventory			-
	(b). Sundry Debtors			-

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
	(c). Cash			-
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			-
	<b>(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]</b>			<b>37,154.20</b>
(8).	<b>Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)</b>			5,944.67
(9).	<b>Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+(8)]</b>			18,667.44
(10).	<b>Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 3.45% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345)</b>			<b>19,311.47</b>
(11).	<b>Ceiling Indexed ARR as given in Sr.No.10 above</b>			<b>19,311.47</b>
(12).	<b>Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above</b>			<b>17,263.00</b>

- (ii). The VSPL has furnished the working of revenue estimation for the existing tariff as well as the proposed tariff in Form 4 for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed level of tariff is `17,163/- lakhs.

4.3. The VSPL has also furnished Form Nos.1, 2, 3, 4, 6A, 6B and 7 duly certified by the practicing Chartered Accountant.

4.4. The VSPL has vide e-mail dated 11 February 2020 furnished proposed SOR along with copy each of the Audited Annual Accounts for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

4.5. The VSPL has proposed increase/ (decrease) to meet the estimated ARR as given below:

Descriptions	% Increase / Decrease	
	Foreign	Coastal
Berth Hire Charges	Upto 11.24%	62.88% to 80%
Wharfage charges	0.33% to 90%	-53.95% to 166.67%
Demurrage Charges	Status quo	
Stevedoring Charges	0% to 132.56%	-13.60% to 125%
Shore Handling Charges	24.62%	
100T HMC	Status quo	
Charges for hire of Gantry unloader	Deleted	
Charges for railway maintenance and siding charges	Re-introduced	
Storage charges	33% to 50%	
Dust suppression system charges	50% to 100%	
Weighment Charges	20% to 66.67%	
Material Handling System for handling bulk cargo	7.21%	
Tarpaulin coverage charges	20%	

<b>Miscellaneous charges</b>	
Visitors / vehicles entry pass	Status quo
Photography	400%

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy each of the proposal dated 31 January 2020 and 11 February 2020 along with all enclosures (excluding the Audited Annual Accounts) was forwarded to the VPT and concerned users/ user organisations seeking their comments. We have received comments only from M/s.Steel Authority of India Limited (SAIL) a copy of which was forwarded to VSPL as feedback information. The VSPL has furnished its response.

6. A joint hearing in this case was held on 26 February 2020 at the VPT premises. The VSPL made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the VSPL, VPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

7. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the VSPL was requested vide our letter dated 3 March 2020 to furnish additional information/ clarifications on a few points by 10 March 2020. The VSPL vide its e-mail dated 12 March 2020, subsequent e-mails dated 16 March 2020 and 6 April 2020 has furnished its reply. A summary of the additional information/ clarifications sought by us and the corresponding replies furnished by the VSPL is tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarifications sought by us	Reply furnished by VSPL																																																				
1.	<b><u>Annual Revenue Requirement (ARR) (Form-1):</u></b>																																																					
(i).	<p><b><u>Form-1, Sr. No.1, Total Expenditure:</u></b></p> <p>The total expenditure figures match with Audited Annual Accounts of the years 2016-17 to 2018-19. However, the individual figures viz., Operating Expenditure (including depreciation) and Finance and Miscellaneous Expenses do not match with respective figures as per Audited Annual Accounts. The VSPL to consider these figures as per Audited Annual Accounts. There is minor mismatch in total expenditure for the years 2016-17 and 2018-19 from the figures reported in the Audited Annual Accounts of the said years which may also be corrected.</p>	<p>Below is a reconciliation between audited financials and Tariff form No.1:</p> <table> <tr> <th>As per Audited financials:</th> <th>2016-17</th> <th>2017-18</th> <th>2018-19</th> </tr> <tr> <td>Operating Expenditure</td> <td>8,640.43</td> <td>10,539.09</td> <td>11,511.79</td> </tr> <tr> <td>This includes.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Purchase of traded goods</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Changes in Inventory of traded goods</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Operating expenses</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Employee benefit expenditure</td> <td>612.74</td> <td>729.93</td> <td>908.58</td> </tr> <tr> <td>Finance Costs</td> <td>3,124.96</td> <td>2,511.19</td> <td>2,568.52</td> </tr> <tr> <td>Depreciation and Amortization</td> <td>1,411.41</td> <td>1,466.20</td> <td>1,458.61</td> </tr> <tr> <td>Other Expenditure</td> <td>773.69</td> <td>905.90</td> <td>533.85</td> </tr> <tr> <td><b>Total Expenditure</b></td> <td>14,563.23</td> <td>16,152.31</td> <td>16,981.35</td> </tr> <tr> <td><b>As per Forms:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Operating expenses (including depreciation)</td> <td>11,438.25</td> <td>13,641.12</td> <td>14,794.00</td> </tr> </table>	As per Audited financials:	2016-17	2017-18	2018-19	Operating Expenditure	8,640.43	10,539.09	11,511.79	This includes.				1. Purchase of traded goods				2. Changes in Inventory of traded goods				3. Operating expenses				Employee benefit expenditure	612.74	729.93	908.58	Finance Costs	3,124.96	2,511.19	2,568.52	Depreciation and Amortization	1,411.41	1,466.20	1,458.61	Other Expenditure	773.69	905.90	533.85	<b>Total Expenditure</b>	14,563.23	16,152.31	16,981.35	<b>As per Forms:</b>				Operating expenses (including depreciation)	11,438.25	13,641.12	14,794.00
As per Audited financials:	2016-17	2017-18	2018-19																																																			
Operating Expenditure	8,640.43	10,539.09	11,511.79																																																			
This includes.																																																						
1. Purchase of traded goods																																																						
2. Changes in Inventory of traded goods																																																						
3. Operating expenses																																																						
Employee benefit expenditure	612.74	729.93	908.58																																																			
Finance Costs	3,124.96	2,511.19	2,568.52																																																			
Depreciation and Amortization	1,411.41	1,466.20	1,458.61																																																			
Other Expenditure	773.69	905.90	533.85																																																			
<b>Total Expenditure</b>	14,563.23	16,152.31	16,981.35																																																			
<b>As per Forms:</b>																																																						
Operating expenses (including depreciation)	11,438.25	13,641.12	14,794.00																																																			

		<table><tr><td>Finance and Miscellaneous Expenses (FME)</td><td>3,124.96</td><td>2,511.19</td><td>2,187.39</td></tr><tr><td><b>Total Expenditure</b></td><td>14,563.21</td><td>16,152.31</td><td>16,981.39</td></tr><tr><td><b>Difference</b></td><td><b>0.02</b></td><td><b>0.00</b></td><td><b>(0.04)</b></td></tr></table> <p>There is a minor mismatch due to casting of balance sheet prepared in lakhs. Difference of ₹2 thousand and ₹4 thousand respectively in 2016-17 and 2018-19 is adjusted in revised forms.</p>	Finance and Miscellaneous Expenses (FME)	3,124.96	2,511.19	2,187.39	<b>Total Expenditure</b>	14,563.21	16,152.31	16,981.39	<b>Difference</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.04)</b>
Finance and Miscellaneous Expenses (FME)	3,124.96	2,511.19	2,187.39											
<b>Total Expenditure</b>	14,563.21	16,152.31	16,981.39											
<b>Difference</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.04)</b>											
(ii).	As per Clause 2.3.2 of Tariff Guidelines, 2019 in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP, then necessary adjustments need to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. In this regard, Form 6A, furnished by the VSPL at Sr. No.2 shows adjustments under the head “Other Expenses” towards replacement cost, cost of development, other finance charges, gratuity, lease rental and loss on sale of asset from IND AS to IGAAP for the years 2016-17 to 2018-19 respectively by way of showing as exclusion from the ARR computation. In this regard, the VSPL to clarify the following:													
	(a). The VSPL to briefly explain the treatment given under IND AS for the items which are considered for exclusion while drawing the statement under IGAAP.	<p>Summary of IND AS Impact given in VSPL financial Statements:</p> <p>1. Replacement Cost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The Company has applied IND AS 11 (Appendix A-Service Concession Arrangements) on the date of transition which is being carried forward in subsequent years.</li><li>• The Net present value of decommissioning cost to be incurred at the end of Service concession agreement is added to Intangible Assets.</li><li>• Interest on the above NPV is shown as Finance Cost in the year 2018-19 (Refer Note no.21 in Signed Financial Statements) and in the year 2016-17 and 2017-18 the same is shown as provision for replacement cost in Other Expenses (Refer Note no. 23 in 2017-18 and Note no. 4.23 in 2016-17 in Signed Financial Statements).</li></ul> <p>2. Cost of Development:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As per Appendix A- Service Concession Arrangement construction or upgradation revenue is recognised during the service concession period based on the stage of completion of the work performed.</li><li>• Thus, the cost of construction including margin is capitalised to Intangibles as Right to use as per Service Concession Arrangement and the same is</li></ul>												

	<p>routed through Profit and Loss account.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Thus, there is Construction Cost and corresponding Construction Revenue accounted in Profit and loss account. Therefore Construction Cost is reduced from total expenses as IND AS adjustment.</li><li>• Refer Explanatory Note no.4.18 and 4.20 for the FY 2017, Note no. 15(e) and 19 for the FY 2018.</li></ul> <p>3. Other finance Charges:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• As per IND AS 109, the Processing Charges paid for borrowings needs to be amortised over period of loan. Thus on the date of transition borrowing cost which was debited to Profit and Loss in previous periods were reversed and netted off with borrowings in the financial statements. After the transition date, based on the working, portion of processing charges is debited to PL account which is reversed as IND AS adjustment in the form.</li></ul> <p>4. Gratuity:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actuarial gains and losses are recognized in other comprehensive income and not reclassified to profit and loss in a subsequent period as per Ind AS 19.</li><li>• Therefore, any gain/ loss is not debited to Employee cost, same is directly taken to Other Comprehensive Income in Statement of changes in equity.</li></ul> <p>5. Lease Rental Expenditure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fair valuation of interest free security deposits is accounted on transition date and the difference between the carrying value and NPV is taken to Prepaid Deposit which is amortised over the period of the lease agreement.</li></ul> <p>6. Depreciation as per IND AS;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• On application of Appendix A of IND AS 11, the Company has recognised intangible asset arising from a Service Concession Arrangement (SCA) to the extent the Company has a right to charge for use of the concession infrastructure over the period of SCA. Therefore, amortisation/ depreciation was computed retrospective and the effects was given as on transition date and in subsequent periods.</li></ul> <p>7. Loss on Sale of Asset;</p> <p>Sale of assets forming part of Intangible Asset is credited to the block and no gain/ loss is accounted in IND AS.</p>								
(b). The lease rental reported in the Annual Accounts is `478.88 lakhs, `251.55 lakhs and `544.00 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. As against that, the VSPL has in Form 6 A shown the IND AS figure of lease rent at `3.27 lakhs, `3.27 lakhs and `5.46 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively which do not match with	<p>Lease rental expenses includes Fair Valuation of Security Deposit for WAB and VPT. The said adjustment is the IND AS figure of `3.27 lakhs for 2016-17, 2017-18 and 5.46 lakhs for 2018-19 is taken in Form 6A and the whole expenditure of lease rental is considered as a part of Operating expenses in Form 1. Effect for ARR calculation is correctly given.</p> <table><tr><td>As per Financials</td><td>2016-17</td><td>2017-18</td><td>2018-19</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	As per Financials	2016-17	2017-18	2018-19				
As per Financials	2016-17	2017-18	2018-19						

	figures reported in the Audited Annual Accounts. This figure appears to be the adjustment figures. The VSPL to furnish as per the format the figures as per IGAAP, IND AS figures duly matching with the Audited Accounts and the differential which need to be captured as adjustment in Form 1.	<table><tr><td>Lease Rental Expenses – IND AS</td><td></td><td>3.26</td><td>3.26</td><td>5.46</td></tr><tr><td>Lease Rentals – VPT Others</td><td></td><td>5.85</td><td>11.74</td><td>8.65</td></tr><tr><td>Lease Rent to Exim Park</td><td></td><td>258.40</td><td>64.90</td><td>68.79</td></tr><tr><td>Lease Rent to VPT</td><td></td><td>195.23</td><td>166.12</td><td>437.83</td></tr><tr><td>Lease Rent to WAB Plot</td><td></td><td>16.14</td><td>5.52</td><td>23.28</td></tr><tr><td></td><td>(A)</td><td><b>478.88</b></td><td><b>251.55</b></td><td><b>544.00</b></td></tr><tr><td>Less: IND AS Entry</td><td>(B)</td><td>3.26</td><td>3.26</td><td>5.46</td></tr><tr><td><b>Lease Rent expenditure (IGAAP)</b></td><td></td><td><b>475.62</b></td><td><b>248.29</b></td><td><b>538.55</b></td></tr></table>	Lease Rental Expenses – IND AS		3.26	3.26	5.46	Lease Rentals – VPT Others		5.85	11.74	8.65	Lease Rent to Exim Park		258.40	64.90	68.79	Lease Rent to VPT		195.23	166.12	437.83	Lease Rent to WAB Plot		16.14	5.52	23.28		(A)	<b>478.88</b>	<b>251.55</b>	<b>544.00</b>	Less: IND AS Entry	(B)	3.26	3.26	5.46	<b>Lease Rent expenditure (IGAAP)</b>		<b>475.62</b>	<b>248.29</b>	<b>538.55</b>
Lease Rental Expenses – IND AS		3.26	3.26	5.46																																						
Lease Rentals – VPT Others		5.85	11.74	8.65																																						
Lease Rent to Exim Park		258.40	64.90	68.79																																						
Lease Rent to VPT		195.23	166.12	437.83																																						
Lease Rent to WAB Plot		16.14	5.52	23.28																																						
	(A)	<b>478.88</b>	<b>251.55</b>	<b>544.00</b>																																						
Less: IND AS Entry	(B)	3.26	3.26	5.46																																						
<b>Lease Rent expenditure (IGAAP)</b>		<b>475.62</b>	<b>248.29</b>	<b>538.55</b>																																						
	(c). Likewise, the figures of Other Finance expense, Gratuity and Loss on sale of asset in Form 6A under the column IND AS also could not be matched/ correlated with figures reported in the Audited Annual Accounts. The VSPL to, therefore, furnish the figures as per IGAAP, IND AS figures duly matching with the Audited Accounts and the differential as per the format prescribed. The differential need to be captured as adjustment in Form 1.	<div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Other Finance Expenses (under Finance Costs) includes Amortization of Borrowing Cost as per IND AS. Following are the details of borrowing cost shown for last 3 years, which are shown as adjustment in respect of IND AS in Form 1.</li></ul></div><table><tr><td></td><td>2016-17</td><td>2017-18</td><td>2018-19</td></tr><tr><td><b>As per Financials</b></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Finance Cost (*)</td><td><b>3,124.96</b></td><td><b>2,511.19</b></td><td><b>2,187.39</b></td></tr><tr><td>Less: Borrowing cost – IND AS</td><td>2.47</td><td>7.99</td><td>7.61</td></tr><tr><td>Finance Cost as per IGAAP</td><td><b>3,122.49</b></td><td><b>2,503.20</b></td><td><b>2,179.78</b></td></tr></table><p>(*) Excluding Finance Cost related to Obligation under Service Concession Arrangement shown in Note no.21 for the FY 2018-19.</p><div><ul style="list-style-type: none"><li>Gratuity adjustment in Form 6 A represents actuarial gain/ loss which is required to be shown under Other Comprehensive Income as per IND AS – 19 “Employee Benefits” and not to be debited to Employee cost in profit and loss account. The same can be matched from “Other Equity” Note in Statement of Changes in Equity in each Audited accounts for last 3 years. The same can also checked from the disclosure given as per IND AS 19 below Provision notes in all the years. (Refer Note no.4.13 for FY 2017, 13(b) for FY 2018 and 13(b) for FY 2019 in the signed Financial Statements) The said gain/ loss is shown as adjustment in Form 1.</li></ul></div><table><tr><td><b>As per Financials</b></td><td>2016-17</td><td>2017-18</td><td>2018-19</td></tr><tr><td>Gratuity as per Financials</td><td><b>7.64</b></td><td><b>11.17</b></td><td><b>13.34</b></td></tr><tr><td>Less: Re-measurement gain (IND AS) (*)</td><td>4.22</td><td>1.37</td><td>(7.32)</td></tr><tr><td>Gratuity as per IGAAP</td><td><b>3.42</b></td><td><b>9.80</b></td><td><b>20.66</b></td></tr></table><div><ul style="list-style-type: none"><li>Loss on Sale of Asset as per IND AS is Zero, since the sale proceeds is credited to Block of Intangible and Profit and Loss will be accounted once the block is NIL. However, under IGAAP loss would</li></ul></div></div>		2016-17	2017-18	2018-19	<b>As per Financials</b>				Finance Cost (*)	<b>3,124.96</b>	<b>2,511.19</b>	<b>2,187.39</b>	Less: Borrowing cost – IND AS	2.47	7.99	7.61	Finance Cost as per IGAAP	<b>3,122.49</b>	<b>2,503.20</b>	<b>2,179.78</b>	<b>As per Financials</b>	2016-17	2017-18	2018-19	Gratuity as per Financials	<b>7.64</b>	<b>11.17</b>	<b>13.34</b>	Less: Re-measurement gain (IND AS) (*)	4.22	1.37	(7.32)	Gratuity as per IGAAP	<b>3.42</b>	<b>9.80</b>	<b>20.66</b>				
	2016-17	2017-18	2018-19																																							
<b>As per Financials</b>																																										
Finance Cost (*)	<b>3,124.96</b>	<b>2,511.19</b>	<b>2,187.39</b>																																							
Less: Borrowing cost – IND AS	2.47	7.99	7.61																																							
Finance Cost as per IGAAP	<b>3,122.49</b>	<b>2,503.20</b>	<b>2,179.78</b>																																							
<b>As per Financials</b>	2016-17	2017-18	2018-19																																							
Gratuity as per Financials	<b>7.64</b>	<b>11.17</b>	<b>13.34</b>																																							
Less: Re-measurement gain (IND AS) (*)	4.22	1.37	(7.32)																																							
Gratuity as per IGAAP	<b>3.42</b>	<b>9.80</b>	<b>20.66</b>																																							

		be booked and hence ₹45.67 lakhs has been calculated under IGAAP and added to Expenditure for ARR calculation in Form 6A and consequently in Form 1 as well.
(iii).	The figure considered by the VSPL for exclusion under the head interest on loan in Form-1 for the year 2018-19 is ₹2,165.22 lakhs. This does not match with the figures reported in Audited Annual Accounts at ₹2,151.41 lakhs for the year 2018-19. This item of exclusion to be corrected and considered as reported in the Audited Annual Accounts.	Amount of ₹2165.22 lakhs includes interest on short term loans of ₹13.82 lakhs which is grouped under other Finance Cost in Notes to Financial Statements.  Hence, interest of ₹2151.41 lakhs plus ₹13.82 lakhs is ₹2165.22 lakhs which we have shown in Form 1.  No such short term loan interest was there in FY 2016-17 and 2017-18.
(iv).	The VSPL has excluded the provision for bad and doubtful debts of ₹8.22 lakhs, ₹80.62 lakhs and ₹31.03 lakhs in the years 2016-17 to 2018-19 respectively from the total expenses as per clause 2.3 (ii) of the Tariff Guidelines 2019. These figures could not be cross checked with the Audited Annual Accounts. The VSPL to clarify under which head these items are reported in the Audited Annual Accounts.	The figures can be cross checked by referring to Allowance on impairment of trade receivables under the head Other Expenses in each of the Audited Accounts.  TAMP may also refer the movement in expected credit loss allowance shown under Trade receivable schedule in each of the Audited Accounts.  Refer Note No.4.8(ii) in reports for FY 17-18 and 6.1(A) for the FY 2017-18 and 2018-19.
(v).	In the reconciliation statement furnished in Form 6B reconciling the total expenditure as per Audited Annual Account for the years 2016-17 to 2018-19 vis-à-vis the total expenditure considered in Form 1, it is seen that the Total Expenditure in Sl. No.4 in reconciliation statement in Form 6B does not match with the Total Expenditure in Sl. No.5 in Form-1. The Reconciliation Statement to be corrected in the light of the above observation.	VSPL have considered only IND AS entries under this reconciliation (for Expenditure excluded in the ARR computation).  However, as suggested by TAMP, VSPL have considered other expenses also and Revised Reconciliation Statement is furnished.
(vi).	The following to be furnished:	
	(a). Justification for including Traded goods to the extent of ₹144.20 lakhs in the year 2018-19.	This is in line with Matching Principle of matching each revenue item with relevant expenditure.
	(b). Justification for including cargo handling charges outside terminal to the extent of ₹429.25 lakhs, ₹652.62 lakhs and ₹708.52 lakhs for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 respectively.	VSPL was required to handle at least six grades of Coking coal of Sail and for most of the time terminal stockpile area is occupied by Sail's cargo leaving little space for stocking cargos handled at EQ-9. Due to such acute space constraints, there was a challenge of gross under- utilisation of EQ-9 berth for want of storage area at the back up of the EQ-9 berth. Increase in cargo dwell time due to shortage of rakes was a further constraint on storage space inside our terminal. To overcome this, certain volume were handled by giving only delivery at hook point and the Handling agents (Stevedore) shifted the cargo to their plots taken on lease from VPT outside our terminal. However, most of our customers contract require VSPL to offer full shore handling services. Hence in the same way, VSPL had to shift cargos handled at EQ-9 berth to plots of VPT adjacent to our terminal, taken on lease by Stevedore of VPT and incurred expenditure for associated stock management services like Tarpaulin covering, Security, Plot rentals, dust

		suppression etc. on such stevedore's plots. In addition, VPT collects dust suppression charges for such movement of cargos on roads. All such expenditure are accounted under this item which are essential to avoid gross underutilisation of the EQ-9 berth and to achieve the target throughput.
	(c). The VSPL has considered `152.04 lakhs for the year 2017-18 as construction cost. If the construction cost is related to Service Concession Agreement as per IFRIC 12, the said expenditure may be excluded.	The said expenditure is excluded as IND AS Adjustment (Cost of Development as per IND AS) in the year 2017-18. Thus, the same is already excluded in Form 6 B.
	(d). The nature of other finance cost of ₹22.21 lakhs, ₹25.05 lakhs and ₹35.99 lakhs considered for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 to be clarified.	Includes Bank Guarantee Charges, Finance Charges on Car Loan and Amortization of Processing Cost etc.
	(e). It may be clarified why the interest on others to the extent of `27.56 lakhs for the year 2016-17 should be admitted as expenditure.	Interest on others includes interest of `22.67 lakhs paid to VPT on delayed payment of differential royalty as per arbitration award. Remaining `4.89 lakhs on account of payments made to service tax department on availing ineligible input credits.
	(f). Inclusion of Finance cost related to obligation under Service Concession Agreement to be justified.	No finance cost in relation to obligation under SCA is included as allowable expenses. Refer Form 6A which Excludes "Replacement Cost as per IND AS "for all the years as adjustment to total cost.
	(g). Justification for charges for shortfall in committed discharge to the extent of ₹46.30 lakhs in the year 2016-17, the charges being penalty in nature.	Charges for shortfall in committed discharge is not considered as an expenditure for ARR calculation in Form 1. It is shown as operating expense in 2016-17 balance sheet but the same is netted off against revenue as a regrouping in the year 2017-18. Further, it may be noted that the Guidelines prescribe only certain items of expenditure i.e. Royalty, Interest on loans, Provisions for bad debts, slow moving inventory and other provisions only to be adjusted against total expenditure. This item is not covered under any such disallowance.  Further, it is to be noted that it is a compensation for not achieving the contracted discharge rate and most of the times it is due to non-evacuation of cargos of previous vessels on wharf by our clients taking cargo from hook point.
	(h). Justification for provision for replacement cost of ₹276.85 lakhs considered for the year 2016-17.	Provision for Replacement cost has been considered as a part of Other expenses and subsequently removed as an IND AS adjustment to arrive at IGAAP (Refer Form 6A).
(vii).	<u>Form 3 - Computation of Working Capital:</u>  As per Clause 2.6 of Tariff Guidelines, 2019 the norm for computation of working capital is limited to one year's average consumption of inventory for capital spares and other items of inventory at six months' average consumption of stores excluding fuels. Limit on cash balance will be one month's cash expenses. Advance payment of Revenue Share/ royalty and advance payment of	



	<p>lease rental/ license fee to the landlord port flowing from the contractual obligations will be recognised as a part of sundry debtors.</p> <p>In the light of the above provision in the TG 2019, with regard to the computation of Working Capital in Form no.3, the VSPL to clarify/ furnish the following:</p>	
	<p>(a). The VSPL has considered cash at ₹0.024 lakhs in computation of working capital which is not found as per the prescribed norm. Cash expense for working capital computation may be corrected and considered as one month cash expense of the year 2018-19 as per clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. To explain, as the per the cost statement furnished by the VSPL in the original proposal dated 31 January 2020 cash expense works out to ₹1,063.75 lakhs (i.e. admissible expenses ₹14,366.92 lakhs for the year 2018-19 - ₹1,601.94 lakhs depreciation as per IGAAP/ 12 = ₹1,063.75 lakhs). The VSPL to make necessary modification to comply with the Tariff Guidelines.</p>	<p>Based on the formula given by TAMP, average cash expenditure is revised as per the said revised formula provided by TAMP as per the Tariff Guidelines, 2019.</p>
	<p>(b). As regards capital spares, the VSPL has given a figures of `458 lakhs as one year's average consumption of capital spares. However, the VSPL has considered ₹399.96 lakhs as allowable inventory towards capital spares in the computation of working capital at Sr. No. (i). Thus, there is mismatch in these two figures. This may be corrected. The VSPL to indicate under which head this item is captured in the Annual Accounts of the year 2018-19.</p>	<p>One year's average consumption by VSPL is ₹458 lakhs. However, the closing inventory of spares is only to the extent of `399.96 lakhs which is considered for Working Capital working.</p> <p>TAMP may refer Note 9 of the Audited Annual Accounts of March 2019. The head also includes Fuel Stock of ₹8.13 lakhs which is not admissible in Working Capital working as per TG 2019 and hence appropriately excluded by the Company.</p>
	<p>(c). As per the TG 2019 and as per note prescribed under Form-3, advance payment of Revenue Share/ royalty and lease rental/ license fee to landlord port flowing from the contractual obligation will be recognized as part of sundry debtors. As per LA entered by the VSPL with the VPT, the VSPL is not required to make any advance payment of revenue share or the lease rent. Hence, as recorded in the last tariff revision Order none of the items flowing from the License Agreement qualify for consideration as sundry debtors. As against that, the VSPL has considered ₹1,998.30 lakhs in Form-3 which is not in line with Tariff Guidelines, 2019. The VSPL to make necessary corrections in the computation of Working Capital in this item to comply with the guidelines position.</p>	<p>As per Clause No.5.2 of License Agreement, VSPL has entered into lease agreement with VPT for Land lease. As per Lease Agreement rent shall be paid in advance. The VSPL has vide its e-mail dated 16 March 2020 furnished copy of Lease Agreement entered by VSPL with VPT which requires VSPL to make advance payment of lease rental. Accordingly, lease rentals to VPT for terminal and Exim park are shown in revised Tariff form 3. Subsequently, VSPL vide its email dated 16 March 2020 had furnished copies each of lease agreement with VPT for Terminal and Exim park.</p>

(viii).	<p><b>Indexed ARR:</b></p> <p>The VSPL has indexed the estimated ARR of `19,311.47 lakhs arrived based on actuals for the years 2016-17 to 2018-19 by 3.45%. The applicable indexation to be considered is 4.26% for the year 2019-20 instead of 3.45%. The VSPL, therefore, to revise ARR by applying the indexation factor of 4.26% in place of 3.45%.</p>	ARR is revised by applying the indexation factor of 4.26%.																																
(ix).	<p><b><u>Fixed Asset Statement as per IGAAP considered in ARR (Form-7):</u></b></p> <p>As per Audited Annual Accounts, disposals in the year 2018-19 for Plant &amp; Machinery and Vehicles is `808.77 lakhs and ₹10.37 lakhs respectively. As against that, the VSPL has considered ₹1,455.30 lakhs and ₹12.39 lakhs respectively which do not match with the disposal figures reported in the Annual Accounts. The VSPL, therefore, to consider figures of disposal as per Audited Annual Accounts for the year 2018-19. Consequently, necessary correction may also be done in depreciation figures under IGAAP and Return on Capital Employed (ROCE).</p>	<p>On transition to IND AS, VSPL has elected to continue with carrying value of all of its PPE recognised as at 01 October 2014. Accordingly carrying value of Plant and Machinery and Vehicles are shown as disposals in the year 2018-19.</p> <p>As per IGAAP, total value of assets were shown as disposals in Form 7. Loss on sale of asset is shown as item in Form 6B and hence no change is required in tariff forms.</p> <p>Difference in disposal as per IGAAP and Audited Annual Accounts is because the Financial Statements are prepared as per IND AS and hence depreciation on Service Concession Assets differs from the life of Assets under IGAAP.</p> <p>This differences are adequately adjusted as an IND AS Adjustment in Form 6A and 6B by VSPL.</p> <table><tr><td></td><td></td><td><b>Plant &amp; Mach</b></td><td><b>Vehicles</b></td></tr><tr><td>Gross Value</td><td>A</td><td>1,455.30</td><td>12.39</td></tr><tr><td>Carrying value as at 01.10.14</td><td>B</td><td>1,202.68</td><td>10.37</td></tr><tr><td>Depreciation upto 30.09.14</td><td>C</td><td>252.62</td><td>2.02</td></tr><tr><td>Depreciation from 01.10.14 upto disposal</td><td>D</td><td>348.23</td><td>6.47</td></tr><tr><td>Total Depreciation</td><td>C+D</td><td>600.85</td><td>8.49</td></tr><tr><td>Sale proceeds</td><td>E</td><td>808.77</td><td>5.26</td></tr><tr><td>Loss on sale of Asset</td><td>A-(C+D)-E</td><td>45.68</td><td>(1.36)</td></tr></table>			<b>Plant &amp; Mach</b>	<b>Vehicles</b>	Gross Value	A	1,455.30	12.39	Carrying value as at 01.10.14	B	1,202.68	10.37	Depreciation upto 30.09.14	C	252.62	2.02	Depreciation from 01.10.14 upto disposal	D	348.23	6.47	Total Depreciation	C+D	600.85	8.49	Sale proceeds	E	808.77	5.26	Loss on sale of Asset	A-(C+D)-E	45.68	(1.36)
		<b>Plant &amp; Mach</b>	<b>Vehicles</b>																															
Gross Value	A	1,455.30	12.39																															
Carrying value as at 01.10.14	B	1,202.68	10.37																															
Depreciation upto 30.09.14	C	252.62	2.02																															
Depreciation from 01.10.14 upto disposal	D	348.23	6.47																															
Total Depreciation	C+D	600.85	8.49																															
Sale proceeds	E	808.77	5.26																															
Loss on sale of Asset	A-(C+D)-E	45.68	(1.36)																															
2.	<p><b><u>Revenue estimation (Form-4):</u></b></p> <p>As regards estimation of revenue, the following points are observed:</p>																																	
(i).	<p><b><u>Wharfage Charges and Stevedoring charges:</u></b></p> <p>Revenue from wharfage charges and stevedoring charges are estimated only for a few cargo item viz. Coal, Fertilisers, Steam Coal, Pet Coke, Gypsum, Iron Ore, Manganese Ore and others. For all other cargo items for which tariff are proposed, the VSPL has not estimated any revenue from wharfage charges and stevedoring charges. Further, for the cargo items for which wharfage and stevedoring revenue are estimated, it is observed that it is only for foreign cargo and not for coastal</p>	<p>Below are the cargo-wise details of average quantity handled by VSPL for the last 3 years. Accordingly, revenues are estimated for cargo items in the ARR. For all other cargo items for which tariff are proposed, VSPL shall be in a position to handle whenever customers approach to handle these cargoes through our terminal.</p> <p>No coastal cargos are envisaged on the basis of last three years' experience and same will be handled as per extant policies on rates and terms applicable for Coastal cargos.</p> <table><tr><td><b>Description</b></td><td><b>Average per annum [Lakh MT]</b></td><td><b>% Cargo</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<b>Description</b>	<b>Average per annum [Lakh MT]</b>	<b>% Cargo</b>																													
<b>Description</b>	<b>Average per annum [Lakh MT]</b>	<b>% Cargo</b>																																

	cargo.	<table> <tr> <td>Coking Coal</td><td>28.74</td><td>42.00</td></tr> <tr> <td>Steam Coal</td><td>15.28</td><td>22.33</td></tr> <tr> <td>Gypsum</td><td>6.20</td><td>9.06</td></tr> <tr> <td>Lime Stone</td><td>2.70</td><td>3.94</td></tr> <tr> <td>Manganese Ore</td><td>1.71</td><td>2.50</td></tr> <tr> <td>Iron Ore</td><td>3.91</td><td>5.71</td></tr> <tr> <td>Pet Coke</td><td>7.10</td><td>10.37</td></tr> <tr> <td>Fertilisers</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Bauxite</td><td>2.29</td><td>3.34</td></tr> <tr> <td>Others</td><td>0.50</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>-</td><td><b>68.43</b></td><td><b>100.00</b></td></tr> </table>	Coking Coal	28.74	42.00	Steam Coal	15.28	22.33	Gypsum	6.20	9.06	Lime Stone	2.70	3.94	Manganese Ore	1.71	2.50	Iron Ore	3.91	5.71	Pet Coke	7.10	10.37	Fertilisers	-	-	Bauxite	2.29	3.34	Others	0.50	0.74	-	<b>68.43</b>	<b>100.00</b>
Coking Coal	28.74	42.00																																	
Steam Coal	15.28	22.33																																	
Gypsum	6.20	9.06																																	
Lime Stone	2.70	3.94																																	
Manganese Ore	1.71	2.50																																	
Iron Ore	3.91	5.71																																	
Pet Coke	7.10	10.37																																	
Fertilisers	-	-																																	
Bauxite	2.29	3.34																																	
Others	0.50	0.74																																	
-	<b>68.43</b>	<b>100.00</b>																																	
(ii).	Tariff items are prescribed in existing SOR and also included in proposed SOR with revised tariff; but no revenue is estimated by the VSPL in Form-4 for the following tariff items:																																		
	(a). Berth Hire Charges for coastal vessel.	As VSPL has not handled significant coastal vessels during the last 3 years with respect to annual quantities. Hence, income is not envisaged from coastal vessels. VSPL has estimated revenue considering 100% foreign vessels.  If some quantity is estimated for coastal vessels, then revenue shall get reduced by 40% and revenue requirement will increase correspondingly which is not found desirable.																																	
	(b). Penal Berth Hire Charges for over stay of vessels.	VSPL has collected penal berth hire charges in one or two cases only during the last 3 years. Hence, no income is estimated for this tariff.																																	
	(c). Charges for supply of water to vessels.	VSPL has not collected charges for supply of water to vessels during the last 3 years. Hence, income is not envisaged.																																	
	(d). Charges on transshipment cargoes.	Same as above.																																	
	(e). Demurrage charges (imports/ exports/ transshipment).	Same as above.																																	
	(f). Shore operation services for coastal cargo.	Same as above.																																	
	(g). Charges for deployment of Equipment: (i). 104 tonnes HMC for coastal cargo. (ii). Dust suppression system charges (Break bulk). (iii). Weighment charges for 120 tonne electronic Motion Weigh Bridge.	Included under revenue from Shore handling.  (i). Same as above.  (ii). Break bulk not at all handled.  (iii). This is an optional service.																																	
	(h). Charges for other services.	--																																	
(iii).	As regards (i) and (ii) above, the VSPL is requested to confirm that no cargo traffic/ services are rendered by the VSPL for the above items in the year 2018-19 and no revenue was earned during the year 2018-	As VSPL has not handled significant coastal vessels during the last 3 years with respect to annual quantities, income is not envisaged from coastal vessels. Coastal volume is about 6.5%.																																	

	<p>19. If the traffic was not handled by the VSPL in the year 2018-19, the VSPL may consider traffic of the years 2016-17 and/ or 2017-18 as base for revenue estimation for the above items. The VSPL may consider to simplify the Scale of Rates and delete the tariff items for which no traffic is envisaged or services proposed to be rendered by VSPL.</p>	<p>However VSPL has estimated revenue for 100% considering only foreign vessels, which is 40% higher revenue compared to revenue from coastal vessels.</p> <p>Tariff items are proposed if customers do feel to handle these cargoes through our terminal then the same shall be applicable. VSPL being a multi cargo terminal and considering seasonal nature of some cargos, it is felt essential to have the rates fixed.</p>																												
(iv).	<p>It is observed that there is slight mismatch for the following few items as regards the tariff rates considered by the VSPL for estimation of revenue in Form 4 vis-à-vis rates proposed in the draft Scale of Rates:</p> <p style="text-align: center;"><b>₹/ per MT</b></p> <table><tr><th>Sr. No.</th><th>Particulars</th><th>Rates proposed in draft SOR (for foreign cargo)</th><th>Proposed rates considered by VSPL for revenue estimation in Form-4 (for foreign cargo)</th></tr><tr><td>(i).</td><td>Wharfage charges</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(a).</td><td>Pet Coke</td><td>57</td><td>45</td></tr><tr><td>(b).</td><td>Others</td><td>76</td><td>40</td></tr><tr><td>(2).</td><td>Stevedoring charges</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(a).</td><td>Manganese Ore</td><td>40</td><td>36</td></tr><tr><td>(b).</td><td>Others</td><td>60</td><td>40</td></tr></table> <p>The VSPL is requested to make necessary corrections in the revenue estimation in the light of above observation.</p>	Sr. No.	Particulars	Rates proposed in draft SOR (for foreign cargo)	Proposed rates considered by VSPL for revenue estimation in Form-4 (for foreign cargo)	(i).	Wharfage charges			(a).	Pet Coke	57	45	(b).	Others	76	40	(2).	Stevedoring charges			(a).	Manganese Ore	40	36	(b).	Others	60	40	<p>Necessary changes made as suggested.</p>
Sr. No.	Particulars	Rates proposed in draft SOR (for foreign cargo)	Proposed rates considered by VSPL for revenue estimation in Form-4 (for foreign cargo)																											
(i).	Wharfage charges																													
(a).	Pet Coke	57	45																											
(b).	Others	76	40																											
(2).	Stevedoring charges																													
(a).	Manganese Ore	40	36																											
(b).	Others	60	40																											
3.	<b><u>Scale of Rates:</u></b>																													
(i).	<p><b><u>General Terms and Conditions:</u></b></p> <p>The Authority has passed common adoption Orders for all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including VSPL from time to time and all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including VSPL were requested to include suitable notes in the SOR. However, the VSPL has not included suitable notes in the proposed SOR in line with following common adoption Order:</p>																													
	<p>(a). Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25 September 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one</p>	<p>Provisions as per Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated November 26, 2015 for System for classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC) and Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate has been incorporated in revised SOR.</p>																												

	Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance.	
	<p>(b). The Authority had passed the Order No.TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 as common Order incorporating a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat for a period of two years as per the common adoption Order by all Major Port Trusts and BOT terminals thereat shall be applicable in case of VSPL also.</p> <p>The VSPL to incorporate the provisions in the SOR stipulated in these common Orders.</p>	Provision for Mandatory User Charges (MUC) as per Order No.TAMP/12/2019-MUC is specifically for containers. VSPL is not handling any container cargo, hence the same is not applicable.
(ii).	<p>The VSPL has proposed following new tariff items:</p> <p>(a). Wharfage charges for Bauxite.</p> <p>(b). Stevedoring Charges for Bauxite and Manganese Ore.</p> <p>The basis for the proposed new tariff items may be explained. The Revenue estimate does not capture, revenue from these new tariff items. The VSPL to include probable revenue estimate for these new items even if no revenue would have been earned during the year 2018-19.</p>	As VSPL has handled average quantity of 2.29 Lakh MT Bauxite cargo during the last 3 years, which is equivalent to 3.34% of total cargo handled, a separate wharfage and Stevedoring rates are proposed to avoid ambiguity in future on levy of said charges. Proposed stevedoring rates for Bauxite and Manganese ore are in line with bulk cargo like cement clinker. However, without bauxite, our volume has been projected 99.5% on commodity wise. We may handle bauxite under remaining 0.5% and hence no projection is given.
(iii).	<p>During the last revision the VSPL had proposed for deletion of railway siding, administration and maintenance charges stating that this tariff item is not being collected by the VSPL. The VSPL has now proposed a re-introduce this tariff item under Schedule 4.2 at ₹6/- per tonne towards charges for railway maintenance and siding charges.</p> <p>It is seen that in the tariff Order prior to the last revision i.e. Order No.TAMP/5/2011-VSPL dated 11 October 2011 the tariff approved by the Authority for the railway siding charges was ₹3.20 per tonne which is proposed to be increased to ₹6.00 per tonne. The basis for the revised tariff item may be</p>	<p>A discount rate was proposed during 2010 while introducing the new tariff. Refer Annexure VIII of our covering letter dated 24 August 2011, wherein we have furnished revenue requirement. Considering escalation in expenditure, now we have proposed rate of ₹6 PMT.</p> <p>We have estimated revenue considering 100% for Coal handled through bulk material handling system and 60% for all other cargoes.</p>

	explained. The Revenue estimate does not capture, revenue from these new tariff item. The VSPL may include probable revenue estimate for these new item even if no revenue would have been earned during the year 2018-19.																									
(iv).	<p>Clause 8.2.2 of the Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019 for determination of tariff for BOT operators stipulates that while drawing up the SOR, the BOT operators shall as far as possible do away with ad valorem wharfage rate if any, in its existing SOR and determine specific wharfage rate in these cases taking into consideration special care to be taken for handling this cargo or a market determined tariff.</p> <p>Even during the last tariff revision, the Authority advised VSPL to propose unit rates for electrical goods and machinery on the basis of cost of handling and special care, if any, required to be taken while handling the said cargo. However, the VSPL has proposed wharfage rates on ad-valorem basis for electrical goods and machinery. In this context, the VSPL to propose wharfage rate for electrical goods and machinery based on weight or volume of cargo with reference to cost of handling the relevant cargo instead of proposing ad-valorem rate in line with the advice rendered in the last tariff Order and in compliance with the Working Guidelines.</p>	As informed during the last tariff revision, these two goods are rarest items and not handled generally. Hence cost of handling and other factors to be considered will have to be gained by experience in due course. We therefore request for continuation of ad-valorem rate for the present.																								
(v).	<p>In the existing Scale of Rates, Schedule 2.1.2 prescribes penal berth hire charges for over stayal of vessel beyond berth occupancy as per norms prescribed in clause 2.1.4. Schedule 2.1.4 prescribes commodity-wise per vessel per shift output for import cargo and export cargo separately for about 34 cargo items.</p> <p>In the proposed Scale of Rates, the VSPL has rationalised/ modified the Schedule 2.1.4 and proposed per day output for 5 group of commodities. In this regard, the VSPL to furnish the following clarifications:</p>																									
	(a). The reasons for the proposed modification.	Proposed modification is in line with VPT norms vide Trade Circular No.907 dated 30.06.2018 and Trade 912 dated 09.07.2018 on norms of handling dry bulk cargo and levy of penal charges. (Copy attached)																								
	(b). The basis for arriving at the proposed vessel output in tonnes per day. Also, furnish the actual average per day output for the last three years for each of the five cargo groups.	<p>Following are the actual average per day output for the last three years:</p> <table><tr><th rowspan="2">Cargo</th><th colspan="4">Avg. Discharge Rate</th></tr><tr><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>Avg.</th></tr><tr><td>Coking Coal</td><td>22,720</td><td>23,550</td><td>22,735</td><td>23,002</td></tr><tr><td>Steam Coal</td><td>16,176</td><td>15,636</td><td>14,430</td><td>15,414</td></tr><tr><td>Gypsum</td><td>16,899</td><td>16,694</td><td>12,995</td><td>15,530</td></tr></table>	Cargo	Avg. Discharge Rate				2016-17	2017-18	2018-19	Avg.	Coking Coal	22,720	23,550	22,735	23,002	Steam Coal	16,176	15,636	14,430	15,414	Gypsum	16,899	16,694	12,995	15,530
Cargo	Avg. Discharge Rate																									
	2016-17	2017-18	2018-19	Avg.																						
Coking Coal	22,720	23,550	22,735	23,002																						
Steam Coal	16,176	15,636	14,430	15,414																						
Gypsum	16,899	16,694	12,995	15,530																						

		<table><tr><td>Lime Stone</td><td>12,205</td><td>13,790</td><td>13,446</td><td>13,147</td></tr><tr><td>Manganese Ore</td><td>12,079</td><td>11,976</td><td>5,702</td><td>9,919</td></tr><tr><td>Iron Ore</td><td>16,973</td><td>14,530</td><td>12,535</td><td>14,679</td></tr><tr><td>Pet Coke</td><td>16,447</td><td>13,151</td><td>16,809</td><td>15,469</td></tr><tr><td>Fertilisers</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Bauxite</td><td>13,574</td><td>15,013</td><td>19,301</td><td>15,963</td></tr><tr><td>Others</td><td>4,416</td><td>7,135</td><td>8,891</td><td>6,814</td></tr></table>	Lime Stone	12,205	13,790	13,446	13,147	Manganese Ore	12,079	11,976	5,702	9,919	Iron Ore	16,973	14,530	12,535	14,679	Pet Coke	16,447	13,151	16,809	15,469	Fertilisers	-	-	-	-	Bauxite	13,574	15,013	19,301	15,963	Others	4,416	7,135	8,891	6,814
Lime Stone	12,205	13,790	13,446	13,147																																	
Manganese Ore	12,079	11,976	5,702	9,919																																	
Iron Ore	16,973	14,530	12,535	14,679																																	
Pet Coke	16,447	13,151	16,809	15,469																																	
Fertilisers	-	-	-	-																																	
Bauxite	13,574	15,013	19,301	15,963																																	
Others	4,416	7,135	8,891	6,814																																	
	(c). The VSPL has grouped various cargo item into one group and proposed the tonnes per day. The VSPL to confirm that the handling rate for the commodities grouped together are similar/ same.	VPT had issued Trade Circular No.907 dated 30.06.2018 and Trade 912 dated 09.07.2018 on norms of handling dry bulk cargo and levy of penal charges.  It is confirmed that the handling rates for the commodities grouped together are similar/ same.																																			
	(d). In Form-5, the VSPL has stated that the revised norms proposed are as per the Output per Ship Berth Day (OSBD) norms. The VSPL to elaborate which OSBD norms are adopted and give reference of applicability of those norms to the BOT operators under TG 2019 who were earlier governed by the TG 2005.																																				
(vi).	<p>In the existing Scale of Rates, Schedule 2.1.2 prescribes penal berth hire charges for over stayal of vessel beyond berth occupancy as per norms prescribed in clause 2.1.4. Schedule 2.1.2 (i) prescribes permitted to berth occupancy after completion of cargo operation without attracting penal berth hire charges.</p> <p>In the proposed Scale of Rates, the VSPL has now proposed to reduce permitted period of berth occupancy for stayal after completion of cargo operation from 10 hours to 4 hours for any vessel which requires “Securing” and Food grains vessels requiring fumigation and in all other cases from 7 hours to 4 hours. The VSPL to explain basis and reasons for the proposed modification and confirm, whether the revenue impact of the same is captured in Form 4.</p>	These modifications are proposed based on our past experience and in line with modifications made by VPT. Reduced hours were found sufficient as there were hardly any such case of delay. Hence, revenue too was not considered in the estimate in Form-4.																																			
(vii).	The tariff increase proposed by VSPL for foreign going vessel works out 11.24% increase in berth hire charges for Berth No.EQ-8, 1.12% increase in berth hire for Berth No.EQ-9. However, the increase for coastal vessel works out to 80.03% and 62.88% respectively. Likewise, the increase proposed in penal berth hire charges and charges for supply of water for coastal category is higher than the tariff increase proposed for foreign category. The steep increase in the proposed rates for coastal category arose because the VSPL has arrived at rate for coastal container by restating it with the prevailing exchange rate and then pegging it at 60% thereof which is not in line with	<p>As VSPL has not handled significant coastal vessels during the last 3 years with respect to annual quantities, income is not envisaged from coastal vessels. And hence, no need to change Form 4.</p> <p>Coastal rates are modified in Proposed SOR in line with coastal concession policy of the Government.</p> <p>Effectively coastal rates are not 60% of foreign vessels tariff which is not in spirit of the policy.</p>																																			

	the prevailing applicable coastal concession policy of the Government. The coastal concession policy of the Government is not amended to allow restatement with reference to prevailing exchange rate for coastal cargo/ container handling rate during each general revision. The VSPL, therefore, to examine the proposal and make necessary correction to comply with the coastal concession policy of the Government. Consequently, the revenue estimation in Form 4 may also be modified as per the revised rates to be proposed by the VSPL in the light of the above observation.	
(viii).	It is seen that the wharfage rate and stevedoring charges for Iron ore, Iron ore pellets and Thermal Coal for coastal cargo are proposed applying 60% concession over the rates proposed for the foreign cargo. In this regard, it is relevant to state that as per the coastal concession policy of the MOS, crude including POL products, iron ore and thermal coal are not entitled for coastal concession. In line with the coastal concession policy, coastal wharfage rate and stevedoring for these items should be prescribed at par with foreign rate. Further, in line with the decision of the Authority based on the recent proposal of the NMPT for general revision of the SOR approved by the Authority vide Order No.TAMP/78/2018-NMPT dated 24 July 2019, based on the clarification of the NMPT, it is understood that pet coke is equivalent to Petroleum products. Hence, as per the coastal concession Policy, this cargo is also not entitled for coastal concession. The VSPL, therefore, to make necessary correction in line with the coastal concession policy.	For revenue estimate of coal, both thermal and non-thermal, the Company considered only foreign vessels based on the previous years' experience. Though, in revised SOR, concession for coastal vessels carrying coal other than thermal coal has been proposed as per the tariff policy, there is no need to change the revenue estimates as all the coal are considered for foreign vessels.  In the revised proposed SOR, the VSPL has not proposed Coastal Concession for thermal Coal, Iron Ore, Iron ore pellets and Pet coke.
(ix).	Further, wharfage rate for machinery proposed by VSPL is uniform for both foreign and coastal cargo for this item. This cargo is entitled for coastal concession of 40%. The proposed rate to be corrected to fall in line with the coastal concession policy of the Government and revenue estimate may also be corrected accordingly.	In the revised proposed SOR, the VSPL has proposed coastal concession for Machinery.
4.	<b><u>Past Period Surplus:</u></b>	
(i).	Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that in case of operators who have not approached Courts, the surplus/ deficit upto the period of first tariff fixation under this Guidelines shall be dealt with as per Clause 2.13 of the 2005 Tariff Guidelines as reproduced	Statement showing the actual physical and financial performance vis-à-vis the estimates relied upon in the previous tariff cycle is enclosed. Also enclosed statement on reconciliation of expenditure and income between Audited financials and Forms for the FY 2017-18, 2018-19 and 2019-20 (up to December 2019



	<p>below:</p> <p><i>"The actual physical and financial performance will be reviewed at the end of the prescribed tariff validity period with reference to the projections relied upon at time of fixing the prevailing tariff. If performance variation of more than + or - 20% is observed as compared to the projections, tariff will be adjusted prospectively. While doing so 50% of the benefit/ loss already accrued will be set off while revising the tariff."</i></p> <p>The VSPL, therefore, to furnish the statement showing the actual physical and financial performance vis-à-vis the estimates relied upon in the previous tariff cycle as done in earlier tariff revision exercises under erstwhile Tariff Guidelines, 2005 and make necessary adjustments from the estimated ARR in case there is variation in both physical and financial parameters by +/-20%.</p>	<p>based on limited audit financials). Projections are made for January 2020 to March 2020 based on 9 months actuals up to December 2019. There is no variation in both physical and financial parameters by +/-20% (considering January 2020 to March 2020 also) and there is a deficit of ₹631 lakhs for the tariff cycle. We will update actuals for the period ended 31 March 2020 once audit is completed for records.</p>																																													
(ii).	<p>The Authority during the last tariff revision Order No.TAMP/19/2017-VSPL dated 19 January 2018 in para 16(xv)(c), while estimating repairs and maintenance cost of own HMC has considered approach of VSPL for estimating expenditure i.e. based on 2016-17 actuals with 2% annual escalation and adjusted for the tonnage expected to be handled by VSPL owned HMC. The repairs and maintenance cost as estimated by VSPL towards maintenance of its own HMC was considered and it was stated in the said that the actuals will be reviewed with the estimates, and, if any, advantage is accrued on account of relying the estimates during the next tariff revision, it will be adjusted in the next tariff cycle as per the guidelines.</p> <p>The VSPL, therefore, to furnish the actuals as per the Audited Accounts for the years 2017-18 to 2019-20 as against the estimate of repairs and maintenance cost considered during the last revision for the years 2017-18 to 2019-20 is at ₹1113.43 lakhs, ₹1145.27 lakhs and ₹1178.01 lakhs respectively to comply with the decision on the last tariff Order.</p>	<p>Due to frequent break downs and repairs beyond control and expenditure, VSPL has decommissioned one of its Harbour Mobile Cranes from Nov 2018 onwards. The said crane was sold as scrap Post Dec 2019. There is no significant repair and maintenance expenditure for remaining Harbour Mobile crane as the same is being used sparingly with reduced capacity. Due to the said reasons (Decommission of One Crane and Utilisation of other crane with reduced capacity), quantity handled by own cranes is reduced there by expenditure is also reduced for the last two years. This has resulted to increase in quantity by hired cranes and respective expenditure is increased.</p> <p>Below are the details of actual expenditure with respect to estimated expenditure.</p> <table><tr><th>Repairs and Maintenance</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th></tr><tr><td>Projected</td><td>1,113.44</td><td>1,145.27</td><td>1,178.01</td></tr><tr><td>Actuals</td><td>1,076.64</td><td>1,078.39</td><td>999.35</td></tr><tr><td>Diff</td><td>3.42%</td><td>6.20%</td><td>17.88%</td></tr></table> <p>Also find details of quantities handled by Hired and own cranes</p> <table><tr><th rowspan="2">Year</th><th colspan="2">Qty by Hired crane</th><th colspan="2">Qty by Own cranes</th></tr><tr><th>MT in lakhs</th><th>%</th><th>MT in lakhs</th><th>%</th></tr><tr><td>FY 2017-18</td><td>36.30</td><td>56.81</td><td>27.60</td><td>42.99</td></tr><tr><td>FY 2018-19</td><td>41.32</td><td>69.20</td><td>18.39</td><td>30.80</td></tr><tr><td>FU 2019-20 (Dec)</td><td>36.99</td><td>78.94</td><td>9.87</td><td>21.06</td></tr><tr><td></td><td>114.61</td><td></td><td>55.86</td><td></td></tr></table>	Repairs and Maintenance	2017-18	2018-19	2019-20	Projected	1,113.44	1,145.27	1,178.01	Actuals	1,076.64	1,078.39	999.35	Diff	3.42%	6.20%	17.88%	Year	Qty by Hired crane		Qty by Own cranes		MT in lakhs	%	MT in lakhs	%	FY 2017-18	36.30	56.81	27.60	42.99	FY 2018-19	41.32	69.20	18.39	30.80	FU 2019-20 (Dec)	36.99	78.94	9.87	21.06		114.61		55.86	
Repairs and Maintenance	2017-18	2018-19	2019-20																																												
Projected	1,113.44	1,145.27	1,178.01																																												
Actuals	1,076.64	1,078.39	999.35																																												
Diff	3.42%	6.20%	17.88%																																												
Year	Qty by Hired crane		Qty by Own cranes																																												
	MT in lakhs	%	MT in lakhs	%																																											
FY 2017-18	36.30	56.81	27.60	42.99																																											
FY 2018-19	41.32	69.20	18.39	30.80																																											
FU 2019-20 (Dec)	36.99	78.94	9.87	21.06																																											
	114.61		55.86																																												

		As stated above, no advantage is accrued on account of relying the estimates made during the last tariff cycle and no adjustment is required.																																																																												
(iii).	<p>During the last tariff revision Order No.TAMP/19/2017-VSPL dated 19 January 2018 in para 16(xx), while estimating customs mining charges under the head “other expenses”, the VSPL had estimated ₹90.18 lakhs in the year 2017-18 (For the next two years, this item was escalated by 2% per annum) as against this expense is reported to be nil in the years 2014-15 to 2016-17 as per the break-up of expenses furnished by the VSPL. From the submissions made by VSPL, it appears that these charges are under litigation for the period 2014-15 to 2016-17. The estimate of `90.18 lakhs for the year 2017-18 was considered by the Authority, based on Customs Demand Note dated 22 June 2017 issued to VSPL for the period April 2017 to Sept 2017 at ₹47.13 lakhs. In this regard, in para 16(xx) of the Order, it is stated that if, at the time of next tariff revision while reviewing the estimates with the actuals, it is observed that the estimate allowed under this item is not incurred by VSPL, the expense allowed in the last revision shall be adjusted i.e. nullified in the current revision.</p> <p>The VSPL, therefore, to furnish actual expenses incurred by VSPL for the year 2017-18 towards customs mining charges as per the Audited Annual Accounts.</p>	<p>This matter is still sub judice. VSPL is remitting 50 % of the periodical demand raised by the Customs as per the conditions of the Court order for stay of demand. However, entire expenditure is provided in the books of accounts.</p> <p>Customs manning charges:</p> <table><tr><td></td><td><b>2017-18</b></td><td><b>2018-19</b></td><td><b>2019-20</b></td></tr><tr><td>Projected</td><td>90.17</td><td>91.98</td><td>93.82</td></tr><tr><td>Actuals</td><td>448.10</td><td>106.95</td><td>79.35</td></tr><tr><td><b>Diff</b></td><td><b>396%</b></td><td><b>16.27%</b></td><td><b>- 15.42%</b></td></tr></table> <p>Following are the details of demands received from commissioner of customs and expenditure booked under respective years.</p> <table><tr><td><b>Demands received for</b></td><td><b>Total Amount</b></td><td><b>2017-18</b></td><td><b>2018-19</b></td><td><b>2019-20</b></td></tr><tr><td>Oct 2012 to June 2014</td><td>137.77</td><td>137.77</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>July 2014 to Sep 2017</td><td>263.21</td><td>263.21</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Oct 2017 to March 2018</td><td>47.13</td><td>47.13</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>April to June 2018</td><td>29.86</td><td>-</td><td>29.86</td><td>-</td></tr><tr><td>July to Sep 2018</td><td>25.18</td><td>-</td><td>25.18</td><td>-</td></tr><tr><td>Oct to Dec 2018</td><td>26.21</td><td>-</td><td>26.21</td><td>-</td></tr><tr><td>Jan to March 2019</td><td>25.69</td><td>-</td><td>25.69</td><td>-</td></tr><tr><td>April to June 2019</td><td>26.93</td><td>-</td><td>-</td><td>26.93</td></tr><tr><td>July to Sep 2019</td><td>26.21</td><td>-</td><td>-</td><td>26.21</td></tr><tr><td>Oct to Dec 2019</td><td>26.21</td><td>-</td><td>-</td><td>26.21</td></tr><tr><td></td><td><b>634.39</b></td><td><b>448.10</b></td><td><b>106.95</b></td><td><b>79.35</b></td></tr></table>		<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>	Projected	90.17	91.98	93.82	Actuals	448.10	106.95	79.35	<b>Diff</b>	<b>396%</b>	<b>16.27%</b>	<b>- 15.42%</b>	<b>Demands received for</b>	<b>Total Amount</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>	Oct 2012 to June 2014	137.77	137.77	-	-	July 2014 to Sep 2017	263.21	263.21	-	-	Oct 2017 to March 2018	47.13	47.13	-	-	April to June 2018	29.86	-	29.86	-	July to Sep 2018	25.18	-	25.18	-	Oct to Dec 2018	26.21	-	26.21	-	Jan to March 2019	25.69	-	25.69	-	April to June 2019	26.93	-	-	26.93	July to Sep 2019	26.21	-	-	26.21	Oct to Dec 2019	26.21	-	-	26.21		<b>634.39</b>	<b>448.10</b>	<b>106.95</b>	<b>79.35</b>
	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>																																																																											
Projected	90.17	91.98	93.82																																																																											
Actuals	448.10	106.95	79.35																																																																											
<b>Diff</b>	<b>396%</b>	<b>16.27%</b>	<b>- 15.42%</b>																																																																											
<b>Demands received for</b>	<b>Total Amount</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>																																																																										
Oct 2012 to June 2014	137.77	137.77	-	-																																																																										
July 2014 to Sep 2017	263.21	263.21	-	-																																																																										
Oct 2017 to March 2018	47.13	47.13	-	-																																																																										
April to June 2018	29.86	-	29.86	-																																																																										
July to Sep 2018	25.18	-	25.18	-																																																																										
Oct to Dec 2018	26.21	-	26.21	-																																																																										
Jan to March 2019	25.69	-	25.69	-																																																																										
April to June 2019	26.93	-	-	26.93																																																																										
July to Sep 2019	26.21	-	-	26.21																																																																										
Oct to Dec 2019	26.21	-	-	26.21																																																																										
	<b>634.39</b>	<b>448.10</b>	<b>106.95</b>	<b>79.35</b>																																																																										
5.	<p>As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall agree to abide by this guidelines, by way of a separate Agreement with the concerned Major Port Trust. The VSPL to furnish a copy of the separate Agreement as per the prescribed format forwarded by the MOS vide letter No.PR-14019/20/2009-PG (PT-IV) dated 08 March 2019 to all the Major Port Trusts including the VPT duly signed by the VSPL and the VPT.</p>	<p>We have requested from VPT. VSPL shall submit in due course. However, VSPL have already confirmed to VPT that VSPL accepts to submit its proposal for tariff revision from 1.4.2020 under the Tariff guidelines, 2019 in response to their query. (Copy attached)</p> <p>Subsequently, the VSPL has vide e-mail dated 6 April 2020 furnished a copy of the Agreement signed by the VSPL.</p> <p>[The Agreement is to be signed by VPT also which is yet to be furnished.]</p>																																																																												

8. The VPT was also requested vide our letter dated 3 March 2020 to furnish additional information/ clarifications on a few points by 10 March 2020. The VPT vide its e-mail dated 18 March 2020 has furnished its reply. A summary of the additional information/ clarifications sought by us and the corresponding replies furnished by the VPT are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarifications sought by us	Reply furnished by VPT																							
(i).	Furnish comments on the computation of ARR as furnished by VSPL in its Form-1.	<p>Royalty paid by VSPL for the year 2016-17 to 2018-19 and its admissibility is as under:</p> <table><tr><th></th><th>Royalty paid</th><th>Admissibility</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>₹693.96</td><td>₹519.57</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>₹791.82</td><td>₹592.84</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>₹876.35</td><td>₹656.12</td></tr></table> <p>Escalation factor for 2019-20 is 4.26% but not 3.45% as considered by VSPL at Sl. No.10 of Form-1.</p>		Royalty paid	Admissibility	2016-17	₹693.96	₹519.57	2017-18	₹791.82	₹592.84	2018-19	₹876.35	₹656.12											
	Royalty paid	Admissibility																							
2016-17	₹693.96	₹519.57																							
2017-18	₹791.82	₹592.84																							
2018-19	₹876.35	₹656.12																							
(ii).	<p>In Form-4, the VSPL has indicated the actual traffic for the years 2016-17 to 2018-19 as given below and average traffic at 68,43,271 TEUs for revenue estimation. The VPT to confirm the actual traffic considered by the VSPL for the said years and the average traffic of 68,43,271 TEUs considered by the VSPL in the revenue estimation.</p> <table><tr><th colspan="3">Actual Traffic in TEUs</th><th rowspan="2">Average</th></tr><tr><th>Y1 (2016-17)</th><th>Y2 (2017-18)</th><th>Y3 (2018-19)</th></tr><tr><td>63,24,345</td><td>71,55,969</td><td>70,89,500</td><td>68,43,271</td></tr></table>	Actual Traffic in TEUs			Average	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)	63,24,345	71,55,969	70,89,500	68,43,271	<p>The actual traffic handled (in Metric Tonnes) by VSPL from 2016-17 to 2018-19 is as follows:</p> <table><tr><th></th><th>Traffic</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>6362933</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>7092286</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>7102977</td></tr><tr><td>Total</td><td>20558196</td></tr><tr><td>Average</td><td>6852732</td></tr></table> <p>Also, the average of traffic stated by VSPL works out to 68,56,605 but not 68,43,271.</p>		Traffic	2016-17	6362933	2017-18	7092286	2018-19	7102977	Total	20558196	Average	6852732
Actual Traffic in TEUs			Average																						
Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)																							
63,24,345	71,55,969	70,89,500	68,43,271																						
	Traffic																								
2016-17	6362933																								
2017-18	7092286																								
2018-19	7102977																								
Total	20558196																								
Average	6852732																								
(iii).	Also furnish its comments on the estimation of revenue at the proposed level of tariff as furnished by VSPL in its Form-4.	No comments to offer.																							
(iv).	The Audited Annual Accounts of the VSPL under IND AS reports the lease rental at ₹478.88 lakhs, ₹251.55 lakhs and ₹544.00 lakhs for the years 2016-17 to 2018-19 respectively. As per Clause 2.3.2 of Tariff Guidelines, 2019 in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP, then necessary adjustments need to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. In this regard, the VPT is requested to furnish the actual lease rent paid by VSPL in this regard for the years 2016-17 to 2018-19 and also confirm that it is as per the provisions of the License Agreement.	<p>The actual lease rent paid by VSPL for the years 2016-17 to 2018-19 are as follows:</p> <table><tr><th></th><th>Actual lease rent paid</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>₹493.38 lakhs</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>₹375.43 lakhs</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>₹625.02 lakhs</td></tr></table> <p>The above amounts does not include disputed rentals of ₹25.10 crores.</p>		Actual lease rent paid	2016-17	₹493.38 lakhs	2017-18	₹375.43 lakhs	2018-19	₹625.02 lakhs															
	Actual lease rent paid																								
2016-17	₹493.38 lakhs																								
2017-18	₹375.43 lakhs																								
2018-19	₹625.02 lakhs																								
(v).	As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the BOT operator shall agree to abide by this guidelines, by way of a separate Agreement with the concerned Major Port Trust. The VPT to furnish a copy of the separate Agreement as per the prescribed format forwarded by the MOS	No such separate agreement under Tariff Guidelines, 2019 was entered by VSPL till date.																							

	vide letter No.PR-14019/20/2009-PG (PT-IV) dated 08 March 2019 to all the Major Port Trusts including the VPT duly signed by the VSPL and the VPT.	
--	--	--

9.1. While furnishing the additional information/ clarifications which is brought out earlier paragraph, the VSPL vide its e-mail dated 12 March 2020 has furnished revised proposal comprising revised Form-1 (ARR) and revised Form-4 (Revenue Estimation):

- (i). A summary position of revised ARR computation furnished by VSPL is tabulated below:

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Description		Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(1).	<b>Total Expenditure</b> (As per Audited Annual Accounts)	<b>Note 1</b>			
(i).	Operating expenses (including depreciation)		11,438.27	13,641.12	14,793.96
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)		3,124.96	2,511.19	2,187.39
	<b>Total Expenditure 1=(i)+(ii)</b>		<b>14,563.23</b>	<b>16,152.31</b>	<b>16,981.35</b>
(2).	<b>Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per IND AS (as per Audited Accounts) and IGAAP</b>	<b>Form 6A and Note 2</b>			
(i).	Depreciation		152.03	150.85	143.33
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed		(703.37)	(490.69)	(341.20)
	<b>Total of Adjustments 2=(i)+(ii)</b>		<b>(551.34)</b>	<b>(339.84)</b>	<b>(197.87)</b>
(3).	<b>Less Adjustments:</b>				
(i).	Actual Royalty/ Revenue share paid to the port		693.96	791.82	876.35
(ii).	Interest on loans		3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	Provision for bad and doubtful debts		8.22	80.62	31.03
(iv).	Provision for slow moving inventory		-	-	-
(v).	Other provisions, if any		-	-	-
	<b>Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]</b>		<b>3,777.37</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	<b>Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019</b>	<b>Form 2 and Note 3</b>	519.57	592.84	656.12
(5).	<b>Total Expenditure after Total Adjustments</b> (5=1+2-3)		<b>10,754.09</b>	<b>13,046.72</b>	<b>14,367.00</b>
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [Y1+Y2+Y3]/3				<b>12,722.60</b>
(7).	<b>Capital Employed</b>				
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)				34,749.18
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)				6.73
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019	<b>As per Form 3 &amp; Note 4</b>			1,717.02
	(a). Inventory				-
	(b). Sundry Debtors				-
	(c). Cash				-
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)				-
	<b>(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]</b>				<b>36,472.94</b>
(8).	<b>Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)</b>				5,835.67
(9).	<b>Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable</b> [(6)+(8)]				18,558.27
(10).	<b>Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 4.26% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345)</b>				<b>19,348.86</b>
(11).	<b>Ceiling Indexed ARR as given in Sr.No.10 above</b>				<b>19,348.86</b>
(12).	<b>Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above</b>	<b>As per Form 4 &amp; Note 5</b>			<b>17,356.00</b>

- (ii). The VSPL has furnished the working of revenue estimation for the existing tariff as well as the proposed tariff in Form 4 for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed level of tariff is ₹17,356/- lakhs.

9.2. The VSPL has also furnished Form Nos.1, 2, 3, 4, 6A, 6B and 7 duly certified by the practicing Chartered Accountant.

10. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

11. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The Scale of Rates (SOR) of Vizag Seaport Private Limited (VSPL) was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/19/2017-VSPL dated 19 January 2018, following the Tariff Guidelines of 2005, which stipulated cost plus pricing model and the revised SOR was notified in the Gazette of India on 26 February 2018 vide Gazette No.78. Subsequently, this Authority has passed an Order No.TAMP/24/2018-VSPL dated 03 October 2018 disposing of the Review Application filed by VSPL which was notified on 06 November 2018. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2020.
- (ii). The Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the MOS, the tariff fixation exercise in respect of the VSPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019.

The VSPL has filed its proposal dated 31 January 2020 for general revision of its SOR under the Tariff Guidelines, 2019 and Working Guidelines 2019. The VSPL has furnished the requisite information/ clarification sought by us along with revised Annual Revenue Requirement (ARR), draft SOR and modified estimates of revenue vide its email dated 12 March 2020. The final revised proposal filed by VSPL vide its email dated 12 March 2020 along with submissions made by the VSPL, port and SAIL during the processing of the case are considered in this analysis. The revised cost statements and modified revenue estimates furnished by VSPL are duly certified by a practicing Chartered Accountant.

- (iii). (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess the ARR which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital Employed obtaining as on 31<sup>st</sup> March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.
- (b). The VSPL has assessed the ARR based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2016-17 (Y1), 2017-18 (Y2) and 2018-19 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the VSPL has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation for arriving at the Average annual expenses for the year 2016-17, 2017-18 and 2018-19, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The ARR estimated by the VSPL is found to be in order and hence considered based on clarification furnished during the processing of the case except for few modifications for the reasons explained in the following paragraph.

- (i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, *inter alia*, stipulates that Royalty/ Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator in those cases where the bidding process was finalized before 29 July 2003 tariff computation will be taken into account to the extent of the next highest bidder in the ARR computation.

Accordingly, during the years 2016-17 to 2018-19, Revenue share as reflected in the Audited Annual Accounts of corresponding period to the tune of ₹693.96 lakhs, ₹791.82 lakhs ₹876.35 lakhs respectively are excluded. Since the bidding process in respect of VSPL was finalised before 29 July 2003, revenue share to the extent of the next highest bidder i.e. 12.811% has been considered in the computation of ARR i.e. ₹519.57 lakhs, ₹592.84 lakhs and ₹656.12 lakhs during

the years 2016-17 to 2018-19 respectively. This is in line with the clause 2.2 of the tariff guidelines of 2019.

- (ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, Interest on loans, provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory etc., are to be excluded.

Accordingly, the VSPL has excluded the Interest on loans, to the tune of ₹3075.19 lakhs, ₹2486.14 lakhs and ₹2165.22 lakhs; ₹8.22 lakhs, ₹80.62 lakhs and ₹31.03 lakhs towards provision for bad and doubtful debts during the years 2016-17 to 2018-19 respectively.

The ARR computation by the VSPL captures the interest on others to the extent of ₹27.56 lakhs for the year 2016-17. The VSPL has clarified that the interest on others comprises of ₹22.67 lakhs paid to VPT on delayed payment of differential royalty as per arbitration award and ₹4.89 lakhs is on account of interest payments made to service tax department on availing ineligible input credits. Since both these interest payments by the VSPL are of penal nature are excluded by us from the ARR computation so as not to burden the users for default of the VSPL.

- (iii). Clause 2.3.2 stipulates that in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary adjustments to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. The Audited accounts of VSPL are IND AS compliant. The VSPL has made necessary adjustment in the Depreciation and under the head “Other Expenses” towards replacement cost, cost of development, other finance charges, gratuity, lease rental and loss on sale of asset from IND AS to IGAAP for the years 2016-17 to 2018-19 respectively by way of showing as exclusion from the ARR computation to capture these items as per IGAAP to comply with the Guideline position. Further, the VSPL has explained the adjustments done by it from the audited figures reported under IND AS to IGAAP for the purpose of ARR computation which is brought out in the earlier paragraphs. The VSPL has furnished the requisite working in Form 6A which is duly certified by practicing Chartered Accountant and the same is relied upon.

For the purpose of the analysis, the lease rent for the years 2016-17 to 2018-19 as furnished by the VSPL duly certified by the practicing Chartered Accountant is considered.

- (c). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as discussed above, the VSPL has arrived at average expenses for the years 2016-17 to 2018-19 at ₹127.23 crores. The modified average expense as per our working comes to ₹127.13 crores on account of one modification done in the year 2016-17 as explained above.

- (iv). (a). As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines, 2019 Capital Employed will comprise of Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per norms prescribed. The Audited Annual Accounts for the year 2018-19 reports Gross fixed Tangible Assets of ₹298.65 crores under the IND AS. The VSPL has considered gross fixed assets at ₹347.49 crores as per IGAAP in line with provision prescribed in Clause 2.5 of the Tariff Guidelines, 2019. The VSPL has furnished the prescribed Form 7 giving computation of gross fixed assets as per IGAAP duly certified by practicing Chartered Accountant. The Gross Fixed Assets as on 2018-19 considered by the VSPL as per IGAAP duly certified by the Chartered Accountant is relied upon and considered.

The VSPL has considered capital work-in-progress at ₹6.73 as reflected in the audited Annual Accounts for the year 2018-19.

- (b). Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The norm prescribed for the computation of working capital is limited to one year's average consumption of inventory for capital spares and other items of inventory at six months' average consumption of stores excluding fuels. The VSPL has reported annual consumption of capital spares at ₹458.00 lakhs. However, for computation of working capital, the VSPL has considered the closing inventory of capital spares at ₹399.96 lakhs. This is not in line with the prescribed norm. Therefore,

this item is modified and considered at one year's average consumption of capital spares at ₹458.00 lakhs less Fuel ₹8.13 lakhs i.e. ₹449.87 lakhs.

The cash balance is seen to have been computed as per norms prescribed in clause 2.6 of Tariff Guidelines, 2019.

As per the clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, advance payment of lease rental / license fee to landlord port flowing from the contractual obligations will be recognised as sundry debtor for computation of working capital. The VSPL in its revised proposal has captured ₹253.31 lakhs in the working capital computation being 50% of the advance lease rent paid by it to the VPT in the year 2018-19. The VSPL has clarified that as per Clause No.5.2 of License Agreement dated 28 November 2001, VSPL has entered lease agreement with VPT for lease of Terminal and for land at Exim Park vide agreement dated 29 July 2005 and dated 29 July 2015 respectively. As per both Lease Agreements, the VSPL is required to pay the lease rent in advance every year.

The License fees paid by VSPL to VPT for the year 2018-19 is reported to be ₹506.62 lakhs. 50% thereof comes to ₹253.31 lakhs which is considered by the VSPL in the computation of working capital. This is found to be in line with Guideline position and the general approach followed where there is advance payment of license fee every year.

- (c). Subject to modifications as explained above, the modified capital employed works out to ₹365.23 crores as against total capital employed arrived by VSPL at ₹364.73 crores. Return on Capital Employed (ROCE) considered by VSPL at 16% is ₹58.36 crores. The modified ROCE works out to ₹58.44 crores based on the modified Capital Employed.
  - (v). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2016-17 to 2018-19 plus 16% ROCE. The ARR arrived by VSPL is ₹185.58 crores (₹127.22 crores + ₹58.36 crores). The modified ARR arrived by us works out to ₹185.57 crores (₹127.13 crores + ₹58.44 crores). Further, as per Clause 2.8 of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 which is 4.26%. The indexed ceiled ARR assessed by the VSPL is ₹193.49 crores applying 4.26% indexation. As per the modified ARR computation done by us the modified indexed ceiling ARR works out to ₹193.48 crores for the year 2019-20 (₹185.57 crores \* 1.0426). This does not include of past period adjustment. The analysis relating to the past period is brought out in subsequent paragraphs.
- The final detailed working of ARR calculation furnished by the VSPL which has been duly certified by Chartered Accountant is relied upon. This is subject to minor modification as explained above. The detailed ARR calculation furnished by the VSPL and modified ARR calculation by us are attached as **Annex - I (a) and (b)** respectively.
- (vi). Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulate that in case of the BOT operators who have not gone to the Court against the previous Order of this Authority, the surplus/ deficit for the past period till the period of tariff fixation during the first fixation of Tariff under the Tariff Guidelines of 2019 is to be done as per clause 2.13 of the Tariff Guidelines, 2005.

The estimates considered in the last tariff Order is for the years 2017-18 to 2019-20. Hence, review of the estimates vis-à-vis the actuals need to be done for these three years. The VSPL has furnished Cost Statement for the past period 2017-18 and 2018-19 based on Audited Annual Accounts. The year 2019-20 is still not over and the accounts are not finalized. The VSPL has, therefore, for the year 2019-20 considered actuals for nine months from April 2019 to December 2019 and estimates for three months from January 2020 to March 2020 for comparison purpose of actuals with estimates considered in the last tariff Order for the year 2019-20. The VSPL has furnished reconciliation statement of the expenditure reported in the Audited Annual Accounts for the years 2017-18 and 2018-19 and for the year 2019-20 considered actuals for nine months from April 2019 to December 2019 and the expenditure considered in the cost statement. The year 2019-20 is just now over, however, the Audited Accounts for this year is not available. This Authority, therefore, for the purpose of past period analysis, goes ahead based on the approach followed by the VSPL, subject to review during the fixation of tariff for next tariff cycle based on actuals for 2019-20.

Based on the reconciliation statement furnished by the VSPL, the figures considered by the VSPL in the past period statement are considered in the analysis subject to a few modification as explained in the subsequent paragraphs. The actuals for the year 2019-20 shall, however, be reviewed based on the actuals as per the Audited Annual Accounts for the year 2019-20 during the next tariff revision of the VSPL.

- (vii). The analysis is as given below:

- (a). The actual traffic handled by VSPL during the period from 2017-18 to 2019-20 is 71.16, 70.90 and 71.93 lakh tonnes respectively aggregating to 213.98 lakh tonnes as against the estimated traffic of 62.00, 63.24 and 64.49 lakh tonnes for the corresponding period respectively aggregating to 189.73 lakh tonnes estimated in the tariff Order dated 19 January 2018 as well as review Order dated 03 October 2018.

The VPT has furnished the actual traffic handled by the VSPL at 63.63, 70.92 and 71.03 lakh tonnes and the aggregate traffic at 205.58 lakh tonnes. The traffic figures furnished by the VPT are lower than the actual traffic reported by the VSPL. The difference in traffic figures remains unexplained by VPT. Therefore, for the purpose of this analysis, the actual traffic figures furnished by the VSPL are considered.

The variation in the physical performance is 12.78% positive which is found to be less than +/-20%.

- (b). The income estimates considered in the last tariff Order for the years 2017-18 to 2019-20 are adjusted to capture the effect of tariff increase granted in the tariff Order dated 19 January 2018 as well as review Order dated 03 October 2018 for a like to like comparison with the actual income from the date of implementation of the Order.

The opinion of Attorney General for India conveyed by Ministry of Shipping vide its letter dated 12 June 2015 is that the actual income earned by the operator based on their Audited Accounts should be considered and not any notional income. Therefore, for the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the Audited Annual Accounts for the years 2017-18 and 2018-19 and for the year 2019-20 actuals/ estimates as furnished by the VSPL and supported with reconciliation statements are considered.

It is seen from the reconciliation statement that the VSPL has reduced ₹945.79 lakhs, ₹609.28 lakhs and ₹470.47 lakhs from the actual revenue reported in the Annual Accounts of the years 2017-18 and 2018-19 and the actuals/ estimates of the year 2019-20. This exclusion is towards income received under EPCG and scrap sale from cargo gathered by sweeping internal roads and rake cleaning. Since these income has accrued to the VSPL on account of the terminal, these items are captured under FMI in the cost statement prepared by us.

- (c). The estimates of depreciation in the cost statement prepared during the last revision was based on IGAAP. From the year 2016-17, the VSPL has followed IND AS method of accounting. For a like to like comparison, the VSPL has considered the depreciation figure under IGAAP and has reconciled the same with the IND AS figures. The depreciation figures as considered by the VSPL are relied upon and considered.

- (d). The VSPL has considered lease rent at ₹248.29 lakhs, ₹538.55 lakhs and ₹502.15 lakhs for the years 2017-18 to 2019-20 respectively in the past period cost statement. When the VPT was sought information on the lease rent paid by VSPL, the port has indicated the actual lease rent of ₹375.43 lakhs and ₹625.02 lakhs for the years 2017-18 and 2018-19. The VPT has not furnished the figures for the years 2019-20.

The estimates for the years 2017-18 to 2019-20 considered during the last tariff revision was based on the then accounting method as per IGAAP followed by the VSPL. The VSPL has furnished reconciliation of the lease rent reported in the Annual Accounts under IND AS to IGAAP figures considered in the cost statement for the past period for the years 2017-18 and 2018-19 respectively and the adjustment done in this regard is duly certified by the practicing Chartered Accountant in Form 7 and hence the same is considered.

- (e). It is seen from the reconciliation statement that the VSPL has not excluded provisions for bad and doubtful debts reported in the Annual Accounts while drawing the past period cost statement for the years 2017-18 and 2018-19. The VSPL has, however, made necessary adjustment in this regard in the ARR computation in Form 1. Hence, in the cost statement for the past period prepared by us, the provisions for bad and doubtful debts reported in the Audited Annual Accounts for the years 2017-18 and 2018-19 are excluded. Apart from the above, the VPT has not made necessary adjustment as regards Gratuity payment from INDAS to IGAAP though it has done necessary adjustment of excluding it in the computation of ARR. Hence, similar adjustment is done in the past period cost statement.



- (f). Further, the VSPL has, on the expenditure side reduced ₹144.19 lakhs toward purchase of scrap inventory. Since the interlinked income from sale of scrap from sweeping of cargo is considered by us under the FMI for the past period, the corresponding nature of expenditure is captured in the cost statement for the past period prepared by us.
- (g). The VSPL has considered admissible Revenue share paid to VPT for each of the years 2016-17 to 2018-19 in line with the Tariff Guidelines, 2005 and Tariff Guidelines, 2019.
- (h). The interest on loans has also been excluded by VSPL for each of the years 2017-18 to 2019-20 in line with the general approach followed by this Authority.
- (i). The Capital employed considered during the last tariff revision under the then applicable Tariff Guidelines of 2005 is Net Fixed Assets + working capital as per the prescribed norms. The Net Fixed Assets reported in the Audited Annual Accounts is based on IND AS. The VSPL has considered capital employed at ₹16,953.29 lakhs, ₹14,965.08 lakhs and ₹13,414.52 lakhs for the years 2017-18 to 2019-20 respectively for the purpose of computing ROCE.

The Net Fixed Assets under IGAAP as furnished by the VSPL duly certified by the practicing Chartered Accountant is ₹18,398.11 lakhs, ₹16,906.02 lakhs and ₹15,281.49 lakhs for the years 2017-18 to 2019-20. The net fixed assets considered by the VSPL in the computation of capital employed for the past period do not match with the Form 7 figures which is duly certified by the Chartered Accountant. Since the net fixed assets under the IGAAP furnished by the VSPL in Form 7 are duly certified by the practicing Chartered Accountant, the same are considered for the years 2017-18 to 2019-20 for the past period.

The working capital is considered as per norms. The Stores and spares consumed is captured in line with the norms prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The cash balance is considered at one month cash expense in line with the guideline position. The current liabilities as reported in the audited annual accounts of the respective years is considered. Subject to the above adjustments, Working Capital works out to negative and hence treated as Nil.

- (j). A copy of the cost statement reviewing estimates of 2017-18 to 2019-20 vis-à-vis actuals of the corresponding period is attached as **Annex - II**.
- (k). A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is tabulated below:

(₹ in crores)

Particulars	Aggregate for the years 2017-18 to 2019-20 in absolute terms		Variation in %
	Estimates as per tariff Order	Actuals	
Traffic (in lakh tonnes)	189.73	213.98	12.78%
Total Operating Income	405.67	485.56	19.69%
Total Expenditure including FME less FMI, Depreciation and overheads	329.67	399.48	21.17%
Surplus/ deficit before Return	76.00	86.08	13.26%
Capital Employed (Average)	158.32	168.62	6.50%
16% Return on Capital Employed	76.00	80.93	6.50%
Net Surplus after ROCE (before adjustment of past surplus)	0.00	5.15	--

- (l). The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period from 2017-18 to 2019-20 are given below:
- (i). The actual aggregate traffic handled by the VSPL is 213.98 lakh tonnes as against the estimated traffic of 189.73 lakh tonnes during the period from 2017-18 to 2019-20. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic handled is 12.78% positive in comparison to the estimates.

- (ii). The operating income earned by the VSPL is `485.56 crores as against estimation of ₹405.67 crores for the corresponding period resulting in positive variance of 19.69%.
- (iii). On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years 2017-18 to 2019-20 is `399.48 crores as against the estimated expenditure of ₹329.67 crores considered in the last Order for the corresponding period. The total actual expenditure thus shows positive variance of 21.17% in comparison to the expenditure estimated in the last tariff Order.
- (iv). The average capital employed for the period from 2017-18 to 2019-20 is ₹168.62 crores as against average estimated capital employed of ₹158.32 crores. The variation in the average capital employed comes to 6.50% negative.
- (v). As per the modified cost statement for the past period prepared by us, the VSPL has earned aggregate surplus of ₹5.15 crores after admissible cost and 16% ROCE for the period from 2017-18 to 2019-20.
- (vi). The average annual return earned on the average capital employed thus works out to 17.02%, as shown in the following table:

(₹ in crores)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	AVG.
Actual Surplus/ deficit before return	30.61	29.41	26.07	86.09 (Total) 28.70 (Avg.)
Actual Capital Employed	183.98	169.06	152.82	168.62 (Avg.)
Actual Return earned on capital employed	16.64%	17.40%	17.06%	17.02%

- (vii). As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of more than +/ (–) 20%, then 50% of such accrued benefit/ loss has to be adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be taken into account for the purpose of clause 2.13. Further, as per the opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20% that shall be shared equally i.e.50:50 between the operator and the users. In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the operator and 40% additional is to be shared with users by considering adjustment in future tariff.

It can be seen from the above analysis that the variation in the physical parameter i.e., actual traffic handled is less than 20% i.e. 12.78% positive and financial performance in terms of return on capital employed is positive but the variation is not more than 20% (20% variation over 16% comes to 19.20%). Since the variation in both the parameters are found to be less than +/(-) 20%, there is no case for adjustment of past period surplus in the current tariff cycle following the opinion of the AG on the interpretation of clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005.

- (m). As stated earlier, since the Audited Accounts for the year 2019-20 is not available at the time of finalizing this case, the comparison of estimates for the year 2019-20 considered in the last tariff Order along with the actuals/ estimates for the year 2019-20 furnished by the VSPL in the current tariff revision exercise and considered in the past period analysis shall be again reviewed with reference to the Audited Accounts for the year 2019-20 at the time of next review. Adjustment, if any, to be done in the future tariff on account of variation shall be governed by the applicable Tariff Guidelines.
- (n). During the last tariff revision Order dated 19 January 2018 in para 16 (xx), while estimating customs manning charges under the head “other expenses”, the VSPL had estimated `90.18 lakhs in the year 2017-18 with 2% escalation in the subsequent years as against nil expense reported in the years 2014-15 to 2016-17. The estimate of ₹90.18

lakhs for the year 2017-18 was considered by this Authority, based on Customs Demand Note dated 22 June 2017 issued to VSPL for the period April 2017 to Sept 2017 and the tariff Order stated that if at the time of next tariff revision while reviewing the estimates with the actuals, it is observed that the estimate allowed under this item is not incurred by VSPL, the expense allowed in the last revision shall be adjusted i.e. nullified in the current revision. The VSPL has furnished the actuals expenditure reported under this item for each of the three years 2017-18 and 2019-20 and clarified that the matter is still subjudice and that the VSPL is remitting 50% of the periodical demand raised by the Customs as per the conditions of the Court order for stay of demand. The expenditure reported by the VSPL for each of the three years 2016-17 to 2019-20 is found to be higher than the level estimated in the last tariff order. That being so, no adjustment is warranted on this account.

- (o). Further, during the last tariff revision Order in para 16(xv)(c), as regards estimation of repairs and maintenance cost of HMC owned by the VSPL it was brought out that the VSPL had not renewed AMC for its own HMC for the year 2016-17. However, in view of unforeseen breakdown, value of spares consumed under AMC in the past years, the expenditure for the past year was taken as the base and 2% annual escalation thereon was considered for estimation of the expenditure for the years 2017-18 to 2019-20 by VSPL. The approach adopted by the VSPL was considered in the said Order and it was stated that the actuals will be reviewed with the estimates, and, if any, advantage is accrued on account of relying the estimates during the next tariff revision, it will be adjusted in the next tariff cycle as per the guidelines.

When sought actuals from the VSPL in this regard, the VSPL has clarified that due to frequent break down and repairs beyond control, the VSPL has decommissioned one of its HMC from November 2018 onwards and sold as scrap post December 2019. Thereby, quantity handled by own cranes is reduced but there has been increase in expenditure of hired cranes. The VSPL has given the details of the estimates vis-à-vis actuals in this regard which is brought out in the earlier paragraphs. The VSPL has categorically stated that no advantage is accrued on account of relying the estimates made during the last tariff cycle and no adjustment is required. Based on the submissions made by the VSPL and also recognizing that the past period analysis, the variation is not found in both the parameters viz. physical and financial more than +/- 20% variation, no adjustment is warranted on this account.

- (viii). As brought out in the preceding paragraphs, the modified indexed ceiling ARR was arrived at ₹193.48 crores for the year 2019-20. As stated in the analysis in the preceding paragraphs there is no case for past period adjustment based on the analysis given in the preceding paragraphs.
- (ix). (a). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic considered by the VSPL for the years 2016-17 to 2018-19 is 68.43 lakh tonnes. The VPT has furnished the actual traffic handled by the VSPL at 63.63, 70.92 and 71.03 lakh tonnes and the average of three years traffic is worked out at 68.53 lakh tonnes. There is slight variation in the average traffic furnished by the VPT by 0.10 lakh tonne. The reason for variation remains unexplained by VPT. For the purpose of this analysis, the average traffic of 68.43 tonnes for the years 2016-17 to 2018-19 considered by the VSPL for revenue estimation is relied upon.

The VSPL has not estimated revenue from coastal vessel/cargos citing that no coastal cargos are envisaged based on last three years experience. The VSPL has not estimated penal berth hire charges. When sought clarification, it has stated that in one or two cases only during the last 3 years it has earned revenue from this item and hence no income is estimated for this tariff.

- (b). Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to determine the rates within the estimated ARR to respond to the market forces based on commercial judgment. The proposal of the VSPL is within the guideline provision.

The tariff increase proposed by the VSPL in the revised proposal is tabulated in the earlier paragraphs and hence not reiterated for the sake of brevity. The VSPL has stated that it is facing stiff competition from stevedores, BOT operators in VPT and neighboring private

ports like Gangavaram. Users go by lowest rates in VPT. That being so, tariff hike in VRC and CRC is proposed after lot of deliberation. VSPL has stated that it has proposed balanced tariff hike for ship and cargo interest keeping in view all the points.

At the proposed tariff, VSPL does not envisage to meet full ARR. The ARR gap left uncovered is to the tune of ₹19.92 crores.

- (c). The existing SOR of VSPL prescribes uniform berth hire charges for berth nos. EQ 8 and EQ 9. In the proposed SOR, separate berth hire charge for EQ8 and EQ9 berths are proposed by the VSPL adopting the approach followed by another BOT operator viz. SWPL in MOPT who also, like the VSPL, has two berths of which one is for conventional and the other is for mechanised handling. The increase proposed in berth hire charges for EQ8 which is a mechanised berth is at 11.24% and for EQ9 berth marginal increase of 1.12% is proposed. The Steel Authority of India Ltd. (SAIL) has pointed out that the proposed increase in berth hire charge by 11.2% will impact them.

The VSPL has clarified that out of the proposed increase of 11.2%, there is escalation factor of 4.26% for the year 2019-20. Balance increase works out to only 6.94% which is proposed so as to meet the estimated annual revenue requirement. The VSPL has justified that even at the proposed berth hire charges, it is still much lower than the berth hire charges at other BOT terminals in VPT, Gangavaram Port as well as SWPL operating in MOPT. Further, benefit of lower turnaround time is enjoyed by users from the mechanized operations at berth no.EQ8.

- (d). The VSPL has stated that increase proposed in wharfage rate and Stevedoring rates is to maintain parity with the rates of VPT and also to meet the estimated ARR. Only for a few cargo items, wharfage rate proposed is higher than the rates prescribed in the SOR of the VPT. No increase is proposed in HMC charge. The VSPL has proposed new tariff items i.e. (a). Wharfage charges for Bauxite and (b). Stevedoring Charges for Bauxite and Manganese Ore. The wharfage rate for bauxite in VPT is ₹50/- per tonne. The wharfage rate proposed by VSPL at ₹40/- per tonne is lower than the wharfage rate at VPT. The stevedoring rates for Bauxite and Manganese ore proposed by the VSPL are stated to be in line with bulk cargo like cement clinker. The VSPL has not estimated any revenue from these items. However, there is revenue gap of ₹19.92 crores left uncovered. Hence, revenue, if any, accrues from these new tariff items it may get subsumed in the revenue gap left uncovered. The tariff proposed for these two new items is, therefore, approved as proposed by the VSPL.
- (e). In the SOR prior to the last revision, the tariff for railway siding, administration and maintenance charges was prescribed at ₹3.20 per tonne. During the last revision, the VSPL had proposed for deletion of this item stating that it is not being collected by the VSPL. The VSPL has now proposed a re-introduce this tariff item under Schedule 4.2 at ₹6/- per tonne towards charges for railway maintenance and siding charges. The SAIL has objected this tariff item stating that, the VPT already levies Terminal Charges for use of sidings within VPT including VSPL sidings. Hence, a separate charge for maintaining the siding should not be passed on to users and it should be within the purview of railway tariff fixation for respective ports.

The VSPL has clarified that the VSPL has constructed railway lines from Anakapalle gate to its berths inside the terminal and it is a notified private siding and as such VSPL incurs recurring expenditure for maintaining the railway sidings and associated administrative expenditure. The VSPL has confirmed this tariff item is different from the siding charges collected by VPT for maintenance of their entire Railway lines. As stated earlier tariff for this item was prevailing in the SOR of VSPL in the pre-revised SOR. Based on the clarification furnished by the VSPL and also recognizing that the revenue estimates captures the revenue from this tariff item, the proposed tariff is, therefore, approved.

- (f). For Shore handling operations, the existing rate of ₹65/- per tonne is proposed to be increased to ₹81/- PMT. The VSPL has explained that shore handling is the highest cost for VSPL. With Environment Pollution Control measures and NCLT, the shore handling cost has increased. Additional cost is incurred to take care of pollution control measures, like covering with tarpaulin, etc. Based on the clarification furnished by the VSPL and

also recognizing that the revenue estimates captures the revenue from this tariff item, the proposed tariff is, therefore, approved.

- (g). At the rates proposed in the revised Scale of Rates, the VSPL has estimated revenue of ₹173.56 crores. The VSPL has given detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2016-17 to 2018-19, as required as per Clause 2.11.1 of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a Chartered Accountant. The revenue estimation furnished by the VSPL is relied upon.
- (x). As per clause 1.9 of the Tariff Guidelines 2019, the BOT operator shall continue to abide by the provisions contained in the existing Concession Agreement entered into with the concerned Major Port Trust. Simultaneously, the *BOT operator* shall agree to abide by this guidelines, by way of a separate Agreement with the concerned Major Port Trust. The VSPL has stated that it has requested the VPT in this regard and shall submit the same in due course of time. However, VSPL have already furnished written confirmation to the VPT that it accepts to submit its proposal for tariff revision from 1.4.2020 under the Tariff Guidelines, 2019. The VSPL has, subsequently, furnished the copy of separate Agreement duly signed by VSPL. However, it is not signed by the VPT. The VSPL is requested to furnish a copy of the separate Agreement as per the prescribed format forwarded by the MOS vide its letter dated 08 March 2019 to all the Major Port Trusts including the VPT duly signed by both the VSPL and the VPT for our records.
- (xi). Based on the above analysis, a summary of the ceiling indexation ARR furnished by the VSPL and as considered by us based on the modified cost statement is given below:

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	ARR computation furnished by the VSPL	ARR computation modified by us
1	Average admissible Expenses for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 $[Y1+Y2+Y3]/3$	127.23	127.13
2	Capital employed as on 31.03.2019 including capital work in progress as on 31.03.2019 and working capital as per norms	364.73	365.23
3	Return on capital employed @ 16%	58.35	58.44
4	ARR as on 31 March 2019 $(4=2+3)$	185.58	185.57
5	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 (4.26% for the year 2019-20)	193.49	193.48
6	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	193.49	193.48
7	Revenue estimated by the IGTPPL at proposed rate	173.56	173.56
8	Revenue gap	19.93	19.92

- (xii). Clause 8.2.2 of the Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019 for determination of tariff for BOT operators stipulates that while drawing up the SOR, the BOT operators shall as far as possible do away with ad valorem wharfage rate if any, in its existing SOR and determine specific wharfage rate in these cases taking into consideration special care to be taken for handling this cargo or a market determined tariff.

The VSPL has continued to proposed wharfage rates on ad-valorem basis for electrical goods and machinery. The VSPL was, during the processing of this case, requested to propose wharfage rate for electrical goods and machinery based on weight or volume of cargo with reference to cost of handling the relevant cargo instead of proposing ad-valorem rate in line with the advice rendered in the last tariff Order and in compliance with the Working Guidelines.

The VSPL has clarified that these two goods are rarest items and not handled generally at the terminal. Hence cost of handling and other factors to be considered will have to be gained by experience. The VSPL has, therefore, requested for continuation of ad-valorem rate for the present. In the current proposal, in the absence of any proposal of VSPL to prescribe wharfage on per unit basis, the wharfage rate for these two cargo items are allowed to be prescribed on ad-valorem rates as proposed by the VSPL. The VSPL is, however, advised to review and explore the possibility of proposing specific wharfage rate on unit basis instead of ad-valorem basis to comply with the provision in the clause 8.2.2 of Working Guidelines during the next revision.

- (xiii). In the existing Scale of Rates, Schedule 2.1.2 prescribes penal berth hire charges for over stayal of vessel beyond berth occupancy calculated as per norms prescribed in the SOR in schedule 2.1.4

wherein commodity-wise per vessel per shift output for import cargo and export cargo are prescribed separately for 37 cargo items. In the proposed Scale of Rates, the VSPL has rationalised/modified the Schedule 2.1.4 and proposed per day output for 6 group of commodities. The VSPL has clarified that the proposed modification is in line with VPT Trade circular dated 09.07.2018 on norms of handling dry bulk cargo. None of the users including SAIL have objected the proposed rationalised norms.

Further, for levy of penal berth hire charge for over stayal of vessel the VSPL has proposed to reduce permitted period of berth occupancy for stayal after completion of cargo operation from 10/7 hours to 4 hours. The VSPL has clarified that the proposed reduction in hours is based on its past experience and in line with modifications made by VPT and that reduced hours are found sufficient as there are hardly any such case of delay. Based on the clarification furnished by the VSPL, the modification proposed by the VSPL in the existing schedule 2.1.2 and 2.1.4 is approved.

- (xiv). It is seen that tariff increase proposed by VSPL for foreign going vessel works out 11.24% for Berth No.EQ-8 and 1.12% increase in berth hire for Berth No. EQ-9. However, the increase for coastal vessel works out to 80.03% and 62.88% respectively. Likewise, the increase proposed in penal berth hire charges and charges for supply of water for coastal category is higher than the tariff increase proposed for foreign category. The steep increase in the proposed rates for coastal category arises because the VSPL has arrived at rate for coastal container by restating it with the prevailing exchange rate and then pegging it at 60% thereof which is not in line with the prevailing applicable coastal concession policy of the Government. The coastal concession policy of the Government is not amended to allow restatement with reference to prevailing exchange rate for coastal cargo/ container handling rate during each general revision. When the VSPL was requested to examine and make necessary correction to comply with the coastal concession policy of the Government and consequently modify the revenue estimation, the VSPL has stated that coastal rates are modified in revised proposed SOR in line with coastal concession policy of the Government. However, it is seen that the VSPL has not made necessary correction in the proposed SOR in respect of rates for coastal vessel for the above items. The coastal vessel rates for the above items i.e. berth hire charge, penal berth hire charge and charges for supply of water are modified in the revised SOR to comply with the coastal concession policy of the Government i.e. the restatement done by the VSPL with reference to prevailing exchange rate is removed and tariff increase proposed for coastal vessel is done at par with the percentage of tariff increase proposed for its foreign counter part. This will not have any impact in the revenue estimation as such because the VSPL has not estimated any revenue from coastal vessel as stated earlier.

- (xv). In the original proposal, the wharfage rate and stevedoring charges for Iron ore, Iron ore pellets and Thermal Coal for coastal cargo are proposed applying 60% concession over the rates proposed for the foreign cargo. In this regard, it is relevant here to state that as per the coastal concession policy of the MOS, crude including POL products, iron ore and thermal coal are not entitled for coastal concession. In line with the coastal concession policy, wharfage rate and stevedoring rate for these items for coastal cargo should be prescribed at par with foreign rate. Further, in line with the decision of this Authority based on the recent proposal of the NMPT for general revision of the SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/78/2018-NMPT dated 24 July 2019, based on the clarification of the NMPT, it is understood that pet coke is equivalent to Petroleum products. Hence, as per the coastal concession Policy, this cargo is also not entitled for coastal concession.

In the revised proposed SOR, the wharfage rate proposed by the VSPL for coastal thermal Coal, Iron Ore, Iron ore pellets and Pet coke is at par with foreign rate which is found to be in order and hence is approved.

However, under stevedoring charges, the VSPL has not made necessary correction for coastal thermal Coal, Iron Ore and Pet coke. Hence in the revised SOR, necessary correction is made by prescribing stevedoring rates for coastal cargo for these items at par with the foreign rate in line with the coastal concession policy of the Government as they are not entitled for coastal concession.

- (xvi). The VSPL has deleted the existing note no.18 dealing with lower charges to utilize services beyond regular hours to encourage exports / importers which was incorporated in pursuance to the MOS letter No.PD/14033/101/2015-PD.V dated 03 February 2016 based on which a common adoption Order No.TAMP/14/2016-Misc. dated 16 February 2016. The existing note no.18 is continued to be prescribed in the revised SOR as it is uniformly prescribed in SOR of all the Major Ports and BOT operators and it is based on common adoption Order.
- (xvii). The existing note relating to storage charges under Section-3.6.2 at beyond the free period is slightly modified by the VSPL. The existing clause regarding levy of storage charges at ₹3/- per

tonne for storage beyond 30 days and upto 45 days in addition to the second fortnight charges is deleted. The VSPL has retained the storage charges beyond 45 days. The proposed modification is approved, as the rationalisation would give relief to the users.

- (xviii). The VSPL has proposed to delete the existing note under Section-4.5 (Material Handling System) for handling bulk cargo relating to levy of composite rate of ₹140/- per tonne if all the items specified in the schedule are provided. The VSPL has stated that customer has to take consolidated services and the VSPL has withdrawn the concession. That being so, the existing note under the schedule is redundant. The proposed deletion is approved.
- (xix). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31 December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30<sup>th</sup> April of the following year. The VSPL has not proposed any note in this regard. In the current revision, the annual indexation of 4.26% pertaining to the year 2019-20 is captured. That being so, they are entitled for annual indexation in the tariff for the year 2020-21 i.e. from 1 May 2020. Since 1 May 2020 has already crossed, VSPL shall be entitled for annual indexation in the SOR approved by this Authority on the day the revised SOR comes into effect. **The annual indexation at 60% for the year 2020-21 announced by this Authority is 1.13% under Tariff Guidelines, 2019. Hence, the revised SOR approved by this Authority needs to be indexed by 1.13% by the VSPL and apply the revised SOR from the date it comes into effect.** The relevant note as regards annual indexation approved in case of other BOT operators is prescribed in the SOR of the VSPL.
- (xx). Clause 4.9 of the Tariff Guidelines, 2019 prescribe tariff validity cycle of three years subject to annual indexation as mentioned in clause 2.12. Therefore, the validity of the revised SOR is prescribed for a period of 3 years from the date of effect of revised SOR subject to annual indexation clause prescribed in the SOR.
- (xxi). Clause 4.8 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that ordinarily the Order approved by this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date the Order is notified in the Gazette. Accordingly, the revised SOR will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette. The existing SOR of VSPL is valid upto 31 March 2019. By the time, the revised SOR comes into effect it may be around beginning of the financial year 2020-21. Hence, existing SOR is deemed to have been extended from the date of expiry till the revised SOR shall come into effect.
- (xxii). It is relevant here to state that the VSPL has filed Writ Petition No.33402 of 2011 challenging the tariff Order of October 2011 in the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh to the extent of reduction effected by this Authority in the tariff of Harbour Mobile Crane (HMC) from ₹72.75 per tonne to ₹36.70 per tonne. The Hon'ble High Court has passed an interim Order on 19 December 2011 permitting the VSPL to charge and collect at ₹72.75 per tonne until further orders. The Hon'ble Court has also directed VSPL that for all such tariffs, levied and collected on HMC after 22.12.2011, the Petitioner shall keep an account of every such transaction and in the event of the Petitioner not succeeding in its Writ Petition, amount collected by VSPL over and above the tariff of ₹36.70 per tonne fixed under the impugned order shall be subject to further orders of the Hon'ble Court. The Writ Petition is yet to be disposed of by the Hon'ble Court.

During the subsequent tariff revision approved by this Authority vide Order No.TAMP/18/2014-VSPL dated 15 May 2015 and Order No.TAMP/19/2017-VSPL dated 19 January 2018, the VSPL for the purpose of past period analysis had considered the actual income from HMC reported in the Annual Accounts for the years 2011-12 to 2013-14 and 2014-15 and 2015-16 upto 7 July 2015 till the revised rate in the Order dated 15 May 2015 came into effect. In view of the specific interim Order of the Hon'ble High Court permitting VSPL to collect the pre-revised rate of ₹72.75 per tonne and also the direction of the Hon'ble High Court to VSPL to keep the separate accounts for the differential revenue collected which is subject to the decision of the Court, the actual revenue from HMC reported in the Annual Accounts for the years 2011-12 to 2013-14 and 2014-15 and 2015-16 upto 7 July 2015 was considered for the purpose of past period analysis as done by VSPL.

The consolidated position as regards revenue collectable by the VSPL for HMC as per the tariff Order dated October 2011 for the period 2011-12 to 2013-14 and 2014-15 and 2015-16 upto 7 July 2015 and the revenue actually collected by the VSPL based on the statement furnished by the VSPL as tabulated in para 16(vi)(d) of Order No.TAMP/19/2017-VSPL dated 19 January 2018 is reproduced below for ease of reference:

Year	Revenue collected by VSPL from hire of HMC in pursuance of the interim Order of the Hon'ble High Court dated 19.12.2011	Revenue collectable for hire of HMC at the rate ₹36.70 per tonne as approved by this Authority in the October 2011 Order	Differential revenue collected by VSPL over and above the rate for HMC approved by this Authority based on the interim Order of the Hon'ble High Court for the period from 19.12.2011 (date of interim Order of Hon'ble High Court) till 09.07.2015 i.e. revised rate approved in May 2015 Order came into effect assessed in the January 2018 Order
2011-12 (from 19.12.2011) (Refer Note A)	22,018,254	17,582,150	4,435,744
2012-13	82,924,841	65,957,810	16,967,031
2013-14	90,609,219	70,753,209	19,856,011
Total – A (as furnished in para 12(iv) (b) of the Order dated 15 May 2015)	<b>195,552,314</b> (Refer Note B)	<b>154,293,529</b>	<b>41,258,786</b>
2014-15	124,291,963	101,128,145	23,163,818
2015-16 (upto 7.7.2015)	24,240,493	19,624,686	4,615,808
Total B	<b>148,532,456</b> Refer Note (C)	<b>120,752,831</b>	<b>27,779,625</b>
Grand Total (A+B)	<b>344,084,770</b>	<b>275,046,359</b>	<b>69,038,411</b>

- (A). *The interim Order of the Hon'ble High Court directed VSPL to keep separate account of differential levy collected after 22.12.2011. VSPL has, however, furnished the details from 19.12.2011 i.e. from the date of the interim Order of the Hon'ble High Court.*
- (B). *The VSPL has reported during processing of May 2015 Order that they are not able to collect ₹ 72.75 permitted by the Hon'ble High Court. The statements furnished by the VSPL shows that VSPL has collected different rates for hire of HMC in the range of ₹ 36.95 per tonne to ₹ 49.50 per tonne.*
- (C). *The statements furnished by the VSPL during the processing of this case shows that VSPL has collected hire charges of HMC in the range of ₹ 38.20 per tonne to ₹ 47.74 per tonne for the period 1 April 2014 till 7 July 2015.*

In the January 2018 Order, this Authority held that the VSPL has assessed the total differential revenue collected by it over and above the tariff approved by this Authority at ₹690.38 lakhs for the period 2011-12 i.e. from 19 December 2011 being the date of the interim Order of the Hon'ble High Court to 7 July 2015. The total differential collection by VSPL is subject to the final decision of the Hon'ble High Court in the Writ Petition filed by VSPL.

As stated earlier, in the past period analysis for the said period, this Authority has considered the income actually collected by the VSPL for the HMC for the reasons stated pending litigation. Thus, as held in the said Order of January 2018, the differential revenue of ₹690.38 lakhs collected by VSPL as assessed is subject to the final decision of the Hon'ble High Court in the Writ Petition filed by VSPL.

It is also relevant here to mention that vide letter No.TAMP/46/2015-Misc dated 24 July 2015 it has been communicated to VSPL that the surplus quantified for the tariff cycle immediately preceding the challenged tariff Order No.TAMP/5/2011-VSPL dated 11 October 2011 and the tariff fixed in the said Order challenged by the VSPL will be taken up for review based on the Ministry of Shipping (MOS) letter No.14019/20/2009-PG dated 12 June 2015, subject to the permission of the Hon'ble High Court, as the matter is subjudice.

Accordingly, steps have been taken to file Affidavit in the Hon'ble Court in August 2015, *inter alia*, praying before the Hon'ble Court to permit this Authority to review the order of October 2011 to give effect to the opinion of the Learned Attorney General of India as directed by the MOS. The matter is still pending before the Hon'ble Court. After receipt of permission of the Hon'ble High Court, an exercise to quantify the surplus/ (deficit) based on the MOS letter has to be undertaken.

- (xxiii). (a). As per the Tariff Guidelines, 2019, the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The VSPL may exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.



- (b). If there is any error apparent on the face of record considered or for any other justifiable reasons, the VSPL may approach this Authority for review of the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.

12.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the revised Scale of Rates of the VSPL is approved which has been notified separately.

12.2. The revised Scale of Rates and conditionalities of the VSPL will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order notifying the revised SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of three years from the date the revised SOR comes into effect. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

12.3. As per clause 7 of the Tariff Guidelines 2019, the VSPL shall furnish to TAMP without fail annual reports on cargo traffic handled and ship berth day output. The annual reports shall be submitted by the VSPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which is required by TAMP shall also be furnished to them from time to time. The VSPL is advised specifically to refrain from withholding requisite information.

12.4. During the next review of Scale of Rates of VSPL, the actual revenue and actual traffic will be compared with the ARR and the traffic relied upon in the immediate previous tariff cycle. If, on such review, variation in both physical and financial parameters is more than +/- 20%, then the surplus/ deficit shall be adjusted in the Annual Revenue Requirement of the next tariff cycle as per clause 3.2.1 of the Tariff Guidelines 2019.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./119/2020-21]

Annex-I (a)

Form - 1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by VSPL.				
Rs. in lakhs				
Sl. No.	Description	2016-17	2017-18	2018-19
(1).	<b>Total Expenditure per Audited Annual Accounts</b> (As			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	11,438.27	13,641.12	14,793.96
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	3,124.96	2,511.19	2,187.39
	<b>Total Expenditure 1=(i)+(ii)</b>	<b>14,563.23</b>	<b>16,152.31</b>	<b>16,981.35</b>
(2).	<b>Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP</b>			
(i).	Depreciation	152.03	150.85	143.33
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	(703.37)	(490.69)	(341.20)
	<b>Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+ -----</b>	<b>(551.34)</b>	<b>(339.84)</b>	<b>(197.87)</b>
(3).	<b>Less Adjustments:</b>			
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	693.96	791.82	876.35
(ii).	Interest on loans	3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	8.22	80.62	31.03
(iv).	Provision for slow moving inventory			
(v).	Other provisions, if any			
	<b>Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)]</b>	<b>3,777.37</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	<b>Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019</b>	519.57	592.84	656.12

(5).	<b>Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2+3)</b>	<b>10,754.09</b>	<b>13,046.72</b>	<b>14,367.00</b>
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [ Y1 + Y2 + Y3 ] / 3			<b>12,722.60</b>
(7).	<b>Capital Employed</b>			
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)			<b>34,749.18</b>
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			<b>6.73</b>
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			
	(a). Inventory			399.96
	(b). Sundry Debtors			253.31
	(c). Cash			1,063.76
	(d). Sum of (a)+(b)+(c )			1,717.02
	<b>(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]</b>			<b>36,472.94</b>
(8).	<b>Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)</b>			<b>5,835.67</b>
(9).	<b>Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [ (6)+ (8) ]</b>			<b>18,558.27</b>
(10).	<b>Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 4.26% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0426)</b>			<b>19,348.86</b>
(11).	<b>Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr. No.10 above.</b>			<b>19,348.86</b>
(12).	<b>Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above</b>			<b>17,356.00</b>

Annex-I (b)

Form - 1

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by VSPL and modified by TAMP				
				Rs. in lakhs
Sl. No.	Description	2016-17	2017-18	2018-19
(1).	<b>Total Expenditure per Audited Annual Accounts) (As</b>			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	11,438.27	13,641.12	14,793.96
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	3,124.96	2,511.19	2,187.39
	<b>Total Expenditure 1=(i)+(ii)</b>	<b>14,563.23</b>	<b>16,152.31</b>	<b>16,981.35</b>
(2).	<b>Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP</b>			
(i).	Depreciation	152.03	150.85	143.33

(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	(703.37)	(490.69)	(341.20)
	<b>Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+ -----</b>	<b>(551.34)</b>	<b>(339.84)</b>	<b>(197.87)</b>
(3).	<b>Less Adjustments:</b>			
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	693.96	791.82	876.35
(ii).	Interest on loans	3,075.19	2,486.14	2,165.22
(iii).	Interest on others	27.56	-	-
(iv).	Provision for bad and doubtful debts	8.22	80.62	31.03
(v).	Provision for slow moving inventory			
(vi).	Other provisions, if any			
	<b>Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]</b>	<b>3,804.93</b>	<b>3,358.59</b>	<b>3,072.60</b>
(4).	<b>Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019</b>	519.57	592.84	656.12
(5).	<b>Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2+3)</b>	<b>10,726.53</b>	<b>13,046.72</b>	<b>14,367.00</b>
(6).	Average Expenses of Sl. No.5 = [ Y1 + Y2 + Y3 ] / 3			<b>12,713.42</b>
(7).	<b>Capital Employed</b>			
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)			<b>34,749.18</b>
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			<b>6.73</b>
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			
	(a). Inventory			449.87
	(b). Sundry Debtors			253.31
	(c). Cash			1,063.76
	(d). Sum of (a)+(b)+(c )			1,766.93
	<b>(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]</b>			<b>36,522.85</b>
(8).	<b>Return on Capital Employed 16% on Sl. No.7(iv)</b>			<b>5,843.66</b>
(9).	<b>Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [ (6)+ (8) ]</b>			<b>18,557.07</b>
(10).	<b>Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 4.26% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0426)</b>			<b>19,347.61</b>
(11).	<b>Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr. No.10 above.</b>			<b>19,347.61</b>
(12).	<b>Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above</b>			<b>17,356.00</b>

Annex-II

## VIZAG SEAPORT PRIVATE LIMITED

(₹ in Lakhs)

Analysis of the Past Period Performance of VSPL for the years 2017-18 to 2019-20 furnished by VSPL and modified by TAMP

Sr. No.	Particulars	Estimates relied upon in the Tariff review Order dated 03.10.2018				Actuals						Variation in Percentage (%)
		2017-18	2018-19	2019-20	Total	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20	2019-20	Total	
								(Upto Dec)	Jan to March	April to March		
	Traffic (in tonnes)	6200000	6324000	6449000	18973000	7115969	7089500	5394679	1798226	7192905	21398375	12.78%
	Capacity (in tonnes)	7700000	7700000	7700000	23100000	7700000	7700000	5775000	1925000	7700000	23100000	
I	Total Operating Income											
	(i) Vessel related income	1414.01	1676.90	1788.97	4,879.88	1984.29	2,467.26	1,824.35	608.12	2432.47	6,884.02	
	(ii) Cargo related income	11482.44	11984.02	12221.01	35,687.47	13168.74	14,179.17	10,743.34	3,581.11	14324.45	41,672.36	
	Total - I	12896.44	13660.91	14009.99	40567.34	15153.03	16,646.43	12,567.69	4,189.23	16756.92	48,556.38	19.69%
II	Operating Costs (excluding depreciation)											
	(i) Operating & Direct labour	467.12	490.86	508.17	1466.15	489.01	481.16	410.29	136.76	547.05	1,517.22	
	(ii) Maintenance labour	569.65	581.04	592.66	1743.36	590.74	678.98	540.62	180.21	720.82	1,990.55	
	(iii) Equipment Running costs	1648.78	1707.38	1768.37	5124.53	1675.66	1,656.98	1,289.26	429.75	1719.02	5,051.66	
	(iv) Maintenance dredging	101.69	103.72	105.79	311.20	142.12	-	-	-	0.00	142.12	
	(v) Royalty / revenue share	469.89	479.29	488.76	1437.94	592.84	656.12	491.27	163.76	655.03	1,903.99	
	(vi) Equipment hire	4080.38	4237.39	4399.31	12717.08	4713.88	5,541.86	4,441.87	1,480.62	5922.50	16,178.24	
	(vii) Lease Rentals payable as per concession agreement	133.24	134.59	135.96	403.80	248.29	538.55	376.61	125.54	502.15	1,288.98	
	(viii) Insurance	70.32	71.72	73.16	215.20	76.95	106.37	84.12	28.04	112.16	295.48	
	(ix) Other expenses	526.40	537.58	548.99	1612.97	1604.16	1621.97	1070.89	356.96	1427.86	4,653.99	
	(x) Technical service fee	12.16	12.16	12.16	36.48	12.16	12.16	9.12	3.04	12.16	36.48	
	Total - II	8079.63	8355.73	8633.33	25068.70	10145.81	11294.15	8714.06	2904.69	11618.74	33,058.70	31.87%
					32967.87						39947.92	21.17%
III	Depreciation	1517.03	1512.57	1488.17	4517.77	1586.32	1571.20	1218.40	406.13	1624.53	4,782.05	5.85%
IV	Overheads											
	(i) Management & Administration overheads	1078.63	1100.70	1123.22	3302.55	1278.96	1,422.87	1,014.02	338.01	1352.02	4,053.86	22.75%
	(ii) Preliminary expenses & upfront payment write-off	33.10	33.10	33.10	99.30	33.10	33.10	24.83	8.28	33.10	99.30	
	Total - IV	1111.74	1133.80	1156.32	3401.86	1312.06	1,455.97	1,038.84	346.28	1385.12	4,153.16	
V	Operating Surplus / (Deficit) (I) – (II) – (III) - (IV)	2188.04	2658.80	2732.16	7579.01	2108.83	2,325.11	1,596.39	532.13	2128.52	6,562.46	-13.41%
VI	Finance & Miscellaneous Income (FMI)											
	(i) Discounted terminal value receivable as per the LA	6.06	6.79	7.61	20.46	6.06	6.79	5.71	1.90	7.61	20.46	
	(ii) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	945.79	609.28	352.85	117.62	470.47	2,025.54	
	Total FMI	6.06	6.79	7.61	20.46	951.85	616.07	358.56	119.52	478.08	2,046.00	
VII	Finance & Miscellaneous Expenses (FME) -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-			-	
											-	
VIII	FMI Less FME (VI) - (VII)	6.06	6.79	7.61	20.46	951.85	616.07	358.56	119.52	478.08	2,046.00	
IX	Surplus Before Interest and Tax (V) + (VIII)	2194.10	2665.59	2739.76	7599.47	3060.68	2,941.18	1,954.95	651.65	2606.60	8,608.46	13.28%
						16.64%	17.40%	17.06%		17.02%	2,869.49	
X	Capital Employed	17369.84	15824.17	14302.90	15832.30	18398.11	16906.02	15281.49		15281.49	16,861.87	6.50%
XI	RoCE - Maximum permissible	2779.17	2531.87	2288.46	7599.51	2943.70	2,704.96	1,833.78	611.26	2445.04	8,093.70	
XII	Capacity Utilization	81%	82%	84%	82%	92%	92%	93%	93%		93%	
XIII	RoCE adjusted for capacity utilization	2779.17	2531.87	2288.46	7599.51	2943.70	2,704.96	1,833.78	611.26	2445.04	8,093.70	6.50%

XIV	Net Surplus / (Deficit) (IX) - (XIII)	(585.07)	133.72	451.30	(0.04)	116.98	236.21	121.17	40.39	161.56	514.76	
XV	Net Surplus / (Deficit) as a % of operating income (XIV/I)	-4.54%	0.98%	3.22%		0.77%	1.42%	0.96%	0.96%	0.96%	1.06%	
XVI	Average Net Surplus/(Deficit) as a % of operating income	-0.11%				1.05%						